रजिस्ट्री सं० डी(डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25, 1976/पौष 4, 1898
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25, 1976/PAUSA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 31st July, 1976 :—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
300.	का० आ० 445 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 1976 S.O. 445(E), dated the 1st July, 1976.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	सीमेंट नियंत्रण (तृतीय संशोधन) आदेश, 1976। *Cement Control (Third Amendment) Order, 1976.*
301.	S.O. 446(E), dated the 1st July, 1976.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs	Corrigenda for pages 1110 to 1113 in Gazette of India No. S.O. 356(E), dt. 19th May, 1976.
302.	का० आ० 447 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 1976 S.O. 447(E), dated the 1st July, 1976.	राजस्व और बैंकिंग विभाग Department of Revenue and Banking.	वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 52-सीमाशुल्क तारीख 6 अप्रैल, 1972 में और संशोधन। Further amendment in the notification of Min. of Fin. No. 52-Customs dt. 6th April, 1972.
303.	का० आ० 448 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976 S.O. 448(E), dated the 2nd July, 1976.	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय Ministry of Education and Social Welfare.	उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित पुरावशेषों का पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण। Registration of antiquities mentioned in the annexed schedule under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972.
304	सा० नि० 449 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976 S.O. 449(E), dated the 2nd July, 1976.	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत हरियाणा में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी 6 मास जो 8-7-76 से सक्रिय ड्यूटी की घोषणा। Declaration of duty as active duty under Border Security Force Act, 1968 for 6 months w.e.f. 8-7-76 in Haryana.

1	2	3	4
	सा० नि० 450 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976	गृह मंत्रालय	सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी 6 मास के लिए जो 8-7-76 से सक्रिय ड्यूटी की घोषणा।
	S.O. 450(E), dated the 2nd July, 1976.	Ministry of Home Affairs	Declaration of duty by every person as active duty under B.S.F. Act, 1968 for 6 months w.e.f. 8-7-76 in Rajasthan.
	सा० नि० 451 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976	—तदैव—	प० बंगाल में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो छः मास 8-7-76 से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 451(E), dated the 2nd July, 1976.	Do.	Declaration of duty by every person serving in W. Bengal as active duty for 6 months w.e.f. 8-7-76.
	सा० नि० 452 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976	—तदैव—	बिहार में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 6 मास 17-7-76 से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 452(E), dated the 2nd July, 1976.	Do.	Declaration of duty by every person serving in Bihar as active duty for 6 months w.e.f. 17-7-76.
	सा० नि० 453 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976	—तदैव—	देहली में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 6 मास 23-7-76 से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 453(E), dated the 2nd July, 1976.	Do.	Declaration of duty by every person serving in Delhi as active duty for 6 months w.e.f. 23-7-76.
	सा० नि० 454 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976	—तदैव—	केरल में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 6 मास 25-7-76 से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 454(E), dated the 2nd July, 1976.	Do.	Declaration of duty by every person serving in Kerala as active duty for 6 months w.e.f. 25-7-76.
	सा० नि० 455 (अ), दिनांक 2 जुलाई, 1976	—तदैव—	मेघालय में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 6 मास 31-7-76 से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 455(E), dated the 2nd July, 1976.	Do.	Declaration of duty by every person serving in Meghalaya as active duty for 6 months w.e.f. 31-7-76.
305.	का० आ० 456(अ),/आ० आ०/लोहा और इस्पात दिनांक 3 जुलाई, 1976	इस्पात और खान मंत्रालय	लोहा और अयस्क (नियंत्रण) आदेश, 1956 सिक्किम में तुरन्त विस्तारित और प्रवृत्त।
	S.O. 456(E)/Ess. Comm./ Iron & Steel dated the 3rd July, 1976.	Ministry of Steel and Mines	Iron & Steel (Control) Order, 1956 shall extend to, and come into force in Sikkim with immediate effect.
306.	का० आ० 457 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 414(अ)/15ए/ आई० डी० आर० ए०/76 तारीख 11 जून, 1976 में संशोधन।
	S.O. 457(E), dated the 5th July, 1976.	Ministry of Industry and Civil Supplies	Amendment in the order of Min. of Ind. & Civil Supplies No. S.O. 414(E), 15A/IDRA/76, dt. 11th June, 1976.
307.	का० आ० 458 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 1976	आय-कर समझौता आयोग	आय-कर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1976।
	S.O. 458(E), dated the 5th July, 1976.	Income-Tax Settlement Commission	Income-tax Settlement Commission (Procedure) Rules, 1976.
	का० आ० 459 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 1976	धन-कर समझौता आयोग	धन-कर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1976।
	S.O. 459(E), dated the 5th July, 1976.	Wealth Tax Settlement Commission	Wealth-tax Settlement Commission (Procedure) Rules, 1976.
308.	का० आ० 460 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 1976	राजस्व और बैंकिंग विभाग	प्रागज्योतिष गाओंलिया बैंक नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की असम में स्थापना, जो गोलपाड़ा, कामरूप और दारांग में अपना कारोबार करेगा।
	S.O. 460(E), dated the 6th July, 1976.	Department of Revenue and Banking	Establishment of a Regional Rural Bank in Assam under the name of Pragjyotish Gaonlia Bank, which shall operate in Goalpara, Kamrup and Darrang.
	का० आ० 461 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 1976	—तदैव—	नलबाड़ी को उस स्थान के रूप में निर्धारित करना जहां पर प्रागज्योतिष गाओंलिया बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।
	S.O. 461(E), dated the 6th July, 1976.	Do.	Nalbari as the place where Pragjyotish Gaonlia Bank shall have its Head Office.

1	2	3	4
	का० आ० 462 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 1976	राजस्व और बैंकिंग विभाग	प्राग्ज्योतिष गाओंलिया बैंक संस्था की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत स्थापना।
	S.O. 462(E), dated the 6th July, 1976.	Department of Revenue and Banking	Pragjyotish Gaonlia Bank, being an institution established under Regional Rural Banks Act, 1976.
	का० आ० 463 (अ), दिनांक, 6 जुलाई, 1976	भारतीय रिजर्व बैंक	प्राग्ज्योतिष गाओंलिया बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में समाविष्ट करना।
	S.O. 463(E), dated the 6th July, 1976.	Reserve Bank of India	Inclusion of Pragjyotish Gaonlia Bank in the 2nd Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934.
309	का० आ० 464 (अ), दिनांक, 6 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) तेइसवां संशोधन आदेश, 1976।
	S.O. 464(E), dated the 6th July, 1976	Ministry of Commerce	Exports (Control) twenty-third Amendment Order, 1976.
310.	का० आ० 465 (अ), दिनांक, 8 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग के राजपत्र का० आ० 61 (अ), दिनांक 31-1-75 की अधिसूचना सं० 56/75-I दिनांक 31-1-75 में संशोधन।
	S.O. 465(E), dated the 8th July, 1976.	Election Commission of India	Amendment in the notification of Election Commission No. 56/75-I dt. 31-1-75 published as S.O. 61(E), dt. 31-1-75.
311.	का० आ० 466 (अ), दिनांक, 9 जुलाई, 1976	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय	प्रो० बी० रामचन्द्र राव की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति।
	S.O. 466(E), dated the 9th July, 1976.	Ministry of Education and Social Welfare.	Appointment of Prof. B. Ramachandra Rao as the Vice-Chairman of the University Grants Commission.
312.	S.O. 467(E), dated the 9th July, 1976	Ministry of Labour	Shri Dharti Dhar Director General to be the Iron Ore Mines Cess Commissioner for the collection and assessment of duty of excise under Labour Welfare Cess Act, 1961.
313.	का० आ० 468 (अ), दिनांक, 9 जुलाई, 1976	श्रम मंत्रालय	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली को समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शिकायतें करने की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत करना।
	S.O. 468(E), dated the 9th July, 1976.	Ministry of Labour	Authorisation to Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi to Sanction the making the complaints under Equal Remuneration Act, 1976.
314.	का० आ० 469 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	श्री ए० के० सेन को भुगतान आयुक्त के रूप में नियुक्ति।
	S.O. 469(E), dated the 9th July, 1976.	Ministry of Commerce	Appointment Shri A. K. Sen as the Commissioner of payments.
315.	का० आ० 470 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 1976	—तदैव—	निर्यात (नियंत्रण) 24वां संशोधन आदेश, 1976।
	S.O. 470(E), dated the 12th July, 1976	Do.	Exports (Control) Twenty-Fourth Amendment Order, 1976.
316.	का० आ० 471 (अ), दिनांक, 12 जुलाई, 1976	—तदैव—	निर्यात (नियंत्रण) 25वां संशोधन आदेश, 1976।
	S.O. 471(E), dated the 12th July, 1976.	Do.	Exports (Control) Twenty-Fifth Amendment Order, 1976.
317.	का० आ० 472 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) 26वां संशोधन आदेश, 1976।
	S.O. 472(E), dated the 13th July, 1976.	Ministry of Commerce	Exports (Control) Twenty-Sixth Amendment Order, 1976.
318.	का० आ० 473 (अ), दिनांक, 15 जुलाई 1976	श्रम मंत्रालय	15 जुलाई 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करना जिस तारीख को समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण के सम्बन्ध में प्रवृत्त होना।
	S.O. 473(E), dated the 15th July, 1976.	Ministry of Labour	Appointment of the day i.e. 15th July, 1976 as the date on which the Equal Remuneration Act, 1976 shall come into force in respect of employments in the manufacture of textiles.
	का० आ० 474 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1976	—तदैव—	वस्त्र और वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण सम्बन्धी नियोजनों के लिए एक या अधिक समितियों का महिलाओं को नियोजित करने के लिए गठन।
	S.O. 474(E), dated the 15th July, 1976.	Do.	Constitution of one or more Advisory Committees regrding the employment of women in the manufacture of textiles and textile products.

1	2	3	4
319.	का० आ० 475 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1976	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	अधिसूचना सं० 419(अ), तारीख 19 जून, 1976 के हिन्दी रूपान्तर में शुद्धि।
	S.O. 475(E), dated the 15th July, 1976.	Ministry of Agriculture and Irrigation.	Corrigenda in the English version of the Notification No. S.O. 419(E), dt. 19th June, 1976.
320.	का० आ० 476 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 1976	लोक सभा सचिवालय	श्री अर्जुन कस्तूरे का लोक सभा से त्याग पत्र।
	S.O. 476(E), dated the 16th July, 1976.	Lok Sabha Secretariat	Resignation of Shri Arjun Shripat Kasture from Lok Sabha.
321.	का० आ० 477 (अ), दिनांक 16 जुलाई 1976	श्रम मंत्रालय	कर्मचारी राज्य बीमा निगम की समिति का गठन।
	S.O. 477(E), dated the 16th July, 1976.	Ministry of Labour	Constitution of a Standing Committee of the Employees State Insurance Corporation.
322.	का० आ० 478 (अ), 18 क/आई डी आर ए/76 दिनांक 16 जुलाई 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 4460/18क/आई० डी० आर० ए० तारीख 14 दिस० 1967 में संशोधन।
	S.O. 478(E), 18A/IDRA/76, dated the 16th July, 1976.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Further amendment in the Order of the Late Min. of Industrial Dev. and Company Affairs No. S.O. 4460/18A/IDRA/67 dated 14-12-1967.
323.	का० आ० 479 (अ), दिनांक 17 जुलाई, 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	श्री एस० एन० चट्टोपाध्याय को मैसर्स बर्न एण्ड कं० लि० और मैसर्स इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन क० लि० का अभिरक्षक नियुक्त करना।
	S.O. 479(E), dated the 17th July, 1976.	Ministry of Industry and Civil Supplies	Appointment of Shri S. N. Chattopadhya as custodian of M/s Burn & Company Ltd. and M/s. Indian Standard Wagon Co. Ltd.
324.	का० आ० 480 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 1976	गृह मंत्रालय	अधिप्रमाणन (आदेश अन्य लिखित) संशोधन नियम, 1976।
	S.O. 480(E), dated the 19th July, 1976.	Ministry of Home Affairs	Authentication (Orders and other Instruments) Fourth Amendment Rules, 1976.
325.	का० आ० 481 (अ), दिनांक 1 जुलाई 1976	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(2) के अधीन श्री एल्विन संगमा द्वारा दी गई अर्जी।
	S.O. 481(E), dated 19th July, 1976.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs	Petition under Section 8A(2) of Representation of the People Act, 1952, by Shri Elwin Sangma.
326.	का० आ० 482 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० को लक्ष्मीरतन काटन मिल्स क० लि० और अथर्टन वेस्ट एण्ड क० लि० का अभिरक्षक नियुक्त करना।
	S.O. 482(E), dated the 20th July, 1976.	Ministry of Commerce	Appointmeni of National Textile Corporation Ltd. as the custodian of Laxmirattan Cotton Mills Co. Ltd. and Atherton West and Co. Ltd.
	का० आ० 483 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 1976	—तदैव—	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तर प्रदेश) लि०, कानपुर को लक्ष्मीरतन काटन मिल क० लि० तथा अथर्टन वेस्ट एण्ड क० लि० का अपर अभिरक्षक नियुक्त करना।
	S.O. 483(E), dated the 20th July, 1976.	Do.	National Textile Corpn. (Uttar Pradesh) Ltd., Kanpur as the Additional Custodian of Laxmirattan Cotton Mills Co. Ltd. and Atherton West and Co. Ltd.
327.	का० आ० 484 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 1976	गृह मंत्रालय	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में माल के उस विक्रय की बाबत अधीन देय कर की गणना दिल्ली के व्यौहारी, उस दर पर की जाएगी जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है।
	S.O. 484(E), dated the 20th July, 1976.	Ministry of Home Affairs	The tax payable under the Central Sales Tax Act 1956 of goods specified in col. (2) of the annexed Table shall be calculated at the rate specified in col. (3) of the Table by any dealer in Delhi.
328.	का० आ० 485 (अ)/आई० ई० सी० ए०/5/76 दिनांक 20 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	आयात (नियंत्रण) 5वां संशोधन आदेश 1976।
	S.O. 485(E)/I.E.C.A./5/76, dated the 20th July, 1976.	Ministry of Commerce	Imports (Control) Fifth Amendment Order, 1976.

1	2	3	4
329.	का० आ० 486 (अ), दिनांक 21 जुलाई, 1976	निर्माण और आवास मंत्रालय	इण्डियन मिलिटरी एकादमी कम्पलैक्स की घटना की जांच आयोग की अवधि 31-7-76 तक बढ़ाना।
	S.O. 486(E), dated the 21st July, 1976.	Ministry of Works and Housing	Extension of date up to 31-7-76 of Inquiry Commission to enquire into the accident of Indian Military Academy Complex, Dehradun.
330.	का० आ० 487 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	सूती वस्त्र (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1976।
	S.O. 487(E) dated the 22nd July, 1976.	Ministry of Commerce	Cotton Textiles (Control) Second Amendment Order, 1976.
331.	S.O. 488(E), dated the 22nd July, 1976.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	Corrigenda in the Min. of Law, Justice and Company Affairs No. S.O. 426(E), dt. 23rd June, 1976.
332.	S.O. 489(E), dated the 22nd July, 1976.	Central Board of Direct Taxes	Corrigenda in the notification of Central Board of Direct Taxes No. 740(E) dt. 30-12-74.
	का० आ० 490 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 1976	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं० का० आ० 740 (अ), दि० 31-12-74 में शुद्धि।
333.	का० आ० 491 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) 27वां संशोधन आदेश, 1976।
	S.O. 491(E), dated the 23rd July, 1976.	Ministry of Commerce	Exports (Control) 27th Amendment Order, 1976.
334.	का० आ० 492 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1976	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	कृष्णा जल विवाद जिसका गठन जल विवाद अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना सं० का० आ० 1419, तारीख 10 अप्रैल 1969 को हुआ, का विघटन करना।
	S.O. 492(E), dated the 23rd July, 1976.	Ministry of Agriculture and and Irrigation.	Dissolution of Krishna Water Disputes Tribunal constituted under Inter-State water Disputes Act, 1955 vide notification No. S.O. 1419, dt. the 10th April, 1969.
335.	का० आ० 493 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 1976	गृह मंत्रालय	अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) पंचम संशोधन नियम 1976।
	S.O. 493(E), dated the 24th July, 1976.	Ministry of Home Affairs.	Authentication (Orders and other Instruments) Fifth Amendment Rules, 1976.
336.	का० आ० 494 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	पेट्रोलियम (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रवृत्त होने की तारीख 1 अगस्त 1976 नियत करना।
	S.O. 494(E), dated the 26th April, 1976.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Appointment of the day i.e., the 1st Aug., 1976 on which the Petroleum (Amendment) Act, 1970 shall come into force.
337.	का० आ० 495 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 1976	मंत्रिमण्डल सचिवालय	अपराधों को निर्धारित करना जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है।
	S.O. 495(E), dated the 26th July, 1976.	Cabinet Secretariat	Specification of offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment.
	का० आ० 496 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 1976	—तदैव—	अपराधों को निर्धारित करना जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाना है।
	S.O. 496(E), dated the 26th July, 1976.	Do.	Specification of offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment.
338.	का० आ० 497 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) 28वां संशोधन आदेश, 1976।
	S.O. 497(E), dated the 26th July, 1976.	Ministry of Commerce	Exports (Control) 28th Amendment Order, 1976.
339.	एस० ओ० 498 (अ)/आई० ई० सी० ए०/6/76 दिनांक 26 जुलाई 1976	—तदैव—	आयात (नियंत्रण) छटा संशोधन आदेश 1976।
	S.O. 498(E)/I.E.C.A./6/76, dated the 26th July, 1976.		Imports (Control) 6th Amendment Order, 1976.

1	2	3	4
340.	S.O. 499(E), dated the 28th July, 1976.	Ministry of Labour	Appointment of the day, i.e., the 1st day of Aug., 1976 on which the Labour Provident Fund Laws (Amdt.) ordinance, 1976 shall come into force.
	S.O. 500(E), dated the 28th July, 1976.	Do.	Retaining allowance as a rate of contribution payable every month to the Deposit-linked Insurance Fund under Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952, which shall come into force on 1-8-76.
	S.O. 501(E), dated the 28th July, 1976.	Do.	Retaining allowance as a rate of contribution payable every month to the Deposit-linked Insurance Fund under Coal Mines Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1948, which shall come into force on 1-8-76.
	S.O. 502(E), dated the 28th July, 1976.	Do.	Specifies 0.1% of the aggregate of the basic wages D.A. and retaining allowance for meeting the expenses of Admn. of the Insurance Scheme, which shall come into force on 1-8-76.
	S.O. 503(E), dated the 28th July, 1976.	Do.	Specifies 0.1% of basic wages, D.A. and retaining allowance for meeting the expenses of Admn. of the Insurance Scheme, which shall come into force on 1-8-76.
341.	का० आ० 504 (अ)/15/आई० डी० आर० ए०/76 दिनांक 29 जुलाई 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	कलकत्ता स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कं० प्रा० लि०, लिली बार्ले मिल्स (प्रा०) लि० और पी० सेट्ट एण्ड कं० (प्रा०) लि० के मामले की परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए एक समिति की नियुक्ति ।
	S.O. 504(E)/15/IDRA/76, dated the 29th July, 1976.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Appointment of Committee for making investigation into the circumstances of M/s. Lily Biscuit Co. Pvt. Ltd., Lily Barley Mills (P) Ltd. and P. Sett & Co. (P) Ltd. located at Calcutta.
342.	का० आ० 505 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	1-8-76 उस तारीख के रूप में निश्चित करना जिस तारीख को टैरिफ आयोग (निरसन) अधिनियम लागू होगा ।
	S.O. 505(E), dated the 30th July, 1976.	Ministry of Commerce	Appointment of the day i.e. 1-8-76 on which the Tariff Comm is sion (Repeal) Act, 1976 shall come into force.
343.	का० आ० 506 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1976	राजस्व और बैंककारी विभाग	स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 के उपबन्धों को प्रवृत करने के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों की नियुक्ति ।
	S.O. 506(E), dated the 30th July, 1976.	Department of Revenue and Banking	Appointment of officers as Gold Control officers for enforcing the provisions of the Gold (Control) Act 1968.
344.	का० आ० 507 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1976	—तदैव—	स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 ।
	S.O. 507(E), dated the 30th July, 1976.	Do.	Gold Control (Forms, Fees and Misc. Matters) Second Amendment Rules, 1976.
345.	का० आ० 508 (अ), दिनांक 30 जुलाई 1976	—तदैव—	स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1976 ।
	S.O. 508(E), dated the 30th July, 1976.	Do.	Gold Control (Licensing of Dealers) Amendment, Rules, 1976.
346.	का० आ० 509 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1976	—तदैव—	प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यवहारी को मानक स्वर्ण सिल्लियों के विक्रय की बाबत स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत छूट ।
	S.O. 509(E), dated the 30th July, 1976.	Do.	Exemption to licensed dealer in sale of standard gold bars refined in a town different from his licensed premises under Gold (Control) Act, 1968.
347.	का० आ० 510 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1976	—तदैव—	प्रत्येक अधिनिर्णायक अधिकारी और अपील प्राधिकारी को प्राथमिक स्वर्ण और वस्तु को अपने कब्जे में लेने के लिए प्राधिकृत करना ।
	S.O. 510(E), dated the 30th July, 1976.	Do.	Authority to adjudicating officer and appellate authority to take back primary gold or article which has been confiscated under Gold (Control) Act, 1968.
348.	का० आ० 511 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1976	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	दी गई सारणी में फिल्मों की एक मास की अवधि पर रोक ।
	S.O. 511(E), dated the 30th July, 1976.	Ministry of Information and Broadcasting	Exhibition of films mentioned in the Table, suspended for one month.

1	2	3	4
349.	का० आ० 512 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	मेसर्स नेशनल कं० लि० कलकत्ता की निधियों के विपथीकरण से उत्पन्न स्थिति से उत्पादन को प्रभावित होने से रोकने के लिए एक समिति का गठन।
	S.O. 512(E), dated the 30th July, 1976.	Ministry of Industry and Civil Supplies	Constitution of a Committee to prevent the affect on production due to diversion of funds in M/s. National Co. Ltd. Calcutta.
350.	एस० ओ० 513 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 1976	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	दी गई अनुसूची के कालम 2 में फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 513(E), dated the 31st July, 1976.	Ministry of Information and Broadcasting	Approval to films specified in col. 2 of the annexed Schedule.
351.	का० आ० 514(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/76 दिनांक 31 जुलाई, 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 237 (ई)/15/आई० डी० आर० ए०/76, दिनांक 25-3-76 में अग्रतर संशोधन।
	S.O. 514(E)/15/IDRA/76, dated the 31st July, 1976.	Ministry of Industry and Civil Supplies	Further amdt. in the order of Min. of Industry and Civil Supplies No. S.O. 237(E)/15/IDRA/76 dt. 25-3-76.
352.	का० आ० 515 (अ)/15/आई० डी० आर० ए०/76 दिनांक 31 जुलाई, 1976	—तदैव—	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश संख्या का आ० 412 (ई)/15/आई० डी० आर० ए०/76, दिनांक 9-6-76 में संशोधन।
	S.O. 515(E)/15/IDRA/76, dated the 31st July, 1976.	Do.	Amendment in the Order in the Min. of Industry and Civil Supplies No. 412(E)/15/IDRA/76 dt. 9-6-96.
353.	का० आ० 516 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 1976	—तदैव—	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० 665 (अ)/18ई/आई० डी० आर० ए०/75 ता० 19-11-75 में शुद्धि।
	S.O. 516(E), dated the 31st July, 1976.	Do.	Corrigendum in the Order in the Min. of Ind. & Civil Supplies No. S.O. 665(E)/18E/IDRA/75 dt. 19-11-75.
354.	का० आ० 517 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	कपास नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1976।
	S.O. 517 (E) dated the 31st July, 1976.	Ministry of Commerce	Cotton Control (2nd Amendment) Order, 1976.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

का०आ० 4777.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों के अनुसरण में निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन और आगे आदेश होने तक, विकय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) के धारा 8 के उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा भी (चाहे उन्हें उपराज्यपाल मुख्य आयुक्त या प्रशासक जो भी कहा जाता हो) उनके अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत, किया जाएगा।

[सं० यू०-11030/6/76-यू०टी०एल०]

हरीश चन्द्र बक्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd December, 1976

S.O. 4777.—In pursuance of clause (1) of atricle 239 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby directs that subject to his control and until further orders the powers and functions of the State Government under sub-section (1) of section 8 of Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976). shall also be exercised and discharged by the Administrators of Union Territories (whether known as Lt. Governor, Chief Commissioner or Administrator), in relation to their respective Union territories.

[No. U-11030/6/76-UTL]

H. C. BAKHSHI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1976

आय-कर

का०आ० 4778.—साधारण जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्थान को विहित प्राधिकारी, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि की पृथक लेखा रखेगा ;

(ii) कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलापों की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूपों में जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उन्हें प्रज्ञापित किए जाएं, प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक विहित प्राधिकारी को देगा।

संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली ।

यह अधिसूचना 22, जुलाई, 1976 से प्रभावी है ।

[सं० 1502/फा० सं० 203/122/76-आई टी ए-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 25th September, 1976

S.O. 4778.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions:—

(i) that the Indian Institute of Technology Delhi, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish the annual return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30'h April, each year.

INSTITUTION

THE INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI

This notification takes effect from 22nd July, 1976.

[No. 1502/F. No. 203/122/76-ITA. II]

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1976

(आय-कर)

का० आ० 4779.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'दि कांग्रेगेशन आफ दि फ्रांसिस्कन सिस्टर्स आफ दि प्रजेन्टेशन आफ वि ब्लेस्ड वर्जिन मेरी—कोयम्बटूर' को निर्धारण वर्ष (वर्षों) 1973-74 से और के लिए उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं० 1542/फा० सं० 197/30/76-आई टी (ए-I)]

New Delhi, the 30th October, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 4779.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies 'The Congregation of the Franciscan Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary-Coimbatore' for the purpose of said section for and from assessment year(S) 1973-74.

[No. 1542/F. No. 197/30/76-IT (AI)]

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1976

आय-कर

का० आ० 4780.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि उक्त विश्वविद्यालय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा ।

(ii) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर

यह अधिसूचना 17 जुलाई, 1976 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1544/फा० सं० 203/115/76-आई टी ए-II]

New Delhi, the 1st November, 1976

INCOME TAX

S.O. 4780.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) that the Kanpur University, Kanpur, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said University will furnish the annual return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

KANPUR UNIVERSITY, KANPUR

This notification takes effect from 17th July, 1976.

[No. 1544/ F. No. 203/115/76-ITA. II]

का० आ० 4781.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने दि इण्डियन कॉपर इन्फारमेशन सेन्टर कलकत्ता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि उक्त सेन्टर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा ।

(ii) उक्त सेन्टर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

दी इण्डियन कापर इन्फारमेशन सेन्टर, कलकत्ता ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 से तीन वर्ष की कालावधि के लिये प्रभावी है ।

[सं० 1547/फा० सं० 203/165/75-आई टी ए-II]

टी० पी० झुनझुनवाला, निदेशक

S.O. 4781.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 subject to the following conditions:—

(i) that the Indian Copper Information Centre, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Centre will furnish the annual return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

THE INDIAN COPPER INFORMATION CENTRE, CALCUTTA

This notification is effective for a period of three years with effect from 1st April, 1976.

[No. 1547/F. No. 203/165/75-ITA. II]
T. P. JHUNJHUNWALA, Director

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1976

का० आ० 4782.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, कानपुर, के स्टाफ अधिकारी, श्री एस० चिन्तामणि को, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर, के अध्यक्ष श्री के०डी० अग्रवाल के 15 नवम्बर, 1976 से 29 नवम्बर, 1976 तक की अवकाश-अवधि के दौरान, उपर्युक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 4-13/75-ए० सी०]

(Banking Wing)

New Delhi, the 27th November, 1976

S.O. 4782.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. Chintamani, Staff Officer, State Bank of India, Local Head Office, Kanpur, to act as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur, during the period of absence on leave of Shri K. D. Agrawal, Chairman of the said Kshetriya Gramin Bank, commencing on 15th November, 1976 and ending with 29th November, 1976.

[No. F. 4-13/75-AC]

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1976

का० आ० 4783.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० नायक को कोरापुट-पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपोर, का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 13 नवम्बर, 1976 से आरम्भ होकर 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें उक्त श्री पी० नायक, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 4-88/76-एसी]

New Delhi, the 30th November, 1976

S.O. 4783.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri P. Nayak as the Chairman of the Koraput-Panchabati Gramya Bank, Jeypore and specifies the period commencing on the 13th November, 1976 and ending with the 31st March, 1977 as the period for which the said Shri P. Nayak shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-88/76-AC]

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4784.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए० करुणाकर शेट्टी को साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 11 दिसम्बर, 1976 से आरम्भ होकर 30 जून, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें उक्त श्री ए० करुणाकर शेट्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 4-60/76-एसी]

New Delhi, the 11th December, 1976

S.O. 4784.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri A. Karunakara Shetty as the Chairman of the South Malabar Gramin Bank, Malappuram and specifies the period commencing on the 11th December, 1976 and ending with the 30th June, 1977 as the period for which the said Shri A. Karunakara Shetty shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-60/76-AC]

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4785.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए० एम० दामोदरन नायर को नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 12 दिसम्बर, 1976 से आरम्भ होकर 30 जून, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें उक्त श्री ए० एम० दामोदरन नायर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ 4-90/76-एसी]
सी० आर० विश्वास, उप सचिव

New Delhi, the 12th December, 1976

S.O. 4785.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri A. M. Damodaran Nair as the Chairman of the North Malabar Gramin Bank, Cannanore and specifies the period commencing on the 12th December, 1976 and ending with the 30th June, 1977 as the period for which the said Shri A.M. Damodaran Nair shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-90/76-AC]
C. R. BISWAS, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1976

शुद्धि-पत्र

का० आ० 4786.—दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखंड (ii) के पृष्ठ संख्या 2500 पर प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई, 1976 की अधिसूचना संख्या 15(22) बी० ओ० III/76 के हिन्दी पाठ में शब्द "धारा 10-क" के स्थान पर "धारा 10-ख" पढ़े जायें ।

[सं० 15(22)-बी० ओ० III/76]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 4786.—In the Hindi version of the Notification No. 15 (22)-B.O. III/76 dated the 3rd July 1976 published at page 2500 of the Gazette of India Part II Section 3 sub-section (ii) dated the 17th July 1976, the words "section 10-A" may be read as "section 10-B".

[No. 15(22)-B.O. III/76]
M. B. USGAONKAR, Under Secy.

का० आ० 4787.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्ध 30 जून, 1974 से 28 फरवरी, 1977 तक की अवधि के दौरान गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, ढुबरी पर लागू नहीं होंगे ।

[सं० एफ० 8-11/76-ए० सी०]
वी० एन० बहादुर, उप सचिव

S.O. 4787.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Goalpara District Central Cooperative Bank Ltd., Dhubri for the period from 30 June, 1974 to 28 February, 1977.

[No. F. 8/11/76-AC]
V. N. BAHADUR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4788.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 9 की उपधारा (i) के खंड (क) के उपखंड (1) और खंड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उप-खंड और खंड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित संस्थान को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

असम इंडस्ट्रियल डेवलेपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड

[फा० सं० 11-2/75-आई० एफ० II]
विजय शुंगलू, निदेशक

New Delhi, the 7th December, 1976

S.O. 4788.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of Section 9 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby notifies the following institution for the purposes of the said sub-clause and clause, namely:—

Assam Industrial Development Corporation Ltd.

[F. No. 11-2/75-IF. II]
V. K. SHUNGLU, Director

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1976

New Delhi, the 1st December, 1976

का० आ० 4789.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवम्बर, 1976 के दिनांक 19 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

S.O. 4789.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 19th day of November, 1976.

इशू विभाग
ISSUE DEPARTMENT

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.	रुपये Rs.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट Notes held in the Banking Department	15,93,84,000		सोने का सिक्का और बुलियन:— Gold Coin and Bullion :		
			(क) भारत में रखा हुआ (a) Held in India	182,52,45,000	
संचलन में नोट Notes in circulation	7209,55,15,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ (b) Held outside India	..	
जारी किये गये कुल नोट Total notes issued		7225,48,99,000	विदेशी प्रतिभूतियां Foreign Securities	921,73,97,000	
			जोड़ Total		1104,26,42,000
			रुपये का सिक्का Rupee Coin		15,78,67,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां Government of India Rupee Securities		6105,43,90,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
कुल देयताएं Total Liabilities		7225,48,99,000	कुल आस्तियां Total Assets		7225,48,99,000

दिनांक : 24 नवम्बर, 1976
Dated : 24th day of November, 1976

के० आर० पुरी, गवर्नर
K. R. PURI, Governor

19 नवम्बर, 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 19th November, 1976

देयताएं LIABILITIES	रुपये Rs.	आस्तियां ASSETS	रुपये Rs.
चुकता पूंजी Capital Paid up	5,00,00,000	नोट Notes	15,93,84,000
आरक्षित निधि Reserve Fund	150,00,00,000	रुपये का सिक्का Rupee Coin	6,05,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	400,00,00,000	छोटा सिक्का Small Coin	3,95,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	145,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :— Bills Purschased and Discounted:— (क) देशी (a) Internal	142,32,13,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	540,00,00,000	(ख) विदेशी (b) External	..
जमाराशियां:— Deposits:—		(ग) सरकारी खजाना बिल (c) Government Treasury Bills	243,97,57,000
(क) सरकारी (a) Government		विदेशों में रखा हुआ बकाया Balances Hold Abroad	1135,70,02,000
(1) केन्द्रीय सरकार (i) Central Government	61,51,07,000	निवेश Investments	304,80,77,000
राज्य सरकारें (ii) State Governments	11,20,00,000	ऋण और अग्रिम:— Loans and Advances to:— केन्द्रीय सरकार को (i) Central Government	..
(ख) बैंक (b) Banks		राज्य सरकारों को (ii) State Governments	105,77,61,000
अनुसूचित वाणिज्य बैंक (i) Scheduled Commercial Banks	849,39,33,000	ऋण और अग्रिम:— Loans and Advances to:— अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (i) Scheduled Commercial Banks	895,54,54,000
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (ii) Scheduled State Co-operative Banks	22,59,62,000	राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	295,60,38,000
गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	2,01,25,000	दूसरों को (iii) Others	7,42,71,000
अन्य बैंक (iv) Other Banks	63,19,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund (क) ऋण और अग्रिम :— (a) Loans and Advances to:— राज्य सरकारों को (i) State Governments	75,53,17,000
		राज्य सहकारी बैंकों को (ii) State Co-operative Banks	11,97,69,000
		केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को (iii) Central Land Mortgage Banks	..
		कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को (iv) Agricultural Refinance & Development Corporation	136,90,00,000
(ग) अन्य (c) Others	1860,94,90,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,04,16,000

देयताएं Liabilities	रुपये Rs.	आस्तियां Assets	रुपये Rs.
देय बिल		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
Bills Payable	87,26,73,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
अन्य देयताएं		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
Other Liabilities	613,43,80,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	85,81,82,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रचलन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	464,02,06,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों डिबेंचरों में निवेश	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank . . .	
		अन्य आस्तियां	
		Other Assets	818,51,42,000
रुपये		रुपये	
Rupees . . .	4748,99,89,000	Rupees	4748,99,89,000

दिनांक : 24 नवम्बर, 1976
Dated : 24th day of November, 1976

के० आर० पुरी, गवर्नर
K. R. PURI, Governor
[No. F. 10/1/76-B.O-I]

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव
C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, बम्बई)

बम्बई, 30 नवम्बर, 1976

का० आ० 4790.—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की दिनांक 25 सितम्बर, 1958 की अधिसूचना सं० एफ० आई० (67) ईसी/57 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 4 दिसम्बर, 1958 की उसकी अधिसूचना सं० एफ ई आर० ए० 168/58-आर०बी० की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन किए जाए, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

"लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०" प्रविष्टि के बाद "लक्ष्मी विलास बैंक लि०" प्रविष्टि का सन्निवेश किया जाए ।

[अधिसूचना सं० एफ ई आर ए 38/76-आर बी]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Central Office)

(Exchange Control Department, Bombay)

Bombay, the 30th November, 1976

S.O. 4790.—In pursuance of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. FI. (67) EC/57 dated 25th September, 1958 the Reserve Bank of India hereby directs that the following further amendment shall be made in the Schedule to its Notification No. FERA 168/58-RB dated 4th December, 1958, namely :—

In the said Schedule—

After the entry "Lakshmi Commercial Bank Ltd." the entry "Lakshmi Vilas Bank Ltd." shall be inserted.

[Notification No. FERA 38/76-RB]

K. R. KRISHNASWAMY, Dy. Governor

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आय-कर

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1976

का० आ० 4791.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित संस्था को प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी परामर्श के क्षेत्र में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ब की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है।

संस्था

हम्फ्री एण्ड ग्लासगो कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बाम्बे

यह अधिसूचना 16 अगस्त, 1976 से प्रभावी है ।

[सं० 1518/फा० सं० 203/129/76-आई टी ए II]

टी० पी० झुनझुनवाला, सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 12th October, 1976

INCOME TAX

S.O. 4791. It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause (a) of sub-section (2) of Section 35D of the Income-tax Act, 1961 in fields of Technological and Engineering Consultancy.

INSTITUTION

Humphreys and Glasgow Consultants Private Limited, Bombay.

This notification is effective from 16th August, 1976.

[No. 1518/F. No. 203/129/76-ITAII]

T. P. JHUNJHUNWALA, Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1976

आय-कर

का०आ० 4792.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 [फा० सं० 187/2/74 आई टी (ए 1)] तारीख 20 जुलाई, 1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. क्रम सं० 20 के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी :

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
20. आयकर आयुक्त जयपुर	जयपुर	1. जयपुर, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :— (क) जयपुर स्थित सभी वार्ड (ख) जयपुर स्थित सभी केन्द्रीय सर्किल (ग) जयपुर स्थित सभी कम्पनी सर्किल (घ) जयपुर स्थित सभी सर्वेक्षण सर्किल (ङ) जयपुर स्थित सभी वेतन सर्किल (2) भरतपुर (3) अलवर (4) सीकर (5) झुंझुनू (6) मुख्य लेखा परीक्षक और आयकर अधिकारी (आन्तरिक लेखा परीक्षा) जयपुर (7) कोटा (8) झालावाड़ (9) बूंदी (10) सवाई माधोपुर (11) जयपुर तथा कोटा स्थित सभी टी. आर. ओ. (12) सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक एवं 11 सांकल, जयपुर
आयकर आयुक्त जोधपुर	जोधपुर	(1) जोधपुर, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं— (क) जोधपुर स्थित सभी केन्द्रीय सर्किल (ख) जोधपुर स्थित सभी वार्ड (ग) जोधपुर स्थित सभी सर्वेक्षण सर्किल (2) पाली (3) जालौर (4) सिरोही (5) बाड़मेर (6) अजमेर (7) ब्यावर (8) भीलवाड़ा (9) चित्तौड़गढ़ (10) उदयपुर (11) बीकानेर (12) श्री गंगानगर (13) हनुमानगढ़ (14) नागौर (15) चुरू (16) अजमेर, बीकानेर और जोधपुर स्थित सभी टी०आर०ओ०

यह अधिसूचना 18-10-1976 से प्रभावी होगी।

[सं० 1517/फा० सं० 191/35/76-आई०टी० (ए० I)]

New Delhi, the 11th October, 1976

(INCOME-TAX)

S. O. 4792.—In exercise of the powers conferred by sub-sect[on (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 679 [F. No. 187/2/74-IT (AI)] dated the 20th July, 1974, as amended from time to time.

1. Existing entries under Columns (1), (2) and (3) against Sl. No. 20 shall be substituted by the following entries:—

Income tax Commissioner column-1	Headquarters column-2	Jurisdiction column-3
20. Commissioner of Income-tax, Jaipur.	JAIPUR	(1) Jaipur including:— (a) All wards at Jaipur. (b) All Central Circles at Jaipur. (c) All Company Circles at Jaipur. (d) All Survey Circles at Jaipur. (e) All Salary Circles at Jaipur. (2) Bharatpur (3) Alwar (4) Sikar (5) Jhunjhunu

1	2	3
		(6) Chief Auditor & I. T. O. (Internal Audit), Jaipur. (7) Kota (8) Jhalawar (9) Bundi (10) Sawaimadhopur (11) All TROs at Jaipur and Kota (12) Asst. Controller of Estate Duty-cum-IT Circle, Jaipur.
Commissioner of Income-tax, Jodhpur.	JODHPUR	(1) Jodhpur including:— (a) All Central Circles at Jodhpur. (b) All wards at Jodhpur. (c) All Survey Circles at Jodhpur. (2) Pali (3) Jalore (4) Sirohi (5) Barmer (6) Ajmer (7) Beawar (8) Bhilwara (9) Chittorgarh (10) Udaipur (11) Bikaner (12) Sriganganagar (13) Hanumangarh (14) Nagaur (15) Churu (16) All TROs at Ajmer, Bikaner & Jodhpur.

This notification shall take effect from 18-10-1976.

EXPLANATORY NOTE : This Notification has been issued on account of the change of Headquarters of the Commissioner of Income-tax, Rajasthan-II from Jaipur to Jodhpur. This does not form part of notification but is intended to be merely clarifactory.

[No. 1517/F. No. 191/35/76-IT(AI)]

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1976

आय-कर

का० आ० 4793.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63 आई०टी०) तारीख 18-5-64 से उपाबद्ध अनसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है—

विद्यमान क्रम सं० 12(क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
12(क)	महाराष्ट्र राज्य के बृहत्तर मुम्बई जिला की सीमाओं में निवास करने वाले या कारबार, वृत्ति अथवा व्यवसाय करने वाले सभी व्यक्ति जिनकी आय मुख्यतः चलचित्रों के उत्पादन, वितरण, प्रचार और प्रदर्शन, स्टुडियों या प्रयोगशाला के स्वामित्व या चलचित्र संबन्धी माल और मशीनरी के प्रदाय से व्युत्पन्न होती है या जो सिनेमा या फिल्म कलाकार, फिल्मों के निदेशक, सिनेमा-पार्श्वगायक, फिल्म संपादक फिल्म कैमरामैन, चलचित्र कला और नृत्य निदेशक, सिने-संगीतकार सिनेसंगीत निदेशक तथा फिल्म वित्तदाता है (फिल्म वित्तदाता से ऐसे व्यक्ति से तात्पर्य है जिसकी आय पूर्णतः या मुख्यतः फिल्मों के उत्पादन या वितरण में वित्त लगाने से व्युत्पन्न होती है)	आयकर अधिकारी, फिल्म सर्किल मुम्बई	आयकर आयुक्त (अपील), फिल्म रेंज, मुम्बई	सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिसमें स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्तियां निहित की गई हैं	आयकर आयुक्त, मुम्बई सिटी 1, मुम्बई
(ख)	महाराष्ट्र राज्य के बृहत्तर मुम्बई जिला की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले या कारबार, वृत्ति या व्यवसाय करने वाले सभी व्यक्ति जो ऊपर (क) के अनुसार फिल्म सर्किल, मुम्बई के अधीन निर्धारित फर्मों के भागीदार हैं।	आयकर अधिकारी, फिल्म सर्किल, मुम्बई	आयकर आयुक्त, (अपील), फिल्म रेंज, मुम्बई	सहायक आयकर आयुक्त (अपील), स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्तियां निहित की गई हैं	आयकर आयुक्त, मुम्बई सिटी 1, मुम्बई

यह अधिसूचना 1-11-1976 से प्रभावी होगी।

[सं० 1530/फा० सं० 187/5/76-आई० टी० (ए I)]

New Delhi, the 19th October, 1976

INCOME TAX

S.O. 4793.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT), dated 18-5-64.

The existing Serial No. 12(a) and (b) will be substituted as under:—

1	2	3	4	5	6
12(a)	All persons residing or carrying on business, profession or vocation within the limits of Greater Bombay District of Maharashtra State, whose income is mainly derived from production, distribution, publicity or exhibition of movie films; ownership of studios or laboratories or supply of cinematographic goods & machinery; or who are cine & film artists, film directors, cine-play-back singers, film editors, film cameramen, movie-art and dance directors, cine-musicians, cine-music directors, and film financiers ("film financier" refers only to a person whose income is wholly or mainly derived from the business of financing the production or distribution of films).	ITO, Film Circle, Bombay	IAC of I.T. Film Range, Bombay.	AAC of I.T. who has been invested with powers to hear appeals against the decision of the I.T.O. referred to in col. 3.	Commissioner of I.T., Bombay City-I, Bombay.
(b)	All persons residing or carrying on business, profession or vocation within the limits of Greater Bombay District of Maharashtra State, who are partners of firms assessed in Film Circle, Bombay by virtue of (a) above.	ITO, Film Circle, Bombay.	IAC of I.T. Film Range, Bombay.	AAC of IT who has been invested with powers to hear appeals against the decision of the I.T.O. referred to in col.3.	Commissioner of Income Tax, Bombay City-I, Bombay.

This notification shall take effect from 1-11-1976.

[No. 1530/F. No./187/5/76-IT (AI)]

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1976

(आय-कर)

शुद्धिपत्र

का० आ० 4794.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 [फा० सं० 187/2/74-आई टी (एआई)] तारीख 20-7-74 की क्रम सं० 18-क के सामने स्तम्भ I के नीचे निम्नलिखित संशोधन करता है।

"हरयाणा" के स्थान पर

"हरयाणा और चण्डीगढ़" पढ़ें।

[सं० 1537/फा० सं० 191/24/76 आई टी (ए आई)]

New Delhi, the 25th October, 1976

(INCOME-TAX)

CORRIGENDUM

S.O. 4794.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment against Sl. No. 18-A under column-1 of its Notification No. 679 [F. No. 187/2/74-IT(AI)] dated 20-7-74, as amended from time to time.

FOR—"Haryana"

READ—"Haryana and Chandigarh".

[No. 1537/F. No. 191/24/76-IT(AI)]

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1976

का०आ० 4795.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63–आई०टी०) तारीख 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में, आय-कर अधिकारी, बीमा अभिकर्ता सर्किल, क-वार्ड, कलकत्ता और आय-कर अधिकारी, बीमा अभिकर्ता सर्किल, ख-वार्ड, कलकत्ता से संबन्धित विद्यमान प्रविष्टियों का लोप करता है और उक्त अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ता है :—

1	2	3	4	5	6
85.	कलकत्ता शहर हावड़ा तथा 24 परगना के सिविल जिलों के भीतर के सभी व्यक्ति जिनकी आय में, बीमा कारबार (जिसमें बीमा-पालिसियों के चलाने नवीकरण या पुनः प्रवर्तन से सम्बद्ध कारबार सम्मिलित है) उपार्जन करने या उसकी याचना करने के लिए कमीशन या अन्य रूप में पारिश्रमिक या इनाम हो, उनसे भिन्न जो, वेतनों (और केन्द्रीय वेतन सर्किल, रेल और प्रकीर्ण वेतन सर्किल, जिला III-क और जिला V-क, कलकत्ता में किसी भी आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारणयोग्य है) या (ii) कारबार और/या बीमा अभिकर्ता के रूप में से भिन्न वृत्ति, से भी आय व्युत्पन्न करते हैं ।	आयकर अधिकारी, बीमा अभिकर्ता सर्किल, कलकत्ता ।	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) जिसमें बीमा अभिकर्ता सर्किल कलकत्ता की बाबत सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने की शक्तियां विहित हैं ।	सहायक आयकर आयुक्त (अपीली) जिसमें, स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्तियां ।	आयकर आयुक्त जिसमें स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी पर अधिकारिता निहित है ।

यह अधिसूचना 15-11-1976 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1541/फा० सं० 187/8/76–आई० टी० (ए–I)]
एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1976

S.O. 4795.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby deletes the existing entries relating to the Income-tax Officer, Insurance Agents Circle, A-Ward, Calcutta and Income-tax Officer, Insurance Agents Circle, B-Ward, Calcutta in the Schedule annexed to its Notification No.I (F.No. 55/233/63-IT) dated the 18th May, 1964 as amended from time to time and adds the following entry in the said schedule :—

1	2	3	4	5	6
Sl. No. 85	All persons within the city of Calcutta and the Civil District of Howrah and 24-Parganas with income by way of remuneration or reward whether by way of commission or otherwise, for soliciting or procuring Insurance business (including business relating to the continuance, renewal or revival of Policies of Insurance), other than those who derive income also from (i) salaries (and are assessable by any of the Income-tax Officers in Central Salaries Circle, Railways and Miscellaneous Salaries Circle, Distt. III-A, and Dist. V-A, Calcutta) or (ii) business and /or profession other than as an Insurance Agent.	Income-tax Officer, Insurance Agents Circle, Calcutta.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax who has been vested with the powers to perform the functions of an Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax in respect of Insurance Agents Circle, Calcutta.	Appellate Assistant Commissioner of Income tax who has been vested with the powers to hear appeals against the decisions of the Income-tax Officer referred to in Col. 3.	Commissioner of Income-tax who has been vested with the jurisdiction over the Income-tax Officer referred to in Col. 3.

This notification shall take effect from 15-11-1976.

[No. 1541/F.No. 187/8/76-IT(AD)]
M. SHASTRI, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 1976

का०आ०4796.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि बीज-रहित इमली का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तथार किए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम, II के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण को, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे, तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' 14/1 बी एझरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-700001 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि बीज रहित इमली का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा।

(2) इस आदेश के उपाबन्ध 1 में दिए गए, बीज रहित इमली के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार, निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसी बीज रहित इमली पर लागू होगा,

(3) इस आदेश के उपबंध 2 में दिए गए विनिर्देशों को, बीज रहित इमली के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना,

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान बीज रहित इमली के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि ऐसी बीज रहित इमली के पैकेटों या डिब्बों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, इस आशय का चिन्ह या सील न लगा हो या चिपकाया गया हो कि यह इमली उसे लागू होने वाले मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा उसके साथ उसके निर्यात योग्य होने के प्रमाणस्वरूप भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत उस निदेशालय के किसी और अधिकारी द्वारा जारी किया गया श्रेणीकरण का प्रमाण पत्र न हो।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को जलमार्ग, भू मार्ग या वायु मार्ग से निर्यात किए गए बीज रहित इमली के उन नमूनों पर लागू नहीं होगी जिनका मूल्य बीस रुपए से अधिक नहीं हो।

4. इस आदेश में "बीज रहित इमली" से इमली के पेड़ (टैमेरिंडस इंडीकस) के पके फलों से सर्व प्रथम उसके छिलके को, इसके पश्चात् गूदे तथा बीजों को ढकने वाली रेशेदार जाली को उतार कर, प्राप्त इमली का गूदा अभिप्रेत है।

उपाबंध 1

[निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने वाले प्रस्थापित नियमों का प्रारूप]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—इन नियमों का नाम बीज रहित इमली का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 है।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "निरीक्षण अधिकारी" से बीज रहित इमली के निरीक्षण के लिए कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत पैकर" से वह व्यक्ति या व्यक्ति-समूह अभिप्रेत है, जिसे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अन्तर्गत के केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य तथा कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्हन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किए गए बीज रहित इमली श्रेणीकरण तथा चिन्हन नियम, 1971 में विहित मानक विनिर्देशों के अनुसार बीज रहित इमली का श्रेणीकरण तथा चिन्हन करने के लिए कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकरण का प्रमाण-पत्र दिया गया है,

(घ) "प्राधिकरण प्रमाण-पत्र" से कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, "बीज रहित इमली" श्रेणीकरण तथा चिन्हन नियम, 1975 के अनुसार बीज रहित इमली के श्रेणीकरण के इच्छुक प्राधिकृत पैकर को जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है।

(ङ) "बीज रहित इमली" से इमली के पेड़ (टेमरिंडस इंडीकस) के पके फलों से सर्व प्रथम उसके छिलके को, इसके पश्चात, गूदे तथा बीजों को ढकने वाली रेशेदार जाली को उतार कर प्राप्त इमली का गूदा अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार—बीज रहित इमली का निरीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि बीज रहित इमली निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य तथा कृषि उत्पादन (श्रेणीकरण तथा चिन्हन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किए गए बीज रहित इमली श्रेणीकरण तथा चिन्हन नियम, 1971 में विहित विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) निर्यात के लिए तैयार बीज रहित इमली कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्राधिकृत पैकर द्वारा श्रेणीबद्ध तथा पैक की जाएगी।

(2) प्राधिकृत पैकर इस बात का उत्तरदायी होगा कि वह बीज रहित इमली के विनिर्माण तथा नमूना लेने का तथा परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का ऐसा प्रबन्ध करें जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) विनिर्माण तथा पैक करने के लिए प्रयुक्त परिसर स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। कर्मचारी को कोई संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए।

(4) बीज रहित इमली के श्रेणीकृत तथा लेबल लगे परेषण का निर्यात करने का इच्छुक प्राधिकृत पैकर श्रेणीकरण प्रमाण-पत्र के लिए पास ही के निरीक्षण अधिकारी को नियम 3 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निर्धारित विवरणों के लिखित आवेदन करेगा जिससे कि वह श्रेणीकरण प्रमाण-पत्र दे सके ।

(5) उप-नियम (4) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना बम्बई, कलकत्ता मद्रास, कोचीन, तूतीकोरीन तथा नागपत्तिनम शहरों की बन्दरगाहों पर जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों के लिए कम से कम दो दिन पूर्व, तथा अन्य स्थानों पर प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए कम से कम तीन दिन पूर्व, दी जाएगी ।

(6) उप-नियम, (4) में निर्दिष्ट सूचना के प्राप्त होने पर, निरीक्षण अधिकारी बीज रहित इमली के परेषण (परेषणों) का निरीक्षण, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार यह देखने के विचार से करेगा कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

(7) यदि निरीक्षण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है तो वह बीज रहित इमली के डिब्बों पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार एग्मार्क लेबल जारी करेगा और उन्हें कंटेनरों पर चिपकवा देगा । घटिया परेषणों के संबंध में वह एग्मार्क लेबल जारी करने से इंकार कर सकता है और पैकर को लिखित रूप में कारणों सहित वास्तविकता से अवगत कराएगा ।

(8) यदि ऐसे बीज रहित इमली के परेषणों के जांच नमूने लेने तथा जांच नमूनों का परीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जो श्रेणी दी गई हैं वह मान्य विनिर्देशों के अनुसार हैं तो वह उस परेषण (परेषणों) के संबंध में श्रेणीकरण प्रमाण-पत्र दे देगा ।

(9) यदि निरीक्षण अधिकारी का यह समाधान नहीं हुआ है कि परेषण का श्रेणीकरण मान्य नियमों के अनुसार हुआ है तो वह प्राधिकृत पैकर को दस दिनों के भीतर इस तथ्य की लिखित रूप में, उसके कारणों सहित, संसूचित करेगा ।

5. निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के प्रयोजन के लिए पहला निरीक्षण प्राधिकृत परिसर पर किया जाएगा तथा जांच-निरीक्षण निर्यात से पूर्व किसी भी स्थान पर किया जा सकता है ।

6. एग्मार्क लेबलों के मूल्यों का भुगतान—प्राधिकृत पैकर, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एग्मार्क लेबल मूल्यों का भुगतान कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित नीति से करेगा ।

7. अपील—(1) यदि प्राधिकृत पैकर क्षेत्रीय प्रयोगशाला के विश्लेषणात्मक परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह संबंधित क्षेत्रीय वरिष्ठ विपणन अधिकारी से परेषण के पुनः परीक्षण की व्यवस्था करने के लिए लिखित रूप में प्रार्थना कर सकता है । उसके लिए जांच-नमूना लिया जाएगा तथा पैकर को विश्लेषी का परिणाम बता दिया जाएगा ।

(2) अगर उस पर भी प्राधिकृत पैकर जांच नमूना लेने से संतुष्ट नहीं है तो वह भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, नव सचिवालय भवन, नागपुर के विश्लेषण की व्यवस्था करने के लिए लिखित रूप में निवेदन कर सकता है । ऐसी दशा से प्राधिकृत पैकर को लिखित रूप में यह वचन देना होगा कि यदि क्षेत्रीय प्रयोगशाला के पहले वाले निष्कर्ष सही पाए जाते हैं तो वह 50 रु० देगा । ऐसा निवेदन किए जाने तथा आश्वासन प्राप्त होने पर परेषण में से नया जांच-नमूना लेने की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निश्चित की गई प्रयोगशाला में भेज दिया जाएगा और इसका विश्लेषणात्मक परिणाम प्राधिकृत पैकर को यथा संभव शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा और वही अन्तिम माना जाएगा ।

उपाबंध 2

बीज रहित इमली के लिए विनिर्देश

श्रेणी पदनाम	रंग	विशिष्ट विशेषताएं			सामान्य विशेषताएं
		आर्द्रता (भार के आधार पर प्रतिशत)	सहयता की अधिकतम सीमा बीज का अंश (भार के आधार पर प्रतिशत)	गूदे तथा रेशेवार जाली को सम्मिलित करते हुए बाह्य पदार्थ (भार के आधार पर प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6
विशिष्ट . .	हल्का लाल	15.00	3.0	1.5	(1) इमली के पेड़ (टेमरिंडस इनडीकस) के परिपक्व फलों से सर्व प्रथम छिलके को, इसके पश्चात् गूदे तथा बीजों को ढकने वाली रेशेवार जाली को उतार कर प्राप्त किया गया इमली का गूदा होगा ।
बढ़िया . .	लाल आभा लिए हुए भूरा	17.00	5.0	3.0	(2) गूदा भली प्रकार सुखा लिया जाएगा तथा उसे टिक्की के रूप में बना दिया जाएगा ।
अच्छा . . .	गहरे भूरे से हल्का काला	19.00	8.0	5.5	(3) गूदा कीड़ों के उत्पीड़न से मुक्त या जीवित कीड़ों रहित होगा ।

1	2	3	4	5	6
औसत . . .	काला	22.00	10.0	6.0	(4) केक का रंग एक समान होगा।
अविनिर्दिष्ट .	—	—	—	—	(5) गूदे की एक विशिष्ट स्वाद तथा सुगंध होगी तथा उसमें कैसी भी अप्रिय गंध नहीं होगी।

नोट :—अविनिर्दिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत पैकिंग की अनुमति केवल विदेशी क्रेता के विशिष्ट आदेश के आधार पर ही दी जाएगी। ऐसे आदेश में वांछित उत्पाद की मात्रा तथा क्वालिटी दी जानी चाहिए।

[सं० 6 (17)/76/नि०नि०तथा नि०उ०]
के० वी० बालसुब्रह्मण्यम्, उप-निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 25th December, 1976

S.O. 4796.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that seedless tamarind should be subject to quality control and inspection prior to export :

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 :

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/IB, Ezra Street (7th Floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that seedless tamarind shall be subject to quality control and inspection prior to export :

(2) to specify the type of inspection in accordance with the draft export of seedless Tamarind (Inspection) Rules, 1976, set out in the Annexure-I to this Order as the type of quality control and Inspection which shall apply to such seedless tamarind prior to export :

(3) to recognise the specifications as set out in Annexure II to this order as the standard specifications for seedless tamarind :

(4) to prohibit the export in the course of international trade of seedless tamarind, unless a mark or seal recognised by the Central Government as indicating that it conforms to the standard specifications applicable to it has been affixed or applied to packages or containers of such seedless tamarind, and is accompanied by a certificate of grading issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection or any other officer of that Directorate, authorised by him in this behalf, in token of its portworthiness.

3. Nothing in this order shall apply to export by sea, land or air of samples of seedless tamarind not exceeding in value of rupees twenty to prospective buyers.

4. In this order, "seedless tamarind" means the tamarind pulp obtained from the mature fruits of tamarindus indicus by removing first the rind, then the fibrous skelton enclosing the pulp and the seeds.

ANNEXURE-I

[Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963] (22 of 1963)]

In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Export of seedless tamarind (Inspection) Rules, 1976.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;

(b) "Inspecting Officer" means the officer authorised by the Agricultural Marketing Adviser for inspection of seedless tamarind ;

(c) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation by the Agricultural Marketing Adviser for getting seedless tamarind graded and marked in accordance with the standard specifications prescribed in the Seedless Tamarind (Grading and Marking) Rules, 1971, issued under sceiton 3 of the Agricultural produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963.) :

(d) "Certificate of Authorisation" means the certificate by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf, to an authorised packer desirous of grading seedless tamarind as per "Seedless Tamarind" Grading and Marking Rules, 1975.

(e) "Seedless Tamarind" means the tamarind pulp obtained from mature fruits of tamarindus indicus by removing first the rind, then the fibrous skelton enclosing the pulp and the seeds.

3. Bases of inspection-Inspection of seedless tamarind shall be carried out with a view to seeing that seedless tamarind conforms to the specifications prescribed in the Seedless Tamarind Grading and Marking Rules, 1971, issued under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

4. *Procedure of inspection.*—(1) Seedless tamarind meant for export shall be graded and packed by the Authorised packer in accordance with the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other Officer authorised by him in this behalf. For this purpose, the authorised packer shall obtain the Certificate of Authorisation from the Agricultural Marketing Adviser.

(2) It shall be the responsibility of the Authorised Packer to make such arrangements for manufacturing and sampling of seedless tamarind and also provide requisite facilities for testing etc. as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) The manufacturing and packing premises shall satisfy the requirements of sanitary and hygienic standards. The workers shall be free from contagious diseases.

(4) An authorised packer intending to export the graded and labelled consignment of seedless tamarind shall apply to the nearest inspecting Officer for the certificate of Grading in writing, alongwith such details as prescribed by the Agricultural Marketing Adviser in accordance with rule 3 to enable him to issue a Certificate of Grading.

(5) Every intimation under sub-rule (4) shall be given not less than 2 days before the Certificate is to be issued at the port towns of Bombay, Calcutta, Madras, Cochin, Tuticorin and Nagapattinam and not less than 3 days before the certificate is to be issued at other places.

(6) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (4), the Inspecting Officer shall inspect the consignment(s) of seedless tamarind as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other Officer authorised by him in this behalf, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specification referred to in rule 3.

(7) The Inspecting Officer shall issue Agmark labels affixing the same on the containers of seedless tamarind as per instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser in case he is satisfied that the consignment is as per recognised specifications referred to in rule 3. In case of sub-standard consignments he may refuse to issue Agmark labels and convey the fact in writing to the packer alongwith reasons.

(8) If after check-sampling of the consignments of such seedless tamarind and after examination of the check-sample, the Inspecting Officer is satisfied that the Grade assigned is as per recognised specifications he shall issue a certificate of grading in respect of that consignment(s).

(9) In case the Inspecting Officer is not satisfied that the consignment is graded as per recognised rules, he shall intimate the fact in writing to the authorised packer within ten days alongwith the reasons thereof.

5. Place of inspection.—Initial inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the authorised premises and check-inspection can be done at any point before export.

6. Payment of charges for Agmark labels.—The authorised packer shall pay the Agmark label charges which are notified by the Government of India from time to time, in the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

7. **Appeal**

(1) If the authorised packer is not satisfied with the analytical results of the Regional Laboratory, he shall be entitled to request the Regional Senior Marketing Officer concerned, in writing to arrange for the re-examination of the consignment. A check-sample shall, therefore, be drawn and the result of analysis made known to the packer.

(2) If the authorised packer is still not satisfied with check-sampling, he may request the Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India, New Secretariat Building, Nagpur, in writing to arrange for analysis. The authorised packer, in such cases, shall give an undertaking in writing to the effect to pay Rs. 50/- if the initial findings of the Regional Laboratory are proved to be in order. On receipt of the request and undertaking, arrangements may be made to draw a fresh check-sample from the consignments and send the same to such a Laboratory as may be decided by the Agricultural Marketing Adviser and the analytical report shall be made available to the authorised packer as early as possible and the same be taken as final.

ANNEXURE II

Specifications for seedless Tamarind

Grade Designation	Colour	Special characteristics			General, characteristics.
		Maximum limits of Tolerance			
		Moisture (percentage by weight)	Seed content (percentage by weight)	Foreign matter including fibre-strand and rind (Percentage by weight)	
1	2	3	4	5	6
SPECIAL	Light Red	15.00	3.0	1.5	(i) The tamarind pulp shall have been obtained from the mature fruits of Tamarindus indica, by removing first the rind and then the fibrous skeleton enclosnig the pulp and the seeds.
GOOD	Red tinged brown	17.00	5.0	3.0	(ii) The pulp shall be well dried and compressed into cakes.

1	2	3	4	5	6
FAIR	Dark Brown to Light Black	19.00	8.0	4.5	(iii) The pulp shall be free from insect infestation or live insects.
AVERAGE	Black	22.00	10.0	6.0	(iv) The colour of the cake shall be uniform.
NON-SPECIALISED	..	..	..	..	(v) The pulp shall have the characteristics taste and flavour and shall be free from any obnoxious odour.

NOTE : Packing under Non-specified Grade shall be allowed only against a specific order from the foreign buyer indicating the quantity and quality of the produce desired.

[No. 6(17)/76/EI&EP]
K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director

मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4797.—सर्वश्री इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 4,67,100 रुपए मात्र के लिए फ्यूल कोकर आदि के लिए फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या आई/ए/1392031/सी/एक्स एक्स/54/एच/39-40 दिनांक 16-1-75 प्रदान किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की एक अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति पंजीकृत कराए बिना और उपयोग में लाए बिना ही खो गई है । इसके समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और आवेदक को उसकी अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए ।

2. समय समय पर यथा संशोधित आयात व्यापार (नियन्त्रण) आदेश सं० 17/55 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 4,67,100 रुपए मात्र के लिए फ्यूल कोकर आदि के पुर्जों का आयात करने के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० आई/ए/1392031/सी/एक्स एक्स/54/एच/39-40 दिनांक 16-1-75 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची 65/5 के अन्तर्गत रद्द करता है ।

[संख्या 27-28.I/आयलको/74-75/जीएलएस/931]
एल० प्रशाद, उपमुख्य नियन्त्रक
कृते मुख्य नियन्त्रक

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 4th December, 1976

S.O. 4797.—M/s. Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi were granted an Import Licence No. I/A/1392031/C/XX/54/H/39-40 dated 16-1-75 for Rs. 4,67,100 only for import of spare parts for fuel coker etc. from G.C.A. They have applied for the issue of a duplicate Customs Purpose Copy of import licence mentioned above on the ground that the original Customs Purpose Copy has been lost without having been registered and without being utilised. In support of this, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purpose Copy of import licence mentioned above has been lost and that duplicate copy thereof should be issued to the applicant.

2. In exercise of powers conferred on me under Clause 9 (cc) of the Import Trade (Control) Order No. 17/55 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the undersigned cancels the Customs Purpose Copy of Import Licence No. I/A71392031/C/XX/54/H/39-40 dated 16-1-75 for Rs. 4,67,100 only for the import of spare parts for fuel coker etc. from G.C.A. under ITC Schedule 65/V issued in favour of M/s. Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi.

[No. 27-28.1/Oilco/74-75/GLS/931]
L. PRASAD, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1976

का० आ० 4798.—सर्वश्री बंगाल टूल्स लि०, 251/1 नगेन्द्र नाथ रोड़, दमदम, कलकत्ता को कच्चे माल तथा संघटकों का आयात करने के लिए 1,00,000 रुपए के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2201199, दिनांक 7-8-75 प्रदान किया गया था ।

2. पार्टी ने उक्त आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि दोनों मूल प्रतियां उपयोग में लाए बिना और सीमाशुल्क सदन, कलकत्ता के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई हैं ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1976-77 के पैरा 320 के अन्तर्गत एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2201199, दिनांक 7-8-75 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं तथा निदेश देता है कि आवेदक को मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रतियां जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमा शुल्क प्रयोजन प्रतियां मिल जाने पर, इस कार्यालय को रद्द करने के लिए लौटा दी जाएंगी ।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमा शुल्क प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं ।

[संख्या टूल्स/56-डी(आर एम) 74-75/आर एम-7/863]

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1976

S.O. 4798.—M/s. Bengal Tools Ltd., 251/1, Nagendra Nath Road, Dum Dum, Calcutta-28, were granted Import Licence No. P/D/2201199 dated 7-8-75 for Rs. 1,00,000 for import of Raw Material and Components.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copies of Exchange Control and Customs Purpose Copies of the abovementioned import licence on the ground that both the original copies have been lost without having been utilised and registered with the Custom House, Calcutta.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit, as required in para 320, of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1976-77. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control and Customs Copies of Import Licence No. P/D/2201199 dated 7-8-75 have been lost and directs that duplicate copies of Exchange Control and Customs Copies of the licence, should be issued to the applicant. The original Exchange Control and Customs Copies of the licence, if found, will be forwarded to this office for cancellation.

4. The duplicate copies of Exchange Control and Customs Copies of the import licence are being issued separately.

[File No. Tools/56-D(RM) 74-75/RM. VII/863]

आदेश

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4799.—श्री आर० वी० एस० राणावत, 3 गार्डस (राजराईफ) द्वारा 56 ए० पी० ओ० को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत एक ·22 बोर राइफल का आयात करने के लिए 735 रुपए के लिए एक सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या पी/जे/3035888/एम/एम एन/40/एच/35-36/ए एम एस, दिनांक 25-7-1973 प्रदान किया गया था । उन्होंने सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया/अस्थानस्थ हो गया है । लाइसेंसधारी ने आगे यह सूचित किया है कि सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना अस्थानस्थ हो गया/खो गया है और उसका बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3035888 दिनांक 25-7-1973 अस्थानस्थ हो गया/खो गया है और निदेश देता है कि उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट रद्द किया जाता है । सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या 314-4/आर-191/ए एम-73/ए० एल० एस०/951]

ORDER

New Delhi, the 9th December, 1976

S.O. 4799.—Shri R. V. S. Ranawat, 3, Guards (Raj. Rif.) c/o 56 A.P.O. was granted C.C.P. No. P/J/3035886/N/MN/48/H/35-36/ALS dated 25-7-1973 for Rs. 735 under G.C.A. for import of one .22 bore rifle. He has requested for issue of duplicate copy of the C.C.P. on the ground that original C.C.P. has been lost/misplaced by him. It has further been reported by the licensee that the C.C.P. has been misplaced/lost without having been registered with any Custom Authority and that the same has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original C.C.P. No. P/J/3035888 dated 25-7-1973 has been misplaced/lost and directs that duplicate copy of the said C.C.P. should be issued to him. The original C.C.P. is cancelled. Duplicate copy of the C.C.P. is being issued separately.

[No. 314-IV/R-191/AM-73/ALS/951]

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4800—श्री रवीन्द्र कुमार जेटली, 30/34, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 को औद्योगिक सिलाई मशीनरी के आयात के लिए 1,06,890 रुपए के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/सी/जी/2070809/एन/एम एन/61/एच/43-44 दिनांक 30-10-76 प्रदान किया गया था । उन्होंने आयात लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति के साथ) की अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है, क्योंकि मूल आयात लाइसेंस खो गया है । आगे यह कहा गया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं थी और उसका उपयोग नहीं किया गया था ।

2. अपने तर्क के समर्थन में श्री रवीन्दर कुमार जेटली ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । उन्होंने यह वचन दिया है कि बाद में यदि आयात लाइसेंस मिल जाएगा तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देंगे । मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल आयात लाइसेंस संख्या पी/सी/जी/2070809/एन/एम एन/61 एच/43-44 दिनांक 30-10-76 खो गया है और निदेश देता हूं कि एक अनुलिपि लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति के साथ) उन्हें जारी किया जाना चाहिए । मूल आयात लाइसेंस को रद्द किया गया समझा जाए ।

3. उक्त लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति के साथ) की एक अनुलिपि प्रति लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या 47/आई एन एस ए/76-77/बी एल एस/2647]

एच० एल० बहल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 10th December, 1976

S.O. 4800.—Mr. Ravinder Kumar Jaitli, 30/34, West Patel Nagar, New Delhi-110008 was granted Import Licence No. P/CG/2070809/N/MN/61/H/43-44 dated 30-10-76 for Rs. 1,06,890 for import of Industrial Sewing Machinery has applied for a duplicate copy of the Import Licence (with Exchange Control Purposes Copy) as the original Import Licence has been lost. It is further stated that the original Import Licence was not registered with any Customs House and utilised.

2. In support of this contention Mr. Ravinder Kumar Jaitli has filed an affidavit. He has undertaken to return the Import Licence if traced later to this office for record. I am satisfied that the original, Import Licence No. P/CG/2070809/N/MN/61/H/43-44 dated 30-10-76 has been lost and direct that a duplicate Import Licence (with Exchange Control Purposes Copy) should be issued to him. The original Import Licence may be treated as cancelled.

3. A duplicate copy of the said licence (with Exchange Control Purposes Copy) is being issued separately to the licensee.

[No. 47/INSA/76-77/BLS/2647]
H. L. BAHL, Dy. Chief Controller.

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

रद्द करने का आदेश

का० आ० 4801—परियोजना अधिकारी इन्डो-जर्मन कृषि विकास परियोजना, मंडी (हिमाचल प्रदेश) को ऊर्वरक इत्यादि का आयात करने के लिए 14,07,064 रुपये के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए आयात सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या जी/जे/2337347, दिनांक 2 जनवरी, 1969

प्रदान किया गया था जो जारी होने की तारीख से चार माह के लिए वैध था एवं पहले ही पोतलदान किए गए/पहुंचे हुए माल के लिए भी वैध था । उन्होंने उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि वह सीमा शुल्क सदन, बम्बई में खो गया/अस्थानस्थ हो गया है । आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार परियोजना ने एक आवश्यक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा शुल्क सदन पर पंजीकृत नहीं कराया गया है और कुछ भी उपयोग में लाया गया है । उन्होंने यह भी वचन दिया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट बाद में खोजे जाने पर अथवा मिल जाने पर जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट माल की सूची के साथ-2 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है तथा निदेश देता हूं कि आवेदक को सीमाशुल्क निकासी परमिट की एक अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए । एतद्द्वारा मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट रद्द की जाती है ।

[मिसिल सं० 4/ए० जी०-100/68-69/एमएलI/875]

सुरेन्द्र कुमार बत्ता, उप-मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 9th December, 1976

CANCELLATION ORDER

S.O. 4801.—The Project Officer, Indo-German Agricultural Development Project, Mandi (H.P.) were granted an import C.C.P. No. G/J/2337347 dated the 2nd January, 1969 for cif value of Rs. 14,07,064 for import of fertiliser etc. valid for four months from the date of issue and also valid for goods already shipped/arrived. They have now applied for issue of a duplicate copy of the aforesaid C.C.P. on the grounds that the same has been lost/misplaced at Customs House, Bombay. The Project have furnished the necessary declaration as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid C.C.P. has not been registered with any custom house and not been utilised at all. They have also undertaken to return to the issuing authority the original C.C.P. if traced or found later on.

I am satisfied that the original C.C.P. along with the list of goods has been lost/misplaced and direct that a duplicate C.C.P. should be issued to the applicant. The original C.C.P. is hereby cancelled.

[File No. 4/AG-100/68-69/ML. I/875]

S. K. BATTA, Dy. Chief Controller.

आदेश

का० आ० 4802.—भण्डार नियंत्रक, उत्तरी रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली को प० जर्मनी से डिजल लोकोमोटिव के लिए फालतू पूर्जों का आयात करने के लिए 30,954 रुपए मात्र (तीस हजार नौ सौ चौवन रुपए) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० जी/आर/2459285 दिनांक 27-1-76 प्रदान किया गया था । उन्होंने पूर्वोक्त लाइसेंस (दोनों प्रतियां) की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और उस लाइसेंस के मद्दे माल बम्बई पत्तन पर पहले ही पहुंच गया है । इसके समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि पूर्वोक्त मूल आयात लाइसेंस खो गया है तथा आवेदक को उसकी दोनों अनुलिपि प्रतियां जारी की जानी चाहिएं ।

2. अद्यतन यथा संशोधित आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश सं० 17/55, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग कर अधोहस्ताक्षरी आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची 30(एफ/2 के अन्तर्गत डीजल लोकोमोटिव के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए भण्डार नियंत्रक, उत्तरी रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के नाम से जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० जी/आर/2459285, दिनांक 27-1-76 को रद्द करता है ।

[संख्या 197-सी/रेलवे-75-76/जीएलएस/241]

एल० प्रसाद, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 4802.—Controller of Stores, Northern Railway, Baroda House, New Delhi was granted an Import Licence No. G/R/2459285 dated 27-1-76 for Rs. 30,954 (Rupees thirty thousand nine hundred and fifty four) only for import of spare parts for diesel Locomotives from West Germany. He has applied for issue of a duplicate (both copies) import licence mentioned above on the ground that the original import licence has been lost/misplaced without having been registered with any Customs Authority and the material against the same has already been arrived at Bombay port. In support of this, the applicant has filed an affidavit on stamped paper. I am satisfied that the original import licence mentioned above has been lost and that both duplicate copies thereof should be issued to the applicant.

2. In exercise of powers conferred on me under Clause 9(cc) of the Import Trade (Control) Order No. 17/55 dated 7-12-1955 as amended from time to time the undersigned cancels the import licence No. G/R/2459285 dated 27-1-76 for the import of spare parts for diesel locomotives under ITC Schedule 30(F)/II issued in favour of Controller of Stores, Northern Railway, Baroda House, New Delhi.

[F. No. 197-C/Rly/75-76/GLS/941]

L. PRASAD, Dy. Chief Controller

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4803.—बहु-एकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या एल-11011/49/75-विधि तथा प्रबन्ध तारीख 9 मार्च, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में मुख्य निदेशक श्री एन० कृष्णमूर्ति को सहकारी सोसाइटियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० एल०-11011/49/75-विधि तथा प्रबन्ध]

बी० एल० गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4803.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 of the Multi-Unit Cooperative Societies Act, 1942 (VI of 1942) and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation) No. L-11011/49/75-L&M dated 9-3-1976, the Central Government hereby appoint Shri N. Krishnamurthi, Chief Director in the Ministry of Civil Supplies and Cooperation, as the Central Registrar of Cooperative Societies.

[No. L-11011/49/75-L&M]

B. L. GARG, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4804.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4)

के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिस लाइसेंस के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, लाइसेंसधारी के अनुरोध पर 31 जुलाई 1976 से रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
सीएम/एल-5209 1976-05-14	सर्वश्री राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि०, (राजस्थान सरकार का उद्यम) सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन (राजस्थान)	खेती में उपयोग के लिए जिप्सम (चिरोड़ी)	IS : 6046-1971

[संख्या एमडीडी/55 : 5209]

(Department of Industrial Development)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O.4804.—In pursuance of sub-regulation (4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks Regulation, 1955, as amended from time to time the Indian standards Institution, hereby notices that the licence, particulars of which are given below has been cancelled on the request of the party with effect from 31 July 1976.

SCHEDULE

Licence No. and Date	Name and Address of the licencee	Article/ Process Covered by the licence	Relevent Indian Standard
CM L-5209 1976-05-14	M/s. Rajasthan State Mines & Minerals Ltd., (A Govt. of Rajasthan Undertaking), Suratgarh, Rly. Station, (Rajasthan)	Gynsum of agricultural use.	IS: 6046-1971

[No. MDD/55 : 5209]

नई दिल्ली, 1976-12-06

का०आ० 4805.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन शाब्दिक विवरण और भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1971-08-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS:253 ISI DAIRY SALT	डेरी में प्रयुक्त खाने का नमक	IS : 253-1970 खाने के साधारण नमक की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या और मोनोग्राम के नीचे की ओर शब्द 'डेरी साल्ट' और 'टेबुल साल्ट' दिए गए हैं ।
2.	IS:253 ISI TABLE SALT	खाने का मुक्तवाही नमक		

[सं० सी एम डी/13 : 9]

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1976-12-06

S. O. 4805.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1971-08-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title and of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS:253 ISI DAIRY SALT	Dairy salt	IS:253—1970 Specification for edible common salt (second revision)	The monograms of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the Words 'DAIRY SALT' & 'TABLE SALT' being subscribed under the bottom side of the monograms as indicated in the desings.
2.	IS:253 ISI TABLE SALT	Free Flowing table Salt		

[No. CMD/13:9]

का०आ० 4806.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन शाब्दिक विवरण और भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिह्न उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS:393 ISI	मुहर पैड की स्याही	IS : 393—1968 मुहर पैड की स्याही की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	1970-09-01
2.	IS:2026 ISI	पावर ट्रांसफार्मर	IS: 2026—1962 पावर ट्रांसफार्मरों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	1975-08-16
3.	IS:2403 ISI	साइकिल की चेन	IS : 2403—1964 इस्पात की रोलर चेन और चेन के चक्कों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है ।	1976-01-01
4.	IS:3537 ISI	सामान्य कार्यों के लिए भारतीय मानक रंगों के अनुरूप भीतरी फिनिश देने का तैयार मिश्रित रंग रोगन	IS : 3537—1966 सामान्य कार्यों के लिए भारतीय मानक रंगों के अनुरूप भीतरी फिनिश देने के तैयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ, (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	1973-06-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.		क्रुश से लगने वाला प्राथमिक परत देने का एलुमिनियम रेड आक्साइड वाला तैयार मिश्रित रंगरोगन	IS : 5660—1970 क्रुश से लगने वाला प्राथमिक परत देने का एलुमिनियम रेड आक्साइड वाला तैयार मिश्रित रंगरोगन की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।	1973-06-16

[सं० सी०एम०डी/13 : 9]

S.O. 4806.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notified that the Standard Mark(s) design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mrak	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.		Ink, stamp-pad	IS:393—1968 Specification for ink, stamp-pad (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1970-09-01
2.		Power transformers	IS:2026—1962 Specification for power transformers	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-08-16
3.		Bicycle chains	IS:2403—1964 Specification for transmission steel roller chains and chain wheels	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standrad being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1976-01-01
4.		Ready mixed paint, finishing, interior, for general purposes, to Indian Standard colours	IS:3537—1966 Specification for ready mixed paint, finishing, interior, for general purposes, to Indian Standard colours	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1973-06-16
5.		Ready mixed paint, brushing aluminium red oxide primer	IS:5660—1970 Specification for ready mixed paint, brushing, aluminium red oxide primer	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1973-06-16

[No. CMD/ 13:9]

का०आ० 4807.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-3405 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, फर्म द्वारा लाइसेंस वापस कर देने के कारण उसके अनुरोध पर 16 अक्तूबर 1976 से रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सी एम/एल-3405 5-5-1973	सर्वश्री एपीजे स्ट्रक्चरल्स लि०, डाकघर राजबंध, जिला बर्दवान, (पं० बंगाल) कार्यालय : 47 हाइड रोड, कलकत्ता-700027	द्रवित पेट्रोलियम गैसों के भंडारण और परिवहन के लिए 26.9 लिटर और 33 लिटर जल समाई वाले वेल्डकृत अल्पकार्बन इस्पात के गैस सिलेण्डर	IS : 3196-1974 अल्पदाब द्रवित पेट्रोलियम गैसों के लिए 5 लिटर से अधिक जल समाई वाले वेल्डकृत अल्प कार्बन इस्पात सिलेण्डर की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[सं० सी० एम० डी०/55: 3405]

S. O. 4807.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards (Certification Marks), Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L—3405 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 16 October, 1976 on account of surrendering the licence at the firm's request:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and date	Name & Address of the Licensee	Article/Process the Licenses Covdered by Cancelled	Relevant Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	CM/L—3405 5-5-1973	M/s. Apcejay Structurals Ltd., P.O. Rajbandh, Distt. Burdwan (W. Bengal) having their office at 47, Hide Road, Calcutta-700027.	Welded low carbon steel gas cylinders of 26.9 litres and 33 litres water capacity for the storage and transportation of liquefiable petroleum gases	IS : 3196-1974 Specification for Welded low carbon steel gas cylinder exceeding 5 litres water capacity for low pressure liquefiable gases (Second Revision)

[No. CMD/55 : 3405]

का० आ० 4808.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के, उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय, मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई प्रमाणन चिह्न लगाने की फीसें अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई हैं और ये फीसें उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	मुहर पैड की स्याही	IS : 393—1968 मुहर पैड की स्याही की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक लिटर	3 पैसे	1970-09-01
2.	पावर ट्रांसफार्मर	IS : 2026—1962 पावर ट्रांसफार्मरों की विशिष्टि	एक के वी ए	(1) पहली 20000 इकाइयों के लिए 25 पैसे प्रति इकाई ; (2) 20001वीं से 60000 तक इकाइयों के लिए 10 पैसे प्रति इकाई; और (3) 60001वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए 5 पैसे प्रति इकाई ।	1975-08-16
3.	साइकिल की चैन	IS : 2403—1964 इस्पात की रोलर चेस और चेन के चक्कों की विशिष्टि	एक चैन	(1) पहली 200000 इकाइयों के लिए एक पैसा प्रति इकाई; (2) 200001 और उससे ऊपर की इकाइयों के लिए 1/2 पैसा प्रति इकाई ।	1976-01-01

1	2	3	4	5	6
4.	सामान्य कार्यों के लिए भारतीय मानक रंगों के अनुरूप भीतरी फिनिश देने का तैयार मिश्रित रंगरोगन	IS : 3537—1966 सामान्य कार्यों के लिए भारतीय मानक रंगों के अनुरूप भीतरी फिनिश देने के तैयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि	एक लिटर	0.6 पैसे	1973-06-16
5.	क्षुण से लगने वाला प्राथमिक परत देने का एलुमिनियम रेड आक्साइड वाला तैयार मिश्रित रंग रोगन	IS : 5660—1970 क्षुण से लगने वाला प्राथमिक परत देने का एलुमिनियम रेड आक्साइड वाला तैयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि	एक लिटर	0.5 पैसे	1973-06-16

[सं० सी० एम० डी०/13 : 10]

S.O.4808.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products, details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	Ink, stamp-pad	IS : 393—1968 Specification for ink, stamp-pad (first revision)	One litre	3 Paise	1970-09-01
2.	Power transformers	IS : 2026—1962 Specification for power transformers	One KVA	(i) 25 Paise per unit for the first 20 000 units; (ii) 10 Paise per unit for the 20 001st unit to 60 000 units and (iii) 5 Paise per unit for the 60 001st units and above.	1975-08-16
3.	Bicyle chains	IS : 2403—1964 Specification for transmission steel roller chains and chain wheels	One Chain	(i) 1 Paise per unit for the first 200000 units (ii) ½ Paisa per unit for the 20 0001st units and above.	1976-01-01
4.	Ready mixed paint, finishing, interior, for general purposes, to Indian Standard colours	IS : 3537—1966 Specification for ready mixed paint, finishing, interior, for general purposes, to Indian Standard colours.	One litre	0.5 Paise	1973-06-16
5.	Ready mixed paint, brushing, aluminium red oxide primer	IS : 5660—1970 Specification for ready mixed paint, brushing, aluminium red oxide primer.	One Litre	0.5 Paise	1973-06-16

[No. CMD/13 : 10]

का० आ० 4809.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (2) के अनुसार, अधिसूचित किया जाता है कि साधारण नमक खाने के मुक्तिवाही नमक के मानक चिह्न जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, भारतीय मानक वापस ले लिये जाने के कारण 1971-07-3 से निरस्त हो गए हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	भारत के राजपत्र अधिसूचना की एस०ओ० संख्या और तिथि जिसमें मानक चिह्न के निर्धारण की सूचना छपी थी ।
1	2	3	4
1.	मक्खन और पनीर उद्योग के लिए साधारण नमक	IS : 1845—1961 मक्खन और पनीर उद्योग के लिए साधारण नमक की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1962-10-13 में एस० ओ० 3098 दिनांक 1962-10-01 के अन्तर्गत प्रकाशित
2.	खाने का मुक्तिवाही नमक	IS : 2035—1961 खाने के मुक्तिवाही नमक की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1966-04-09 में एस० ओ० 1079 दिनांक 1966-03-25 के अन्तर्गत प्रकाशित

[सं० सी० एम० डी० 13 : 9]

S.O. 4809.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Standard Marks for common/free-flowing table sales, details of which are given in the following Schedule, have been rescinded with effect from 1971-07-31 due to withdrawal of the Indian Standards.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	S.O. No. & Date of Gazette Notification in which Standard Mark was specified
1	2	3	4
1.	Common salt for butter and cheese industry	IS : 1845-1961 Specification for common salt for butter and cheese industry.	S.O. 3098 dated 1962-10-01 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1962-10-13
2.	Free-flowing table salt	IS : 2035-1961 Specification for free-flowing table salt	S.O. 1079 dated 1966-03-25 published in Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) deted 1966-04-09

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 4810.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दिए खाने के साधारण नमक और मुक्तप्रवाही नमक की प्रति इकाई प्रमाणन चिह्न लगाने की फीसें अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई हैं और ये फीसें 1971-08-01 से लागू होंगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पादों की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डेरी में प्रयुक्त खाने का नमक	IS : 253-1970 खाने के साधारण नमक की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 5.0
2.	खाने का मुक्तप्रवाही नमक		एक मीटरी टन	रु० 2.00

[सं० सी एम डी/13 : 10]

S.O. 4810.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for dairy salt and free-flowing table sal details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from 1971-08-01

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dairy salt	IS : 253-1970 Specification for edible common salt (second revision)	One Tonne	Rs. 5.00
2.	Free-flowing table salt		One Tonne	Rs. 2.00

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, 1976-12-07

का० आ० 4811.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि IS : 1988-1962 पेंचदार टोटियों की विशिष्टि जिसके ब्यौरे एस०ओ० 3100, दिनांक 1962-10-01 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1962-10-13 में छपे थे, वापस कर ली गई है और 1976-09-01 से रद्द मानी जाए क्योंकि यह मानक अब मानकों की दो रिसीज. पेंचदार टोटियों की तकनीकी सप्लाई शर्तें तथा विभिन्न प्रकार की टोटियों की माप संबंधी अपेक्षाएं के अधीन प्रकाशित हो रहा है ।

[सं० सीएमडी/13 : 7]

New Delhi, the 1976-12-07

S. O. 4811.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time it is, hereby, notified that IS : 1988-1962 Specification for screwing taps, details of which were published under notification number S.O. 3100 dated 1962-10-01, in the Gazete of India, Part-II,Section-3, Sub-section (ii) dated 1962-10-13, has been withdrawn and stands cancelled with effect from 1976-09-01 as this standard has been split up into a series of standards covering technical supply conditions for screwing taps and dimensional requirements of various type of taps under separate Indian Standard Specifications.

[No. CMD/13 : 7]

का० आ० 4812.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1976-01-10 में एसओ 176 दिनांक 1975-12-15 के अधीन प्रकाशित तत्कालीन उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना के आंशिक संशोधन के रूप में भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पटसन के उर्वरक भरने के परतदार बोरों संबंधी मानक चिह्न में कुछ परिवर्तन किया गया है । इस परिवर्तित मानक चिह्न की डिजाइन तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक तथा शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दी गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1976-11-01 से लागू होगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BAG ISI IS:7406	उर्वरक भरने के पटसन के परतदार बोरे	IS : 7406-1974 उर्वरक भरने के पटसन के परतदार बोरों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें IS शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर शब्द "बैग" और मोनोग्राम के नीचे की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।

[सं० सीएमडी/13 : 9]
ए० बी० राव, उपमहानिदेशक

S. O. 4812.—In partial modification of the then Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) (Indian Standards Institution) notification number S.O. 176 dated 1975-12-15 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-01-10, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark for laminated jute bags for packing fertilizers has been revised. The revised design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the following Schedule.

This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1976-11-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	BAG ISI IS:7406	Laminated jute bags for packing fertilizers	IS : 7406-1974 Specification for laminated jute bags for packing fertilizers	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters, 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in col. (2); the words 'BAG' being superscribed on the top side and the number of the Indian Standard being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]
A.B. RAO, Dy. Director General

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4813.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मलायाकोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मोरवी हाउस जामनगर रोड राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : सिधपुर जिला : मेहसाना राज्य : गुजरात

गांव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र		
		एच०	ए०	वर्ग मीटर
1	2		3	
दाभी	348	0	18	72
	339	0	07	50
	344	0	12	00
	340	0	04	05
	346	0	00	42
	341	0	03	30
	342	0	07	22
	268	0	19	14
	267	0	10	23
	248	0	00	10
	274/1	0	15	48
	274/2	0	03	67
	245	0	11	47
	239	0	10	10
	240	0	22	61
	220	0	07	00
	159	0	04	77
	160	0	12	24
	147	0	03	93
	146	0	20	23
	144	0	20	14
	145	0	00	13
	141	0	10	69
	140	0	16	17
	103	0	20	82
	105	0	19	89
सुनक	174/2	0	05	74
	175	0	03	78
	171	0	00	10
	1746/1	0	15	83
	169/1	0	02	60
	169/2	0	07	77
	178	0	21	70
	268	0	17	19
	269	0	03	78
	270	0	12	30
	267	0	00	10
	237	0	15	95
	235/1	0	03	40
	235/2	0	09	30
	233	0	11	10
	232	0	11	47
	214	0	01	26
	327/3	0	07	59
	327/4	0	07	53
	327/2	0	05	01
	328/1	0	00	12
	329/1	0	04	29
	333/2	0	04	95
	333/1	0	00	32
	330	0	07	29
	332	0	02	60
	336	0	06	87
	337	0	03	41
	338	0	09	45
	345	0	28	04
	348	0	21	94
	349	0	00	69
तुंदव	798	0	05	64
	818	0	11	16
	817	0	15	00
	816	0	00	32
	822	0	16	32
	823	0	07	50
	849/1	0	05	64
	849/2	0	12	50
	857	0	06	50
	848/1	0	03	16
	858	0	00	80
	870/2	0	04	50
	870/1	0	06	32
	871	0	11	00
	873	0	09	64
	875	0	16	00
	876/B	0	12	00
	877	0	06	50
	37	0	00	10
	36/1	0	19	16

1	2	3		
तुंदव—जारी	36/2	0	04	80
	43	0	08	00
	42/1–B	0	01	50
	48/1	0	15	50
	44	0	00	85
	46	0	20	00
	57	0	11	00
	58	0	10	32
	59/1	0	05	00
	59/2	0	06	50
	61	0	00	32
	60/1 5	0	10	50
	60/1 4	0	12	64
	60/1 3	0	00	32
	83	0	13	32
	82	0	00	40
	78	0	09	50
	79	0	09	50
	77/1	0	02	50
	77/3	0	11	00
	101/2	0	15	00
	101/1	0	12	80
	120/1	0	00	50
	120/2	0	07	80
	122/1	0	13	50
	123	0	06	00
	149	0	10	50
	148	0	19	32
	146	0	06	64
	147	0	29	00
	188	0	00	64
	187/1	0	22	00
	187/2	0	03	32
	190	0	12	30
	197/3	0	11	32
	197/2	0	26	50
	197/1	0	08	80
	196	0	08	00
वर्बदा	731	0	00	25
	734	0	16	82
	732	0	14	00
	733	0	10	00
	717	0	15	80
	718	0	01	00
	716/1	0	10	50
	666/1	0	09	50
	668/1	0	00	16
	665	0	07	50
	664/2	0	08	80
	664/1	0	15	12

1	2	3		
वर्बदा—जारी	663/2	0	16	00
	660/1	0	00	32
	29/1	0	08	50
	29/2	0	02	16
	31/5	0	00	16
	30	0	11	20
	28/2	0	11	16
	28/1	0	07	32
	27/1	0	10	00
	27/2	0	00	16
	26/2	0	05	00
	26/3	0	14	00
	25/3	0	19	12
	53	0	25	32
	56/1	0	00	16
	55	0	04	96
	54	0	04	00
	51	0	13	54
	85/6	0	23	40
	87/4	0	03	04
	88/13	0	09	60
	88/11	0	06	07
	88/4	0	19	70
	88/5	0	04	08
	88/6	0	02	10
	160	0	24	12
	161	0	03	06
	159	0	14	58
	112	0	00	75
	113	0	09	60
	138/1	0	10	80
	138/2	0	05	76
	137/2	0	07	92
	137/4	0	07	93
	136/2	0	02	32
	139	0	13	60
	140	0	14	22
	141	0	03	69
	142	0	11	70
	143/1	0	09	90
	143/2	0	06	75
विसोल	53	0	22	50
	54/2	0	03	50
	51	0	16	00
	57	0	01	16
	49/2	0	10	50
	49/1	0	11	32
	47	0	16	40
	46/1	0	13	80
	45/1	0	01	00
	34/1	0	00	64
	34/2	0	08	00

1	2	3		
विसोल—जारी	35	0	12	00
	30/1	0	02	32
	30/2	0	15	50
	36	0	09	00
	37	0	01	32
	28	0	18	80
	24	0	00	80
	21	0	17	80
	20	0	10	50
	19/1	0	06	50
	19/2	0	12	16
	7/3	0	15	32
	7/2	0	04	00
	5	0	10	50
	4/3	0	02	50
कनेसरा	260	0	01	50
	259/1A	0	04	32
	259	0	06	50
	259/1B	0	07	02
	262/1	0	08	10
	263	0	06	20
	263/1	0	15	12
	268/1	0	03	96
	269/5	0	01	69
	268/2	0	07	20
	264	0	00	05
	264/1	0	12	16
	267	0	01	20
	266	0	18	25
	275	0	11	16
	232/1	0	03	64
	231	0	14	64
	230	0	14	40
	229	0	21	60
	228	0	07	12
	227	0	09	10
	204	0	03	80
	207	0	19	08
	206	0	13	68
	162	0	08	60
	161	0	12	65
	159/1	0	07	09
	158	0	08	60
	145	0	17	70
	146	0	00	06
	88/2	0	02	53
	87	0	16	19
	147	0	04	30
	86	0	19	28
	84	0	00	25
	85	0	07	60
	85/1	0	08	40
	82	0	08	61

1	2	3		
खोलवडा	64	0	22	00
	78	0	53	27
	78/2	0	15	68
	34	0	14	16
	33	0	01	01
	101	0	00	75
	103	0	06	07
	106/1-पी	0	33	39
	106/2-पी	0	36	40
	140	0	01	76
	139	0	20	23
	137	0	15	43
	136	0	08	34
	135	0	00	05
	123	0	25	29
	124	0	02	03
	690	0	00	80
	689	0	25	29
	687	0	00	30
	688	0	15	68
	667	0	27	32
	684	0	09	11
	683	0	09	11
	682	0	08	10
	681	0	17	20
	680	0	18	21
	615	0	11	38
सिधपुर	88	0	08	09
	89	0	44	23
	104	0	04	05
	106	0	16	70
	118	0	04	80
	143/13	0	10	60
	143/12-ए	0	07	08
	143/11	0	08	60
	143/10	0	00	50
	143/5	0	05	55
	143-ए/6	0	06	80
	143/4-बी	0	06	57
	143/3	0	10	62
	143/1-ए	0	01	80
	143/1-बी	0	10	30
	181	0	11	38
	182	0	02	62
	179-बी	0	06	30

1	2	3		
सिध्रपुर—जारी	178/4	0	08	60
	178/1—ए	0	01	75
	178/2—बी	0	07	08
	286/1	0	12	65
	287	0	14	17
	288/1	0	03	50
	288/2	0	11	40
	293	0	02	62
	292	0	12	90
	291	0	07	85
	290	0	01	01
	308	0	06	57
	309/5	0	00	40
	309/4	0	04	30
	309/3	0	13	65
	309/2	0	08	60
	327/1—ए	0	02	62
	327/1—बी	0	06	60
	328	0	07	08
	329/2	0	07	75
	329/1	0	08	09
	336	0	09	60
	335	0	01	26
	334/2	0	10	95
	333	0	10	87
	343	0	03	75
	340/2	0	02	62
	340/1	0	05	06
	341	0	07	33
	342	0	04	80
	354	0	10	12
	355	0	00	75
	353	0	07	08
	351/1	0	09	11
	350	0	20	23
	407	0	15	18
	400	0	00	75
	406	0	32	37
	402/1	0	00	59
	404	0	06	57
	403	0	24	28
	479/2	0	07	85
	478	0	28	95
	466	0	02	02
	477	0	07	08
	476	0	02	77
	475/1	0	02	60
	475/2	0	02	52
	468	0	04	05
	470	0	11	38
	471/2	0	02	62
	471/1	0	01	75
सुजानपुर . .	344	0	06	30
	345/पी	0	15	18

1	2	3		
सुजानपुर—जारी	343/1	0	00	40
	346/2	0	15	18
	341/1	0	04	30
	341/2	0	01	51
	346/1	0	14	17
	363/1	0	01	01
	364/2	0	04	30
	364/1	0	11	90
	374	0	25	29
	368/1	0	04	05
	369	0	06	80
	370	0	04	30
	305	0	13	15
	306	0	14	42
	316/1	0	00	06
	308/2	0	08	09
	309	0	11	88
	311/2—पी	0	00	10
	282/2	0	21	25
	282/3	0	07	08
	281/3	0	00	06
	281/1	0	02	02
	140	0	27	32
	141	0	11	13
	139	0	08	09
	138	0	03	04
	137	0	07	08
	136	0	24	77
	104/1	0	32	37
	108	0	16	19
	105	0	04	05
	106	0	25	27
	100/8	0	13	12
	100/6	0	08	59
	106	0	25	27
	100/8	0	13	12
	100/6	0	08	59
	100/7	0	04	05
	100/3	0	10	62
	100/2	0	03	04
सेद्राना . .	997	0	01	51
	1128	0	04	05
	1129	0	00	50

[सं० 12020/9/76-प्रोडक्शन-I]

MINISTRY OF PETROLIUM

New Delhi, the 3rd December, 1976

S.O. 4813.—Whereas it appears to the Centra Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/ Mathura Pipeline Project, "Morvi House" Jamnagar Road, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Sidhpur District : Mehsana State: Gujarat

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2		3	
DABHI	348	0	18	72
	339	0	07	50
	344	0	12	00
	340	0	04	05
	346	0	00	42
	341	0	03	30
	342	0	07	22
	268	0	19	14
	267	0	10	23
	248	0	00	10
	274/1	0	15	48
	274/2	0	03	67
	245	0	11	47
	239	0	10	00
	240	0	22	61
	220	0	07	00
	159	0	04	77
	160	0	12	24
	147	0	03	93
	146	0	20	23
	144	0	20	14
	145	0	00	13
	141	0	10	69
	140	0	16	17
	103	0	20	82
	105	0	19	89
SUNAK	174/2	0	05	74
	175	0	03	78
	171	0	00	10
	176/1	0	15	83
	169/1	0	02	60
	169/2	0	07	77
	178	0	21	70
	268	0	17	19
	269	0	03	78
	270	0	12	30
	267	0	00	10
	237	0	15	95
	235/1	0	03	40
	235/2	0	09	30
	233	0	11	10
	232	0	11	47
	214	0	01	26
	327/3	0	07	59
Sunak (contd.)	327/4	0	07	53
	327/2	0	05	01
	328/1	0	00	12
	329/1	0	04	29
	333/2	0	04	95
	333/1	0	00	32
	330	0	07	29
	332	0	02	60
	336	0	06	87
	337	0	03	41
	338	0	09	45
	345	0	28	04
	348	0	21	94
	349	0	00	69
TUNDAV	798	0	05	64
	818	0	11	16
	817	0	15	00
	816	0	00	32
	822	0	16	32
	823	0	07	50
	849/1	0	05	64
	849/2	0	12	50
	857	0	06	50
	848/1	0	03	16
	858	0	00	80
	870/2	0	04	50
	870/1	0	06	32
	871	0	11	00
	873	0	09	64
	875	0	16	00
	876/B	0	12	00
	877	6	06	50
	37	0	00	10
	36/1	0	19	16
	36/2	0	04	80
	43	0	08	00
	42/1-B	0	01	50
	48/1	0	15	50
	44	0	00	85
	46	0	20	00
	57	0	11	00
	58	0	10	32
	59/1	0	05	00
	59/2	0	06	50
	61	0	00	32
	60/1 5	0	10	50
	60/1 4	0	12	64
	60/1 3	0	00	32
	83	0	13	32
	82	0	00	40
	78	0	09	50
	79	0	09	50
	77/1	0	02	50
	77/3	0	11	00
	101/2	0	15	00
	101/1	0	12	80
	120/1	0	00	50
	120/2	0	07	80
	122/1	0	13	50
	123	0	06	00
	149	0	10	50
	148	0	19	32

1	2	3		
Tundav (contd.)	146	0	06	64
	147	0	29	00
	188	0	00	64
	187/1	0	22	00
	187/2	0	03	32
	190	0	12	30
	197/3	0	11	32
	197/2	0	26	50
	197/1	0	08	80
	196	0	08	00
VARVADA	731	0	00	25
	734	0	16	82
	732	0	14	00
	733	0	10	00
	717	0	15	80
	718	0	01	00
	716/1	0	10	50
	666/1	0	09	50
	668/1	0	00	16
	665	0	07	50
	664/2	0	08	80
	664/1	0	15	12
	663/2	0	16	00
	660/1	0	00	32
	29/1	0	08	50
	29/2	0	02	16
	31/5	0	00	16
	30	0	11	20
	28/2	0	11	16
	28/1	0	07	32
	27/1	0	10	00
	27/2	0	00	16
	26/2	0	05	00
	26/3	0	14	00
	25/3	0	25	32
	53	0	25	32
	56/1	0	00	16
	55	0	04	96
	54	0	04	00
	51	0	13	54
	85/6	0	23	40
	87/4	0	03	04
	88/13	0	09	60
	88/11	0	06	07
	88/4	0	19	70
	88/5	0	04	08
	88/6	0	02	10
	160	0	24	12
	161	0	03	06
	159	0	14	58
	112	0	00	75
	113	0	09	60
	138/1	0	10	80
	138/2	0	05	76
	137/2	0	07	92
	137/4	0	07	93
	136/2	0	02	32
	139	0	13	60
	140	0	14	22
	141	0	03	69
	142	0	11	70
	143/1	0	09	90
	143/2	0	06	75
VISOL	53	0	22	50
	54/2	0	03	50

1	2	3		
Visol (contd.)	51	0	16	00
	57	0	01	16
	49/2	0	10	50
	49/1	0	11	32
	47	0	16	40
	46/1	0	13	80
	45/1	0	01	00
	34/1	0	00	64
	34/2	0	08	00
	35	0	12	00
	30/1	0	02	32
	30/2	0	15	50
	36	0	09	00
	37	0	01	32
	28	0	18	80
	24	0	00	80
	21	0	17	80
	20	0	10	50
	19/1	0	06	50
	19/2	0	12	16
	7/3	0	15	32
	7/2	0	04	00
	5	0	10	50
	4/3	0	02	50
KANASARA	260	0	04	50
	259/1-A	0	04	32
	259	0	06	50
	259/1-B	0	07	02
	262/1	0	08	10
	263	0	06	20
	263/1	0	15	12
	268/1	0	03	96
	268/5	0	01	69
	268/2	0	07	20
	264	0	00	05
	264/1	0	12	16
	267	0	01	20
	266	0	18	25
	275	0	11	16
	232/1	0	03	64
	231	0	14	64
	230	0	14	40
	229	0	21	60
	228	0	07	12
	227	0	09	10
	204	0	03	80
	207	0	19	08
	206	0	13	68
	162	0	08	60
	161	0	12	65
	159/1	0	07	09
	158	0	08	60
	145	0	17	70
	146	0	00	06
	88/2	0	02	53
	87	0	16	19
	147	0	04	30
	86	0	19	28
	84	0	00	25
	85	0	07	60
	85/1	0	08	40
	82	0	08	61

1	2	3		
KHOLVADA	64	0	22	00
	78	0	53	27
	78/2	0	15	68
	34	0	14	16
	33	0	01	01
	101	0	00	75
	103	0	06	07
	106/1-P	0	33	39
	106/2-P	0	36	40
	140	0	01	76
	139	0	20	23
	137	0	15	43
	136	0	08	34
	135	0	00	05
	123	0	25	29
	124	0	02	03
	690	0	00	80
	689	0	25	29
	687	0	00	30
	688	0	15	68
	667	0	27	32
	684	0	09	11
	683	0	09	11
	682	0	08	10
	681	0	17	20
	680	0	18	21
	615	0	11	38
SIDHPUR	88	0	08	09
	89	0	44	23
	104	0	04	05
	106	0	16	70
	118	0	04	80
	117	0	20	00
	116	0	00	20
	143/13	0	10	60
	143/12-A	0	07	08
	143/10	0	00	50
	143/11	0	08	60
	143/5	0	05	55
	143/6	0	06	80
	143/4-B	0	06	57
	143/3	0	10	62
	143/1-A	0	01	80
	143/1-B	0	10	30
	181	0	11	38
	182	0	02	62
	179	0	06	30
	178/4	0	08	60
	178/1	0	01	75
	178/2	0	07	08
	286/1	0	12	65
	287	0	14	17
	288/1	0	03	50
	288/2	0	11	40
	293	0	02	62
Sidhpur (contd.)	292	0	12	90
	291	0	07	85
	290	0	01	01
	308	0	06	57
	309/5	0	00	40
	309/4	0	04	30
	309/3	0	13	65
	309/2	0	08	60
	327/1-A	0	02	62
	327/1/-B	0	06	60
	328	0	07	08
	329/2	0	07	75
	329/1	0	08	09
	336	0	09	60
	335	0	01	26
	334/2	0	10	95
	333	0	10	87
	343	0	03	75
	340/2	0	02	62
	340/1	0	05	06
	341	0	07	33
	342	0	04	80
	354	0	10	12
	355	0	00	75
	353	0	07	08
	351/1	0	09	11
	350	0	20	23
	407	0	15	18
	400	0	00	75
	406	0	32	37
	402/1	0	00	59
	404	0	06	57
	403	0	24	28
	479/2	0	07	85
	478	0	28	95
	466	0	02	02
	477	0	07	08
	476	0	02	77
	475/1	0	02	60
	475/2	0	02	52
	468	0	04	05
	470	0	11	38
	471/2	0	02	62
	471/1	0	01	75
SUJANPUR	344	0	06	30
	345/P	0	15	18
	343/1	0	00	40
	346/2	0	15	18
	341/1	0	04	30
	341/2	0	01	51
	346/1	0	14	17
	363/1	0	01	01
	364/2	0	04	30
	364/1	0	11	90
	374	0	25	29
	368/1	0	04	05
	369	0	06	80
	370	0	04	30
	305	0	13	15

1	2	3		
Sujanpur (contd.)	306	0	14	42
	316/1	0	00	06
	308/2	0	08	09
	309	0	11	88
	311/2	0	00	10
	282/2	0	21	25
	283/3	0	07	08
	281/3	0	00	06
	281/1	0	02	02
	140	0	27	32
	141	0	11	13
	139	0	08	09
	138	0	03	04
	137	0	07	08
	136	0	24	77
	104/1	0	32	37
	108	0	16	19
	105	0	04	05
	106	0	25	27
	100/8	0	13	12
	100/6	0	08	59
	100/7	0	04	05
	100/3	0	10	62
	100/2	0	03	04
SEDRANA	997	0	01	51
	1128	0	04	05
	1129	0	00	50

[No. 12020/9/76—Prod—I]

का० आ० 4814.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 5668 तारीख 28-11-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

रुद्रसागर-लाकवा ट्रंक पाइप लाइन

राज्य : असम जिला : शिसागर तालुक : लाहचरा

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्तर	ऐरे	सेन्ती ऐरे
धेकेरी गांव	273 ख	0	0	27
	391 ख	0	0	27
	797 ख	0	2	41
	392 ख	0	0	27
	393 ख	0	5	08
	791	0	1	34
	795	0	4	28

[सं० 12020/5/76—एल एंड एल/I]

S.O. 4814.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 5668 dated 28-11-75 under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-Section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by Sub-Section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting it the Central Government vest in this date of publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Rudrasagar to Lakwa Trunk Pipeline

State : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Hahchara

Village	Survey No.	Hector	Are	Centi-are
Dhekeri	273 Kha	0	0	27
	391 Kha	0	0	27
	797 Kha	0	2	41
	392 Kha	0	0	27
	393 Kha	0	5	08
	791	0	1	34
	793	0	4	28

[No. 12020/5/76-Prod-I]

का० आ० 4815.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 5670 तारीख 28-11-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गोलिकी जी०जी० एस० नम्बर 3 से गोलिकी

जी०जी० एस० नम्बर 2 तककी पाइप लाइन

राज्य : असम जिला:शिवसागर, तालुक : आठखेल

ग्राम	सर्वेनम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी ऐरे
स्मोयपुर ग्रान्त	44ग	0	33	05
	44ङ	0	10	43
	47ग	0	13	38
	61ख	0	0	27
	64ग	0	0	94
	65ग	0	12	98
	74छ	0	18	06
	74झ	0	23	41
	79ग	0	2	94
	89ग	0	0	94

[सं० 12020/5/76-एल एंड एल II]

S.O 4815.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 5670 dated 28-11-75 under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under Sub-Section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by Sub-Section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki GGS. No. 3 to Geleki GGS. No. 2.
State : Assam Dist. : Sibsagar Taluk : Athkhel

Village	Survey No.	Hector	Are	Centiare
Smithpur Grant	44 Ga	0	33	05
	44 Unga	0	10	43
	47 Ga	0	13	38
	61 Kha	0	0	27
	64 Ga	9	0	94
	65 Ga	0	12	98
	74 Sa	0	18	06
	74 Jha	0	23	41
	79 Ga	0	2	94
	89 Ga	0	0	94

[No. 12020/5/76-Prod-II]

का०आ० 4816.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० तारीख द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तालुका : मेहसाना जिला : मेहसाना राज्य : गुजरात

गांव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र		
		एच	ए	वर्ग मीटर
रामपुरा	493/1	0	13	95
	494/1	0	12	00
	498	0	01	00
	497	0	01	80
	496	0	04	40
	495	0	08	55
	518	0	21	25
	519	0	14	96
	520	0	16	49
	521	0	20	68
	522	0	22	89
	523	0	03	30
	524	0	11	74
	527	0	10	89
	528	0	15	67
मदासा	1169	0	23	27
	1168	0	22	26
पालज (जीवपुरा)	194			
	(1175)	0	00	02
	193			
	(1174)	0	11	13
	192			
	(1173)	0	14	16
	191			
	(1172)	0	04	05
	207			
	(1188)	0	28	33
	208			
	(1189)	0	12	64
	210ए			
	(1191 पी)	0	30	35
	210 बी			
	(1191 पी)	0	05	06
	211			
	(1192)	0	40	47
	166			
	(1147)	0	20	23
	167			
	(1148)	0	26	30
	168			
	(1149)	0	68	80
	169			
	(1150)	0	04	05
	150			
	(1131)	0	40	47
पालज जीवपुरा (समाप्त)	149			
	(1130)	0	38	45
	127			
	(1108)	0	43	50
	126			
	(1107)	0	20	23
	125			
	(1106)	0	50	59
	123			
	(1104)	0	01	45

[सं० 12020/9/76-प्रोडक्शन-II]

S. O. 4816.—Whereas by a notification of the Govt of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No————Dated————under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its Intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act. submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines:

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the CentralGovernment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka : Mehsana District : Mehsana State : Gujarat

Village	Survey No.	Extent		
		H	A	Sq. m
Rampura	493/1	0	13	95
	494/1	0	12	00
	498	0	01	00
	497	0	01	80
	496	0	04	40
	495	0	08	55
	518	0	21	25
	519	0	14	96
	520	0	16	49
	521	0	20	68
	522	0	22	89
	523	0	03	30
	524	0	11	74
	527	0	10	89
	528	0	15	67

1	2	3		
Nadasa	1169	0	23	27
	1168	0	22	26
Palaj (Jivapura)	194			
	(1175)	0	00	02
	193			
	(1174)	0	11	13
	192			
	(1173)	0	14	16
	191			
	(1172)	0	04	05
	207			
	(1188)	0	28	33
	208			
	(1189)	0	12	64
	210-A			
	(1191-P)	0	30	35
	210-B			
	(1191-P)	0	05	06
	211			
	(1192)	0	40	47
	166			
	(1147)	0	20	23
	167			
	(1148)	0	26	30
	168			
	(1149)	0	68	80
	169			
	(1150)	0	04	05
	150			
	(1131)	0	40	47
	149			
	(1130)	0	38	45
	127			
	(1108)	0	43	50
	126			
	(1107)	0	20	23
	125			
	(1106)	0	50	59
	123			
	(1104)	0	01	55

[No. 12020/9/76-Prod-II]

का० आ० 4817.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया-कोयाली, मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मोरवी हाऊस जामनगर रोड, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका:वीरमगम जिला अहमदाबाद राज्य गुजरात

गांव	क्र०संख्या	क्षेत्र		
		एच०	ए०	वर्ग मीटर
1	2	3		4
सचना	837पीए	0	19	50
	837पीबी	0	32	00
	844	0	03	50
	845	0	46	70
	973	0	11	00
	1130	0	12	10
	1025	0	10	50
जखवाडा	688	0	17	65
	687	0	16	10
	569	0	09	15

[सं० 12020/9/76-प्रोडक्शन-III]

S. O. 4817.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided That any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/ Mathura Pipeline Project, "Morvi House" Jamnagar Road" Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

TALUKA: VIRAMGAM DISTRICT: AHMEDABAD STATE: GUJARAT

Village	S. No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2		3	
Sachana	837 PA	0	19	50
	837 PB	0	32	00
	844	0	03	50

1	2	3		
	845	0	46	70
	973	0	11	00
	1130	0	12	10
	1025	0	10	50
JAKHWADA	688	0	17	65
	687	0	16	10
	569	0	09	15

[No. 12020/9/76-Prod.III]

का० आ० 4818.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 5376 तारीख 10-12-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गैलिकी कुप नम्बर जी० 48 से गेलिकी कुप नम्बर 16 (जी० आर०) तक की पाइपलाइन

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुक : आठखेल

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्तिऐरे
गेलिकी ग्रान्त	77ख	0	7	09
नम्बर 1	75ख	0	8	43

[सं० 12020/5/76-एल०एण्ड एस०-III]

S.O. 4818.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 5376 dated 10-12-75 under Sub-Section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-Section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki drill site No. G. 48 to 16 (G. R.)
STATE : ASSAM DIST: SIBSAGAR TALUK: ATHKHEL

Village	Survey No.	hector	are	Contiare
Geleki Grant No. 1.	77 Kha	0	7	09
	75 Kha	0	8	43

[No. 12010/5/76-Prod.III]

का० आ० 4819.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 983 तारीख 18-2-76 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालूका : वदोदरा जिला : वदोदरा राज्य : गुजरात

गांव	सर्वेक्षण सं०	क्षेत्र		
		एच०	ए०	वर्ग मीटर
कराचिया	365	0	05	30
	363	0	00	20
	354/1	0	03	85
	368	0	01	15
	373	0	11	40

[सं० 12017/6/74-एल० एण्ड एल०]

S. O. 4819.— Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 983 dated 18-2-76 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And Further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, that Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation limited free from all encumberances.

SCHEDULE

TALUKA: VADODARA DISTRICT: VADODARA

STATE : GUJARAT

Village	Survey No.	Extent		
		H. A.	A	Sq. M
Karachia . .	365	0	05	30
	363	0	00	20
	354/1	0	03	85
	368	0	01	15
	373	0	11	40

[No. 12017/6/74-L & L]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का०आ० 4820.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० 9 की फ्लो लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

2. और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

3. अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

4. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मलायाकोलाली/मथुरा पाइपलाइन प्रौजेक्ट, "डोली"-33-बी, हरिहर सोसाइटी, कालावद रोड, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

5. ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

आर० ओ० यू० : कूप नं० 9 की फ्लो लाइन तक

राज्य गुजरात जिला : केरा तालुका : मातर

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टेयर	एआरई	सेंटियर
नवागाम	62	0	00	10
	68	0	01	40
	69	0	01	75
	84	0	04	00
	83/2	0	04	75
	83/3	0	02	00
	93/4	0	01	75
	81/2	0	00	10
	80	0	05	75
	76/1/पी	0	06	50
	77	0	00	35
	44	0	04	75
	43	0	13	20
	661	0	04	75
	661/ए	0	20	00

[सं० 12016/11/76-प्रोडक्शन]

टी० पी० सुब्राह्मण्यन, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4820.—Whereas it appears to the Central Government that is necessary in the public interest that for the transport of petroleum for flow line of well No. 9 in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby ; declares its intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation, Salaya, Koyal/Mathura Pipeline Project "Doli" 33/B, Harihar Society Kalawad Road, Rajkot.

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for flow line of well No. 9

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nawagam	62	0	00	10
	68	0	01	40
	69	0	01	75
	84	0	04	00
	83/2	0	04	75
	83/3	0	02	00
	83/4	0	01	75
	81/2	0	00	10
	80	0	05	75
	76/1/P	0	06	50
	77	0	00	35
	44	0	04	75
	43	0	13	20
	661	0	04	75
	661/A	0	20	00

[No. 12016/11/76-Prod.]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4821.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में व्यधन क्षेत्र सं० एस० डी० बी० से एस० डी० ए० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1-12-74 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के पर्यवसित कर दिया है ।

अब यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट प्रक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र एस० डी० बी० से एस० डी० ए० तक पाइप लाइन कार्य का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पेट्रोलियम	जगुदन	1495	24-4-76	1-12-74

[सं० 12016/1/76-एस एल एल]

के० बी० देशपांडे, गुजरात के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 8th December, 1976

S.O. 4821.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of Section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. No. SDB to SDA in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil and Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section 1 of Section 7 of the said Act on 1-12-74.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline From D.S. SDB to SDA

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum	Jagudan	1495	24-4-76	1-12-74

[No. 12016/1/76-L&L]

K. V. DESHPANDEY, Competent Authority Under the Act for Gujarat.

विधि मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1976

का. आ. 4822.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का हाई कमीशन, लुसाका में सहायक श्री जय करन को तत्काल कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फाइल सं. टी 4330(1)/76]

पी. आर. नीम्बसन, उप सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th November, 1976

S.O. 4822.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri Jai Karan, Assistant in the High Commission of India, Lusaka to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T-4330(1)/76]

P. R. NAMBISAN, Dy. Secy.

स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1976

का० आ० 4823.—पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के विषय में और भारतीय पास्तूर संस्थान के विषय में ।

यतः 15000.00 रुपये के 12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना पत्रों के 15,750.00 रुपये के ब्याज की रकम को, जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 31-8-62 की अधिसूचना सं० 14-26/61-इन्स्टिट्यूट के साथ प्रकाशित योजना के अनुसार लगाये जाने के लिए संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट पंचवर्षीय डाकघर सावधिक जमा खाते में फिर से लगा दिया गया है, भारतीय पूर्त अक्षयनिधि ट्रेजेरार में निहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ।

अतः अब पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त रकम भारतीय पूर्त अक्षयनिधि ट्रेजेरार में निहित होगी और वह उसे रखेगा । यह भी निदश देती है कि उक्त रकम और उस पर ब्याज का अनुप्रयोग उक्त योजना में दी गई शर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

अनुसूची

भारतीय पास्तूर संस्थान की तरफ से 15,750.00 रुपये की रकम को पंचवर्षीय डाकघर सावधिक जमा खाता संख्या 500228 में जमा कर दिया गया है ।

[संख्या एस० 22020/10/76-एम० सी०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Deptt. of Health)

New Delhi, the 20th November, 1976

S.O. 4823.—In the matter of the Charitable Endowment Act, 1890 and in the matter of the Pasteur Institute of India.

Whereas an application has been made to the Central Govt. for vesting a sum of Rs. 15,750/- relating to the interest on 12-year National Plan Certificates for Rs. 15,000/- which has been reinvested in the 5-year Post Office Time Deposit Accounts, specified in the Schedule appended hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India, to be applied in accordance with the Scheme, published with the notification of the Govt. of India in the Ministry of Health *vide* No. 14-26/61-Instt., dated the 31-8-1962.

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and on the application as aforesaid, the Central Govt. hereby directs that the said amount shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and directs that the said amount and interest thereof shall be applied in accordance with the terms set out in the aforesaid scheme.

SCHEDULE

A sum of Rs. 15,750/- invested on behalf of the Pasteur Institute of India with the 5-year Post Office Time Deposit Account No. 500228.

[No. S. 22020/10/76-MC]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4824.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् इसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है ;

उक्त अनुसूची के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :

"नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली	मेम्बर अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज	एम० ए० एम० एस०

उक्त अर्हता केवल तभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी जब उस 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद दिया गया हो और जिसका आधार नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के तरफ से नेशनल अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा ली गई परीक्षाओं (चाहे वह उक्त तारीख से पहले या बाद में ली गई हो) के परिणाम हों और इसे आनरेरी डिग्री के रूप में न दिया गया हो ।"

[संख्या वी० 11015/34/76-एम पी टी]

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4824.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, the following entry shall be inserted at the end, namely :—

"National Board of Examination, New Delhi.	Member Academy of Medical Sciences.	M.A.M.S.

This qualification shall be a recognised Medical qualification as aforesaid only when granted on or after the 1st April, 1976 on the basis of the results of examinations conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examination, New Delhi and not when conferred as an honorary degree."

[No. V. 11015/34/76-MPT]

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4825.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्रालय की 22/25 अप्रैल 1960 की अधिसूचना सं० 17-2/60-एम आई, द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए म्यूनिख विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा प्रदत्त एम डी (म्यूनिख) जर्मनी मान्य चिकित्सा अर्हता होगी,

और यतः डा० आई० मेरिया विक्लेर, जिनके पास उपर्युक्त अर्हता है, धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल प्रेमा सेवा अस्पताल, उत्तरोला, गोंडा, उत्तर प्रदेश के साथ संबद्ध है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० आई० मेरिया विंकलेर प्रेमा सेवा, अस्पताल, उत्तररोला, गोंडा (उत्तर प्रदेश) के साथ संबद्ध रहते हैं; जो भी कम हो, वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर प्रेक्टिस कर सकेंगे ।

[संख्या बी 11016/10/76-एम पी टी]

एस० श्रीनिवासन, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th December, 1976

S.O. 4825.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 17-2/60-MI, dated the 22/25 April, 1960, the Central Government has directed that the medical qualifications, "M.D. (Munick), West Germany" granted by the (Munick) University in West Germany shall be a recognised medical qualifications for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. I. Maria Winkler, who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Prema Sewa Hospital, Utraula, Gonda, Uttar Pradesh for the purposes of charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of Section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. I. Maria Winkler is attached to the said Prema Sewa Hospital, Utraula, Gonda, Uttar Pradesh, whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/15/76-MPT]

CORRIGENDUM

S.O. 4826.—In the English version of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Planning (Department of Health), No. S.O. 3334, dated the 3rd Sept., 1976, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 18th September, 1976,—

at page 3037, in line 24, for "D.T.C.S." read "D.T.C.D."

[No. V. 11015/43/75-MPT]

S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4827.—इंडियन नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (ii) में उल्लिखित राज्य समूह के राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा पंजाब और राजस्थान) के नर्सिंग सेवा के अधीक्षक (उनका पदनाम जो भी हो) इंडियन नर्सिंग कौंसिल के पदेन सदस्य होंगे ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 1 दिसम्बर, 1958 की अधिसूचना संख्या एफ० 27-57/57 एम II (बी) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन पदेन सदस्य" शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जाएं, अर्थात् :—

"1. सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा,
(मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य),
बिहार सरकार ।

2. अधीक्षक, नर्सिंग सेवा,
गुजरात ।

3. प्रमुख नर्सिंग अधीक्षक,
केरल ।

4. अधीक्षक, नर्सिंग सेवा,
कर्नाटक ।

5. उप अधीक्षक, नर्सिंग,
उड़ीसा ।

6. सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (नर्सिंग),
पंजाब ।

7. प्रमुख नर्सिंग अधीक्षक,
राजस्थान ।"

[सं० बी० 14013/1/76-एम पी टी]

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4827.—In pursuance of Section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), the Central Government hereby directs that the Superintendents of Nursing Services (by whatever name called) of the States in the group of States specified in sub-section (ii) of clause (m) of sub-section (1) Section 3 of the said Act (namely, Bihar, Gujarat, Kerala, Karnataka, Orissa, Punjab and Rajasthan) shall be ex-officio members of the Indian Nursing Council.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 27-57/57-M. II(B), dated the 1st December, 1958, namely:—

In the said notification, under the heading "Ex-officio members under clause (m) of sub section (1) of Section 3", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"1 Assistant Director of Health Services (Maternity and Child Health), Government of Bihar.

2. Superintendent of Nursing Services, Gujarat.

3. Chief Nursing Superintendent, Kerala.

4. Superintendent of Nursing Services, Karnataka.

5. Deputy Superintendent of Nursing, Orissa.

6. Assistant Director of Health Services (Nursing), Punjab.

7. Chief Nursing Superintendent, Rajasthan."

[No. V. 14013/1/76-MPT]

का. आ. 4828.—यतः केन्द्रीय सरकार ने इंडियन नर्सिंग कौंसिल अधिनियम 1947 (1947 का 48) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अनुसरण में 10 मार्च, 1975 से निम्नलिखित व्यक्तियों को इंडियन नर्सिंग कौंसिल का सदस्य मनोनीत किया है, अर्थात् :—

(1) कुमारी ए. चेरियन, प्रधानाचार्य,
कालेज आफ नर्सिंग,

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ ।

(2) डा. सुनीति दत्त,
33, छत्तर मार्ग,
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आफ दिल्ली,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

(3) कुमारी टी. के. अद्रन वाला,
दि गोल्ड मोहर, लोनाव्ला,
जिला पूना, महाराष्ट्र ।

(4) प्रोफेसर आर. सी. दास,
अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग,
राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 1 दिसम्बर, 1958 की अधिसूचना संख्या एफ 27-57/57-एम 2 (बी) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ़) के अधीन मनोनीत" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 1 से 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"1. कुमारी ए. चेरियन, प्रधानाध्यापक,
कालेज आफ नर्सिंग,
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,
छटी मंजिल, बी ब्लाक, चंडीगढ़ ।

2. डा. सुनीति दत्त,
33, छत्तर मार्ग,
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आफ दिल्ली,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

3. कुमारी टी. के. अद्रन वाला,
दि गोल्ड मोहर, लोनाव्ला,
जिला पूना, महाराष्ट्र ।

4. प्रोफेसर आर. सी. दास,
अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग,
राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ।"

[सं. बी 14013/1/76-एम पी टी]

विवेक कुमार अग्निहोत्री, अवर सचिव

S.O. 4828.—Whereas the Central Government have, in pursuance of clause (n) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), nominated the following persons to be members of the Indian Nursing Council, with effect from the 10th March, 1975, namely:—

(1) Miss A, Cherian, Principal, College of Nursing, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.

(2) Dr. Suniti Dutt, 33, Chattar Marg, Central Institute of Delhi, Delhi University, Delhi.

(3) Miss T. K. Adranvala, The Gold Mohur, Lonavla, Poona District, Maharashtra.

(4) Professor R. C. Das, Head, Department of Teacher Education, National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 27-57/57-M. II(B), dated the Ist December, 1958 namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (n) of sub-section (1) of Section 3" for Serial Nos. 1 to 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

"1. Miss A. Cherian, Principal, College of Nursing, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, 6th Floor, B-Block, Chandigarh.

2. Dr. Suniti Dutt, 33, Chattar Marg, Central Institute of Delhi, Delhi University, Delhi.

2. Miss T. K. Adranvala, The Gold Mohur, Lonavla, Poona District, Maharashtra.

4. Professor R. C. Das, Head, Department of Teacher Education, National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi".

[No. V. 14013/1/76-MPT]

V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1976

का. आ. 4829.—भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 133 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मेसर्स नेशनल मिनरल डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन को वेलाडीला लौह अयस्क खान, डिपाजिट संख्या 5 में, उनके आवेदन संख्या ई ई (ई)/बी 5/76/(410)/1229 तारीख 17/18-7-76 के अनुसार, रशियन ड्रिल मशीन सहित 440 वोल्ट रशियन ट्रेलिंग केबिलों को, 150 मीटर की दो लम्बाईयों में उपयोग की खातिर नियम 117(3), 123(5) और 123(7) के उपबंधों को शिथिल करती है । यह शिथिलीकरण निम्नलिखित शर्तों पर होगा :—

1. ट्रेलिंग केबलों को प्रदाय नियंत्रित करने वाले परिपथ विच्छेदकों में पर्याप्त सुग्रहिता वाले भूक्षरण रिले लगे होने चाहिए ताकि भू-भ्रंश की अवस्था में सिस्टम से प्रदाय का सम्पर्क टूट जाए ।

2. नम्य ट्रेलिंग केबल को 440 वी प्रदाय को नियंत्रित करने वाले परिपथ विच्छेदक के ओवरकरेन्ट ट्रिपों का ड्रिल मशीन से संस्थापित हार्स पावर से सामंजस्य होगा ।

3. नम्य ट्रेलिंग केबल विद्युत प्रदाय तंत्र से और मशीन से उचित रूप से रक्षित योजक बक्सों या पूर्ण रूप से बन्द सुरक्षित संलागों द्वारा योजित होनी चाहिए ।

4. नम्य केबल सम्यक् सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि उसके प्रयोग के दौरान किसी विद्युत त्रुटि से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचा जा सके । यदि कोई त्रुटि देखी जाए तो केबल की तुरन्त मरम्मत की जाए या उसे बदला जाए ।

5. 440 वोल्ट पद्धति में भू-क्षरण रक्षी युक्ति की दक्षता की जांच 24 घंटे से कम के अन्तरालों पर की जाएगी :

परन्तु पूर्वोक्त शिथिलीकरण उतने समय के लिए विधिमान्य होगा जब तक कि केबलों का खान में उपयोग किया जाता है और केबल जैसे ही खान से बाहर निकाले जाते हैं, उपनिदेशक, खान सुरक्षा

(विद्युत) के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को उसकी सम्यक् सूचना दी जाएगी ।

[संख्या ई. एल.-11-6(9)/76]
सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 1976

S.O. 4829.—The Central Government, in exercise of the powers conferred on them by sub-rule (2) of rule 133 of the Indian Electricity Rules, 1956, hereby relax the provisions of rules 117(3), 123(5) and 123(7) in respect of use of two lengths of 150 metres long 440V Russian trailing cables in conjuction with Russian Drill Machine in the iron ore mines of Bailadila Deposit 5 of M/s. National Mineral Development Corporation vide their application No. EE(E)/D5/76/(410)/1229, dated 17/18-7-76. The relaxation shall be subject to the following conditions:—

1. Circuit breaker controlling supply to the trailing cables shall be provided with efficient earth leakage relay of sufficient sensitivity for disconnection of supply from the system in the event of an earth fault taking place in the same.

2. The overcurrent trips of the circuit breaker controlling 440 V supply to the flexible training cable shall be in keeping with the installed horse power in the drill machine.

3. The flexible trailing cable should be connected to the electric supply system and the machine by properly constructed connector boxes or totally enclosed safe attachments.

4. The flexible trailing cable shall be handled with due care so as to avoid danger arising out of any electrical defects in the use. If any defects are noticed, the cables shall forthwith be repaired or replaced.

5. Earth leakage protective device in the 440 Volts system shall be tested for efficiency at intervals not exceeding 24 hours.

Provided that the aforesaid relaxation shall be valid for such time as the cables are in use at the mine and due information shall be given to the Central Government through the Dy. Director of Mines Safety (Elec.) as soon as the cables are taken out of the mine.

[No. 6(9)/76-EL. II]
S. P. JAIN, Dy. Director.

कोयला विभाग

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4830.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2747 तारीख 7 अगस्त 1975 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र में भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 121.75 एकड़ (लगभग) या 49.75 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि अर्जित कर ली जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 121.75 एकड़ (लगभग) या 49.75 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि अर्जित की जाती है ।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त के कार्यालय, रांची में या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) में किया जा सकेगा ।

अनुसूची

खंड-1

(करकट्टा कोलियरी विस्तारण)

उत्तरी करनपुरा कोयलावाले क्षेत्र

डी सं० रा०/56/75

तारीख 1-11-75

(जिसमें अर्जित भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1	नवाडीह	बरमू	4	रांची	121.75	भाग
			कुल क्षेत्र		121.75 एकड़ (लगभग)	
			या		49.75 हेक्टेयर्स (लगभग)	

नवाडीह ग्राम में अर्जित प्लाट सं०

160 (पी), 161 (पी), 162, (पी), 206 (पी) और 207 (पी)

सीमा वर्णन

क—ख रेखा नवाडीह ग्राम की प्लाट सं० 162, 161 और 207 से होकर जाती है ।

ख—ग रेखा नवाडीह ग्राम की प्लाट सं० 207, 206 और फिर 207 से होकर जाती है ।

ग—घ रेखा नवाडीह और तुमन्द ग्राम की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ (अर्थात् करकट्टा कोलियरी की पट्टाधृत सीमा के भाग के साथ-साथ) जाती है ।

घ—क रेखा नवाडीह ग्राम की प्लाट सं० 207, 160 और 162 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

[सं० 25/27/73-सी 31 सी एल]

(Department of Coal)

New Delhi, the 17th December, 1976

S.O. 4830.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Coal), No. S.O. 2747 dated the 7th August, 1975, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire lands in the locality described in the Schedule appended to that notification ;

And Whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government.

And Whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Behar is satisfied that the lands measuring 121.75 acres (approximately) or 49.75 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto, should be acquireed ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 121.75 Acres (approximately) or 49.75 hectares (approximately) described in the said-Scheduled are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Ranchi or in the office of the Coal Controller, 1. Council House, Street, Calcutta or in the office of the Central Coalfields limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

BLOCK-I

(Karkatta Colliery Extension)

North Karanpura Coalfield

DRG No. Rev/56/75
Dated : 1-11-75
(Showing land acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area in acres.	Remarks
1.	Nawadih	Burmu	4	Ranchi	121.75	Part.

Total Area :— 121.75 acres approx.)
or 49.75 hectares (approx.)

Plot Nos. acquired in village Nawadih :—
160 (P), 161 (P), 162(P), 206 (P) and 207 (P).

Boundary Description:—

A–B line passes through plot numbers 162, 161 & 207 of village Nawadih.

B–C line passes through plot numbers 207 , 206 and again 207 of village Nawadih.

C–D Line passes along the part common boundary of village Nawadih and Tumand (*i.e.* along the part lease hold boundary of Karkatta Colliery.

D–A Line passes through plot numbers 207, 160 and 162 of village Nawadih and meets at starting point 'A'

[No. 25/27/73-C3/CL]

का०आ० 4831.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, बिसेसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर-1 में या कलक्टर, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता में किया जा सकता है ।

उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों से हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शे चार्ट और अन्य दस्तावेजें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिसेसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर-1 को परिदत्त कर देंगे।

अनुसूची 1

सास्ती कोलियरी

वार्धा घाटी कोयला क्षेत्र

ड्रा० सं० पी०एल०जी०/सास्ती/भूमि 1–76
तारीख 23 जुलाई 1976

राजस्व भूमि

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	जिला	पटवारी सर्किल सं०	सर्वेक्षण का वर्ष	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियाँ
1.	सास्ती	राजुरा	चन्द्रपुर	आर आई राजुर	1964		भाग
2.	माथा	,,	,,	,,	1962		पयउ
3.	गौरी	,,	,,	,,	1973		,,
4.	ढोपताला	,,	,,	,,	1964		,,

कुल क्षेत्र 3578.26 एकड़ (लगभग)
या 1448.055 हेक्टेयर्स (लगभग)

अनुसूची 2

सरकार वन

क्रम सं०	वन का नाम	खान सं०	प्लाट सं०	तहसील	जिला क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	माथा	53	56	राजुरा	चन्द्रपुर	भाग
2.	ढोपताला	सर्वेक्षण 75 और 89 सं० 51 और 52				

1

कुल क्षेत्र 144.82 एकड़ (लगभग)
या 58.60 हेक्टेयर्स (लगभग)

कुल योग 3723.03 एकड़ (लगभग)
या 1506.655 हेक्टेयर्स (लगभग)

सीमा वर्णन

क—ख यह सास्ती कोलियरी की विद्यमान खनन सीमा है जो ढोपताला ग्रामों से होकर जाती है और सास्ती ग्राम में बिन्दु 'ख' पर मिलता है।

ख—ग यह सास्ती कोलियरी की विद्यमान खनन सीमा है जो सास्ती ग्राम से होकर जाती है और वार्धा नदी के दक्षिणी किनारे पर बिन्दु 'ग' से मिलती है ।

ग—घ रेखा सास्ती ग्राम से होकर जाती है और गौरी ग्राम में बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।

ब—ब रेखा गौरी ग्राम से होकर जाती है और उसी ग्राम में [बिन्दु 'क' पर मिलती है।

ड—क रेखा गौरी, मात्रा ग्रामों से होकर जाती है और [धोपताला ग्राम में प्रारम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 19 (63)/76 सी-एल]

धन्न धर त्रिपाठी, निदेशक

S.O. 4831.—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedules hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the Area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Bisesar House, Temple Road, Nagpur-1 or at the office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or at the office of the Coal Controller, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands specified in the said Schedules shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue officer, Western Coalfields Limited, Bisesar House, Temple Road, Nagpur-1, within 90 days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE I

Sasti Colliery

Wardha Valley Coalfield

Drawing No. PLG/SASTI /LAND/1-76

23rd July, 1976

REVENUE LAND

Sl. No.	Village	Tahsil	District	Patwari Circle No.	Year of Survey	Remarks
1.	Sasti	Rajura	Chandrapur	expand Rajur	1964	Part
2.	Matra	,,	,,	,,	1962	,,
3.	Gauri	,,	,,	,,	1963	,,
4.	Dhoptala	,,	,,	,,	1964	,,

Total area : 3578.26 acres (approximately)
or 1448.055 hectares (approximately)

SCHEDULE II

GOVERNMENT FOREST

Sl. No.	Name of Forest	Compartment No.	Plot No.	Tahsil	District	Area in Acres	Remarks
1.	Matra	53	56	Rajura	Chandrapur		Part
2.	Dhoptala Survey No.	51 & 52	75 1 & 89	,,	,,		Part

Total Area : 144.82 acres (approximately)
or 58.60 hectares (approximately)

Grand total 3723.08 acres (approximately)
or 1506.655 hectares (approximately)

Boundary Description :—

A–B This is the existing mining lease boundary of Sasti Colliery passing through the villages Dhoptala and meets at point 'B' in village Sasti.

B–C This is the existing mining lease boundary of Sasti Colliery passing through the village Sasti and meets at point 'C' on the southern bank of Wardha River.

C–D Line passess through village Sasti and meets at point 'D' in the village Gauri.

D–E Line passes through village Gauri and meets at point 'E' in the same village.

E–A Line passess through village Gauri, Matra and meets at starting point 'A' in village Dhoptala.

[No. 19 (63)/76 C. L.]
C. D. Tripathi, Director

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4832.—तुंगभद्रा बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. वि. का.-छः-4(9) दिनांक 10 मार्च, 1955 (समय-समय पर संशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है, नामशः—

पैरा-1 में "सदस्यों" के अन्तर्गत क्रम सं. 4 पर वर्तमान प्रविष्टि "संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि", के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :—

"कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) में वित्तीय सलाहकार"।

[सं. 19/4/76-वि. का.-एक]

का. रं. श्री आचार्य, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Irrigation Wing)

New Delhi, the 3rd December, 1976

S.O. 4832.—The following further amendment is made in the erstwhile Ministry of Irrigation and Power Notification No. DW-VI-4(9) dated the 10th March, 1955 (as amended from time to time) relating to the constitution of the Tungabhadra Board, namely:—

For the existing entry under "Members" in para 1 at No. (4) namely "The Joint Secretary, Government of India in the Ministry of Finance or his representative", the following entry shall be substituted :—

"Financial Adviser in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Irrigation)".

[No. 19/4/76-DW-1]

K. R. S. ACHARYA, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4833.—अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा एयर चीफ मार्शल पी. सी. लाल के स्थान पर इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री ए. एच. मेहता को तत्काल भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है।

[सं. ए वी : 24012/1/76-एए]

सी. एल. ढींगरा, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 8th December, 1976

S.O. 4833.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri A. H. Mehta, Chairman and Managing Director, Indian Airlines, as a part time Member of the International Airports Authority of India, with immediate effect, *vice* Air Chief Marshal P. C. Lal.

[No. AV. 24012/1/75-AA]

C. L. DHINGRA, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4834.—भारतीय व्यापार पोत (नाविक रोजगार कार्यालय कलकत्ता) नियम, 1954 के नियम 2 के खण्ड (2) के अनुसरण में, और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और नौवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. आ. 3310, दिनांक 7-9-1968 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पत्तन नौवहन वरिष्ठ उप महानिदेशक, बम्बई को उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए अपील अधिकारी नियुक्त करती है।

[का. सं. एम एस ई(42)/76-एम टी-1]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 3rd Dec. 1976

S.O. 4834.—In pursuance of clause (ii) of rule 2 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Shipping, No. SO 3310, dated the 7th September, 1968, the Central Government hereby appoints the Senior Deputy Director General of Shipping, Bombay, *ex-officio*, as the Appellate Authority for the purposes of the said rules.

[File No. MSE(42)/76-MT.I]

का. आ. 4835.—भारतीय व्यापार पोत (नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई) नियम, 1954 के नियम 2 के खण्ड (1) के अनुसरण में, और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और नौवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. आ. 3309, दिनांक 7-9-1968 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पत्तन नौवहन वरिष्ठ उप महानिदेशक, बम्बई को उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए अपील अधिकारी नियुक्त करती है।

[का. सं. एम एस ई (42)/76-एम टी-2]

राम तिलक पाण्डेय, अवर सचिव

S.O. 4835.—In pursuance of clause (i) of rule 2 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Bombay) Rules, 1954, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Shipping, No. SO. 3309, dated the 7th September, 1968, the Central Government hereby appoints the Senior Deputy Director General of Shipping, Bombay, *ex-officio*, as the Appellate Authority for the purposes of the said rules.

[File No. MSE(42)/76-MT-II]

R. T. PANDEY, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

का० आ० 4836.—शिमला टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सब की जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(III) (बी बी) में अपेक्षित है शिमला में चालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 7 मई, 1976 को "ट्रिब्यून" चंडीगढ़ और "वीर हिमाचल" शिमला समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-1-1977 से शिमला का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

शिमला टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :

शिमला का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि शिमला नगर पालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ता है;

किन्तु वे टेलीफोन उपभोक्ता जो कि शिमला नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें शिमला टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे।

[सं० 3-11/76-पी०एच० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 9th December, 1976

S.O. 4836.—Whereas a public notice for revising the local area of Simla Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules 1951 in the Newspapers in circulation at Simla inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 7th May, 1976 in 'Tribune' Chandigarh and 'Vir Himachal' Simla Newspapers.

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General, Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-1-1977 the revised local area of Simla shall be as under;

Simla Telephone Exchange System

The local area of Simla shall cover an area falling under the jurisdiction of Simla Municipality:

Provided that the telephone subscribers located outside Simla Municipal limit but who are served from Simla Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are within 5 Kms. of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-11/76-PHB]

का०आ० 4837.—मशोबरा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(III) (बी बी) में अपेक्षित है मशोबरा में चालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 10 सितम्बर, 1976 को "वीर हिमाचल" शिमला और "ट्रिब्यून" चंडीगढ़ समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III)(बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है कि तारीख 1-1-77 से मशोबरा का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

मशोबरा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

मशोबरा का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि मशोबरा नोटिफाइड एरिया कमेटी के क्षेत्राधिकार में पड़ता है किन्तु वे टेलीफोन उपभोक्ता जो कि मशोबरा नोटिफाइड एरिया कमेटी सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें मशोबरा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे।

[सं० 3/11/76-पी० एच० बी०]
प्रा० ना० कौल, निदेशक फोन (ई)

S.O. 4837.—Whereas a public notice for revising the local area of Mashobra Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Mashobra, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 10th September, 1976 in 'Vir Himachal' Simla and 'Tribune' Chandigarh Newspapers.

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General, Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-1-1977 the revised local area of Mashobra shall be as under;

Mashobra Telephone Exchange System

The local area of Mashobra shall cover an area falling under the jurisdiction of Mashobra Notified Area Committee:

Provided that the telephone subscribers located outside Mashobra Notified Area Committee limit but who are served from Mashobra Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are within 5 Kms. of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-11/76-PHB]
P. N. KAUL, Director of Telephones (E)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4838.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स मेटलचेम इन्डस्ट्रीज, ई-21, नन्दधाम औद्योगिक एस्टेट, मरोल मरोशी मार्ग, कार्यालय-अन्धेरी, कुर्ला मार्ग, मुम्बई-59 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अगस्त के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35018(57)/76-पी. एफ.-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4838.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Metalchem Industries, E-21, Nand Dham Industrial Estate, Marel Maroshi Road, Office-Andheri-Kurla Road, Bombay-59, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of August, 1974.

[No. S-35018/57/76-PF. II]

का. आ. 4839.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स बलवन्तराय मंछाराम एण्ड कम्पनी, सबजेल के पीछे, तालाब के निकट, खत्तोदरा, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अगस्त के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(438)/76-पी. एफ.-2]

S.O. 4839.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Balvantrai Mahchharam and Company, Behind Sub-Jail, Near Talay, Khatodra, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of August, 1976.

[No. S-35019/438/76-PF. II]

का. आ. 4840.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजपुर फार्मस लिमिटेड, डाकघर नरकटिया गंज, चम्पारन नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019/446/76-पी. एफ-2(1)]

S.O. 4840.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajpur Farms Limited, Post-Office Narkatea Ganj, Champaran, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S-35019/446/76-PF. II(i)]

का. आ. 4841.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1973 से मैसर्स राजपुर फार्मस लिमिटेड, डाकघर नरकटिया गंज, चम्पारन नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-35019/446/76-पी. एफ-2(2)]

S.O. 4841.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1973 the establishment known as Messrs, Rajpur Farms Limited, post office Narkatea Ganj, Champaran, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/446/76-PF. II(ii)]

का. आ. 4842.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1975 से मैसर्स मद्रास मैगजीन कम्पनी, 1/155, माउन्ट रोड, मद्रास-2 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-35019/445/76-पी. एफ-2(2)]

S.O. 4842.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1975 the establishment known as Messrs Madras Magazine Company, 1/155, Mount Road, Madras-2, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/445/76-PF. II(ii)]

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1976

का०आ० 4843.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4503 तारीख 11 दिसम्बर, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, पंजाब राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

अध्यक्ष :

1. सचिव, पंजाब सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, चण्डीगढ़।	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

सदस्य :

2. उप-सचिव, पंजाब सरकार, राजस्व विभाग, चण्डीगढ़।	राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति
3. श्रमायुक्त, पंजाब चण्डीगढ़।	
4. श्री ए० पी० मेयर, अध्यक्ष, पंजाब कारखाना स्वामी संगम, नेहरू गार्डेन्स रोड, जालन्धर सिटी।	राज्य में नियोजकों के संगठन के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि।
5. श्री हरबीत सिंह माखनी, द्वारा वस्त्र विनिर्माता संगम, 4, दीवान चन्द मेहरा रोड, अमृतसर।	
6. श्री इन्दरजीत, अध्यक्ष, दि इंडस्ट्रीयल चैम्बर, 117, साईकल मार्केट, गिल रोड, लुधियाना-141003.	
7. श्री ओम प्रकाश, 345, सेक्टर 21-ए, चण्डीगढ़।	राज्य में कर्मचारियों के संगठन के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि
8. श्री ओम प्रकाश मेहता, द्वारा ट्रेड यूनियन कार्यालय, चौक ढोलवाल, लुधियाना, पंजाब।	
9. श्री सेवा राम एडवोकेट, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पंजाबी राज्य, पक्का बाग, जालन्धर सिटी-1	
10. श्री प्रद्युम्नसिंह, टेक्सटाइल मजदूर एकता संघ पुतलीघर, छेहरता, अमृतसर, (पंजाब)	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का अशासकीय सदस्य जो सामान्यतः पंजाब राज्य का निवासी हो।

[सं० बी० 20012/7/72-पी. एफ-2]

New Delhi, the 7th December, 1976

S.O. 4843.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O. 4503 dated the 11th December, 1968, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Punjab consisting of the following persons, namely:—

CHAIRMAN :	
1. The secretary to the Government of Punjab, Labour and Employment Department, Chandigarh.	Appointed by the Central Government.
MEMBERS :	
2. Deputy Secretary to the Government of Punjab, Revenue Department, Chandigarh. 3. The Labour Commissioner, Punjab, Chandigarh.	Two persons appointed by the Central Govt. on the recommendation of the State Government.
4. Shri A.P. Mayor, President, Punjab Factory Owners Association Nehru Gardens Road, Jullundur City. 5. Shri Hardit Singh Makhni, C/o Textile Manufacturers Association, 4, Diwan C. Mehra Road, Amritsar. 6. Shri Inderjit Singh, President, The Industrial Chamber, 117, Cycle Market, Gill Road, Ludhiana. 141003.	Three representatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employers in the State.
7. Shri Om Prakash, 345, Sector 21 A, Chandigarh. 8. Shri Om Prakash Mehta, C/o Trade Union Office, Chowk Dholewal, Ludhiana, Punjab. 9. Shri Sewa Ram, Advocate, President, Indian National Trade Union Congress, Punjab State, Pacca Bagh, Jullundur City-1.	Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employees in the State.
10. Shri Parduman Singh, Textile Mazdoor Ekta Union, Putlighar Chhehorta, Amritsar, (Punjab).	Non-official members of Central Board of Trustees, Ordinarily resident in the State of Punjab.

[No. V. 20012/7/72-PF.II]

का०आ० 4844.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मद्रास मैगनीज कम्पनी, 1/155, माउन्ट रोड, मद्रास-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019/445/76-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 4844.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madras Magazine Company, 1/155, Mount Road, Madras-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1975.

[No-S. 35019/445/76-PF. H(i)]

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1976

का०आ० 4845.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 जनवरी, 1976 से मैसर्स वी० टी० पद्मनाभन एण्ड ब्रदर्स, सं० 34, अन्ना मार्ग, मद्रास-2 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35019/444/76-पी०एफ०2(ii)]

New Delhi, the 8th December, 1976

S.O. 4845.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1976 the establishment known as Messrs. V. T. Padamanaban and Brothers, No. 34, Anna Road, Madras-2 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/444/76-PF. II(ii)]

का०आ० 4846.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवीन सिल्क फैक्टरी संग्रामपुरा, देहलारी मार्ग, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1976 के अगस्त के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019/436/76-पी०एफ०-2]

S.O. 4846.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Navin Silk Factory, Sagrampura, Dehlari Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of August, 1976.

[No. S-35019/436/76-PF. II]

का०आ० 4847.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार-मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2079 तारीख 25 अगस्त, 1961 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जूरनचन्द्र डे को उक्त अधिनियम, और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम कुटुम्ब पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए० 12016/176-पी० एफ०-I(पी०टी०)]

S.O. 4847.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2079 dated the 25th August, 1961 the Central Government hereby appoints Shri Juran Chandra De to be an Inspector for the whole of the State of West Bengal and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the said Act, the Scheme, the Family Pension Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway Company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(1)/76-PF.I(Pt)]

का०आ० 4848.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सर्वश्री राजबहादुर श्रीवास्तव, पी० एन० लाल श्रीवास्तव, और इकबाल बहादुर श्रीवास्तव को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित स्कीम कुटुम्ब पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016/6/76-पी०एफ०-I(पी०टी०)]

S.O. 4848.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Sarvashri Raj Bahadur Srivastava, P. N. Lal Srivastava and Iqbal Bahadur Srivastava to be Inspectors for the whole of the State of Uttar Pradesh for the purposes of the said Act, the Scheme, the Family Pension Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(6)/76-PF.I(Pt.)]

का०आ० 4849.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा-विभाग की अधिसूचना सं० का०आ० 3124, ता० 28 सितम्बर, 1965 के अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए० एस० ईसी को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित स्कीम कुटुम्ब पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए०-12016/11/76-पी०एफ०-I]

S.O. 4849.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the Notifications of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 3124, dated the 28-9-1965, the Central Government hereby appoints Shri A. S. Ishi to be an Inspector for the whole of the State of Gujarat for the purposes of the said Act, the Scheme, the Family Pension Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(11)/76-PF.I]

का०आ० 4850.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० डी० पंडित को उक्त अधिनियम, और उसके अधीन विरचित स्कीम कुटुम्ब पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए०-12016/11/76-पी०एफ-I(पी०टी०)]

S.O. 4850.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri M. D. Pandit to be an Inspector for the whole of the State of Gujarat for the purpose of the said Act, the Scheme, the Family Pension Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway Company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(11)/76-PF.I(Pt.)]

का०आ० 4851.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सर्वश्री जे० एन० त्रिवेदी, आर० पी० शर्मा, एच० एन० शुक्ला और राम बहादुर श्रीवास्तव को उक्त अधिनियम, और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम कुटुम्ब पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निरीक्षण नियुक्त करती है ।

[सं० ए०-12016/6/76-पी०एफ०-I]

S.O. 4851.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Sarvashri J. N. Trivedi, R. P. Sharma, H. N. Shukla and Ram Bahadur Srivastava to be Inspectors for the whole of the State of Uttar Pradesh for the purposes of the said Act, the Scheme, the Family Pension Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[A. 12016(6)/76-PF.I]

का०आ० 4852.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी० टी० पद्मनाभन एण्ड ब्रदर्स सं० 34 अन्ना मार्ग मद्रास-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019/444/76-पी०एफ०-2(i)]

आर० एस० देशपांडे, उप सचिव

S.O. 4852.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. V. T. Padmanaban and Brothers, No. 34, Anna Road, Madras-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35019/444/76-PF. II(i)]

R. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4853.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs G. M. Syed, Calcutta, Marine Contractor and Messrs Great Eastern Shipping Company Limited, Calcutta, on the one hand and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th December, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 12 of 1976

PARTIES :

Employers in relation to Messr G. M. Syed, Calcutta, Marine Contractor and Messrs Great Eastern Shipping Company Limited, Calcutta,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Empoleyrs—Sri Ajit Roy Mukherjee, Counsel, with Sri S. R. Saha, Advocate, appears for Great Eastern Shipping Company Limited.

Nobody appears on behalf of G. M. Syed, Marine Contractor, Calcutta.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port & Dock

AWARD

By Order No. L-32011(24)/75-D-IV(A), dated 27th February, 1976, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to Messrs G. M. Syed, Calcutta, Marine Contractor and Messrs Great Eastern Shipping Company Limited, Calcutta and their workmen, to this Tirbunal, for adjudication. The reference reads :

"Whether the management of Messrs G. M. Syed, Calcutta and Messrs Great Eastern Shipping Company Limited, Calcutta are justified in denying to the steamer watchmen mentioned in the annexure to this Schedule their dues, namely, (i) Additional Dearness Allowance from October, 1973 to July, 1975; (2) Leave Salary for 1974 and (3) Interim Relief for 1974 and 1975 as per the recommendation of the Wage Revision Committee for Port & Dock Workers? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

ANNEXURE

List of Workmen

1. Md. Hossain.
2. Amir Hossain.
3. Sk. Rafique.
4. Sk. Jaman.
5. Rabi Bahadur,
6. Sk. Rouf.

2. The parties to the dispute are Messrs G. M. Syed, Marine Contractors and Great Eastern Shipping Company Limited, Calcutta, representing the management and their alleged workmen.

3. They have filed separate written statements raising various contentions. But, when the reference came up for trial today the workmen as well as the Union which alleged to have represented them were absent. They were, therefore, declared ex-parte.

4. On the management's side MW-1 was examined. He stated that the workmen concerned are not their workmen. It is for the workmen to prove that they are the workmen of the employers.

5. In the absence of any counter-evidence the contention of employers is accepted. I find that the workmen are not entitled to any relief undere the reference.

6. In the result, an ex-parte award is passed against the workmen concerned in the reference accepting the management's contention.

Dated, Calcutta,
the 27th November, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-32011(24)/75-D. IV(A)]

New Delhi, the 8th December, 1976

S.O. 4854.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras in the dispute between the employers in relation to the management of Messrs Collis Line (Private) Limited, Cochin and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1976.

BEFORE THIRU T. N. SINGARAVELU, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER,
INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS
(Constituted by the Central Government)
Friday, the 19th day of November, 1976.

Industrial Dispute No. 49 of 1974

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of M/s. Collis Line (Private) Limited, Willingdon Island, Cochin-3.)

BETWEEN

The workmen represented by:
The General Secretary, Cochin Commercial Employees' Association, 1/1291, Amaravathy Road, Cochin-1.

AND

The Manager' Collis Line Private Limited, Willingdon Island, Cochin-3.

REFERENCE :

Order No.L-35011/5/74-P & D/CMT, dated 26-12-1974 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiruvalargal M.P. Menon and M. Ramachandran, Advocates for the workmen and of Thiruvalargal M. Pathros Matthai and M. Krishnappan of Joseph and Kuriyan, Advocates for the Management and the parties having filed a memorandum of settlement and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India in their order No. L-35011/5/74-P & D/CMT, dated 26-12-1974 of the Ministry of Labour, have referred an Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Messrs. Collis Line (Private) Limited, Cochin and their workmen in respect of the following matters.

Whether the workmen of Messrs Collis Line (Private) Limited, Willingdon Island, Cochin are justified in demanding:—

1. Revision of their existing wage structure and allowances. If so what should be the basic wage, fixed dearness allowance, variable dearness allowance, house rent allowance, city compensatory allowance and special allowance for outdoor duties and from what date?

2. Revision of the existing facility of medical aid and if so what should be the extent of such facility and from what date ?

3. Revision of the existing Willingdon Island Allowance and its applicability to employees who have joined services of Messrs Collis Line (Private) Limited, after their office was shifted to the Willingdon Island. If so what should be the rate of such allowance and from what date?

2. The parties were duly served with summons.

3. The workmen filed claim Statement on 20-1-1975 setting out their claims. In repudiation thereof, the employer filed Counter Statement on 21-2-1975 to the claims of the workmen.

4. On behalf of the workmen, three witnesses were examined and for the employer, one witness was examined. Documents Exs. W-1 to W-13 and M-1 to M-14 were marked.

5. Today, when the dispute was taken up for recording evidence on the side of the Management, the counsel for both sides filed a joint petition along with the memorandum of Settlement, praying to pass an Award in terms of the Settlement. They admitted the terms of Settlement before me.

6. I perused the Settlement and I find that the Settlement is fair and reasonable. Hence the Settlement is recorded.

7. I pass an Award in terms of the Settlement. The Settlement will form an Annexure to this Award. There will be no order as to costs.

Dated, this 19th day of November, 1976.

T. N. SINGARAVELU, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For workmen :

W.W. 1	—Thiru M.V. Mani
W.W. 2	—Thiru Abdul Hameed.
W.W. 3	—Thiru P.K. Chakrapani.

For Management :

M.W. 1	—Thiru K.V. Jacov, Chartered Accountant.

DOCUMENTS MARKED

For Workmen :

Ex.W—1/30-4-71	—Memorandum of settlement between the workmen and the Management of The Malabar Steamship Co., Ltd., and the New Dholera Shipping and Trading Co., Ltd., Cochin-2 (copy).
Ex.W—2/5-2-74	— -do-
Ex.W—3/24-11-73	—Memorandum of settlement between The Rajugiri Rubber and Produce Co., Ltd., The Midland Rubber and Produce Co., Ltd., and others and their workmen (copy).
Ex.W—4/31-12-74	—Memorandum of settlement between Harrisons and Crosfield Ltd., Cochin and their workmen (copy.)
Ex.W—5/24-3-75	—Memorandum of settlement between M/s. Darragh Smail & Co. (I) Ltd., Cochin and their workmen (copy).
Ex.W—6	—Statement showing the rate of Willingdon Island allowance paid by other Companies at Cochin.
Ex.W—7/17-5-75	—Statement showing the pay scales of the workmen in other companies at Cochin.
Ex.W—8/17-5-75	—Statement showing the Dearness allowance of the workmen in other Companies at Cochin.
Ex.W—9	—Statement showing the names of employees, their category, service and emoluments drawn by them as on 1-1-1973 in the Management.
Ex.W—10/7-5-73	—Memorandum of demands made by the Union (Annexure to claim Statement).
Ex.W—11	—Balance sheet and profit and loss Account as at 1-8-1967 of the Ambassador Steamships Private Ltd., Cochin (copy).
Ex.W—12/15-5-74	—Conciliation failure report (copy).
Ex.W—13	—Statement showing the cost of living Index numbers for Ernakulam from January 1966 to July 1976.

For Management :

Ex.M—1/11-11-68 —Certificate of Incorportion (No. 2199/68) (copy).

Ex.M—2 —Balance sheet and profit and loss Account for the year ended 30-9-1973.

Ex.M—3 —Balance sheets and Profit and loss Account Statements for the years 1969 to 1975.

Ex.M—4 —Statement showing the scales of Pay and fixed D.A. paid to the employees of the Management, Tata Oil Company and South India Corporation Group Companies.

T.N. SINGARAVELU, Industrial Tribunal.

Note: Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the Award.

ANNEXURE

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Names of Parties :

Representing Employer — Mr. P.R. Krishnan, Manager, Collis Line Private Ltd., Willingdon Island, Cochin-3.

Representing workmen — Mr. P.K. Chakrapani, General Secretary, The Cochin Commercial Employees Association, Amaravathi, Fort Cochin, Cochin-1.

SHORT RECITAL OF THE CASE

The Cochin Commercial Employees Association submitted a charter of demands on behalf of the staff employed by Collis Line Private Limited at Willingdon Island, Cochin-3. After failure of conciliation proceedings initiated by the Assistant Labour Commissioner (Central) Ernakulam, the Government of India referred certain issues for adjudication before the Industrial Tribunal, Madras. The dispute has been registered by the Industrial Tribunal, Madras, as I.D.No. 49 of 1974. During the pendency of the dispute before the Industrial Tribunal, the parties arrived at a settlement of all the outstanding issues and disputes by mutual negotiations.

TERMS OF SETTLEMENT

1. The management agrees to introduce the following grades and scales of basic wages retrospectively from 1st January 1975 :—

A. **Clerical employees :**

Grade I Rs. 160-12.50-285-EB-17.50-460.

II Rs. 110-10-210-EB-12.50-335.

III Rs. 75-7.50-150-EB-10-250.

B. **Peons/Watchmen :**

Rs. 35-3-65-EB-3-95.

C. **Special Grade for Abdul Hameed, the Peon :**

Rs. 50-5-100-EB-7.50-175.

2. The employees in the service of the management on 1-1-1975 will be fitted into the new scales above on a point to point basis granting one increment for each completed year of service as shown in annexure 'A', except in the case of watchman Ram Bahadur, who will be brought to the minimum of the scale on 1-1-1976. Employees having been fitted as above into the scales will be given the normal annual increment for the year 1975 and thereafter on the 1st January every year. Extra increments given to the employees over and above the annual increment in January 1976 will also be continued to such employees at the enhanced rate.

3. The following scheme of dearness allowance will be introduced retrospectively from 1-1-1975 :—

(a) **Fixed Dearness Allowance :**

On 1st Rs. 100 of basic pay .. 75%

On 2nd Rs. 100 -do- .. 35%

On balance -do- .. 15%

subject to a minimum of Rs. 60/-.

(b) **Variable dearness allowance to all categories of employees over 400 points of Ernakulam Cost of Living Index (old series) :**

For the year 1975 commencing from January .. 29 Paise per point.

-do- 1976 -do- .. 30 -do-

-do- 1977 -do- .. 31 -do-

-do- 1978 -do- .. 32 -do-

4. The management agree to pay from 1st December 1976 to all categories of employees Willingdon Island Allowance at Rs. 25/- per month irrespective of the place of recruitment.

5. The management agrees to revise the privilege leave entitlement of the employees as under :—

Below 10 years of service .. 12 days per annum.

10 to below 20 years of service .. 15 days per annum.

20 years and above of service .. 20 days per annum.

6. The remaining demands in the memorandum of demands or the issues referred for adjudication not specifically dealt with herein are treated as having been settled in view of the above.

7. All other existing terms and conditions of service not specifically altered by the terms of this settlement will continue to remain in force.

8. The payments according to this settlement will be paid on or before 24th December 1976.

9. This settlement will remain in force till 31st December 1978 and shall continue to be in force after the said date until the expiry of two months from the date of a notice in writing of an intention to terminate the settlement is given by either part in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947.

10. It is agreed that during the operation of this settlement no demands involving financial commitments, excepting the question of bonus, will be raised by the workmen or union.

Dated this 18th day of November, 1976.

Signature of the Parties :
Sd/- .....
For COLLIS LINE PRIVATE LTD.,
MANAGER
Representing Employer.

Witnesses :

1. K.S. Gopalakrishnan, Accountant, Collis Line Private Ltd., Cochin-3.

2. T.K. Joseph, Clerk, Collis Line Private Ltd., Cochin-3.

Sd/- .....
For COCHIN COMMERCIAL EMPLOYEES ASSOCIATION
GENERAL SECRETARY
Representing Workmen.

ANNEXURE 'A'

Fitment of Employees as on 1-1-1975

Name of Employee	Grade	Years of Service.	Basic Salary as on 1-1-1975
			Rs.
Mr.E.A. Rebello	1st	12	320.00
,, Morarji P. Vyas	2nd	11	222.50
,, D.G.K. Nair	,,	10	210.00
,, T.X. Joseph	,,	8	190.00
,, V. Viswanathan	,,	8	190.00
Miss Bonny Rodrigues	,,	3	140.00
Mr. T.A. Rockey	,,	18	310.00
,, V.J. Joseph	3rd	9	142.50
,, M.V. Mani	,,	7	127.50
,, E.M. Thomas	,,	5	112.50
,, Abdul Hameed	Special grade		115.00
,, P.V. Franklin	Peon	9	62.00
,, M.V. Parameswaran	,,	7	56.00

Sd/- .....
For COLLIS LINE PRIVATE LTD.,
MANAGER
Representing Employer.

Sd/- .....
For COCHIN COMMERCIAL EMPLOYEES ASSOCIATION,
GENERAL SECRETARY
Representing Workmen.
(Sd/-)

T. N. SINGARAVELU, Industrial Tribunal.

[No.L-35011(5)/74-P&D/CMT/D.IV(A)]

New Delhi, the 9th December, 1976

S.O. 4855.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Alex Miller (Ship Chandlers) (Private) Limited, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th December, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 3 of 1976

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs. Alex Miller (Ship Chandlers) (Private) Limited, Calcutta,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri S. C. Bose, and Sri C. K. Modak, Advocate.

On behalf of Workmen—Sri S. Kar with Sri P. Biswas.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port & Dock

AWARD

By Order No. L-32011(22)/75-D. IV(A) dated 17th January, 1976 the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs. Alex Miller (Ship Chandlers) (Private) Limited, Calcutta and their workmen, to this Tribunal for adjudication. The reference reads :

"Whether the following demands of the casual geat handling workers employed by Messrs. Alex Millers (Ship Chandlers) (Private) Limited, Calcutta, are justified and the workmen concerned are entitled to the same ? If so, from what date and at what rate/scale ?

Demands :

1. Payment of daily rate of wages at par with General Purpose Mazdoors under the Calcutta Dock Labour Board.
2. Attendance allowance at the rate of Rs. 2/- per head per day.
3. Grant of 21 days' minimum guaranteed wage per month.
4. Grant of weekly day of rest with wages.
5. Extension of leave facilities on the lines allowed by the Calcutta Dock Labour Board.
6. Supply of uniforms."

2. The Natioanl Union of Waterfront Workers representing the concerned workmen and Messrs. Alex Miller (Ship Chandlers) (Private) Limited, Calcutta filed written statements taking up various contentions in respect of the claims made by the work but when the reference came up for hearing today, they compromised the dispute and entered into a written memorandum of settlement. The terms of the settlement are as follows :

1. that the daily rate of wages will be paid to the workers covered under the present terms of reference at the rate of Rs. 11.00 for day shift and Rs. 12.00 for afternoon and Night shift of their duties with effect from the date of reference before the Hon'ble Tribunal.
2. that the minimum guaranteed wage will be decided after one year on the basis of average employment available to the workers during the last 12 months from the date of pbulication of award.
3. that the workmen will be paid "Attendance Allowance" at the rate of Re. 1/- for those days when work will not be available for them.
4. that the workers will not press on the demand of weekly day of rest with wages.
5. that the workers will be granted either with 10 days sick leave or 10 days casual leave with pay. The said 10 days leave can be taken at a time.
6. that the workers will be granted with 5 (five) National/Port closed holidays and 3 holidays in ID-UD-ZUHA, ID-UL-FITAR and FATEHADU-AZDHAM with wages. In case the workers are employed/booked on the said 3 working holidays, they will be paid wages at the double rate of their daily rate of wages.

3. They have also filed a petition praying to record the terms of the settlement pass an Award in terms of that settlement.

4. In the result, an Award is passed in favour of the workmen represented by the aforesaid Union in terms of the compromise setforth above.

Dated, Calcutta,

The 4th December, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-32011(22)/75-D.IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 9th December, 1976

S.O. 4856.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 63 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the State Bank of India,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri Ajit Roy Mukherjee Senior Counsel, with Sri A. K. Mitra, Additional Law Officer.

On behalf of Workmen—Sri Anil Das Chowdhury, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

AWARD

By Order No. L. 12011/10/75/DII/A dated 17th September, 1975, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The Reference reads :

"Whether the demand of the workmen of the State Bank of India represented by the State Bank of India Employees' Association, Bengal Circle, for treating the staff of such canteens which are run by Local Implementation Committees, as workmen of State Bank of India for giving them the same status, pay and facilities as are available to other class IV employees of the Bank is justified ? If so, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

2. The alleged industrial dispute covered by the reference was sponsored by the State Bank of India Employees' Association, Bengal Circle, for and on behalf of the employees of Canteens established in the branches of the bank on the basis of Welfare Scheme propounded by the Bank in or about the year 1963. The canteen staff are working in the premises of the bank but the control and management of the staff is with the Local Implementation Committee which was formed under the Scheme. The Bank management constitutes a fund known as Staff Welfare Fund. The memorandum prepared in connection with the Staff Welfare Fund is contained in Ext. M-1 dated 8th August, 1963. There are nine Circles within the area of operation of Bank in this country. On the basis of the Scheme, Circle Welfare Committees were to be formed and under that Committee the Local Implementation Committee was formed to look after the welfare of the employees of the Bank. The terms and conditions for the utilization of the Scheme of the Welfare fund are contained in Ext. M-1(a). Clause (iv) of Ext. M-1(a) provides that welfare activities were to be undertaken in respect of the following, but the list was said to be not exhaustive. The nature of the welfare activities are as follows :—

(a) promotion of cateen facilities;

(b) provision of libraries and reading rooms;

(c) encouragement of sports and games—indoor and outdoor;

(d) promotion of cultural activities;

(e) improved medical facilities—reservation of beds in hospital and sanatoria;

(f) establishment of holiday homes and convalescent homes;

(g) educational facilities—scholarships to sons and daughters of employees of lower income group (i.e. upto the grade of Sub-Accountants and Head Cashiers).

In the note attached to Ext. M-1(a) it is provided that canteen facilities should be given top priority and should be taken up without delay. There are also directions in the note regarding other welfare activities. Directions were given in clause (vi) at page 2 of the said exhibit that Implementation Committee should be formed at each branch and also at the respective local Head offices to determine the particular welfare activity or activities to be conducted at the branch or local Head offices within the limit of the found allocated to the branch or local Head offices by the Circle Welfare Committee and within the heads of activities specified. It is further stated that such Functional or Implementation Committee will be in charge of the management of the welfare activities, if necessary, through sub-committees and it is also suggested that on consultation with the Circle Welfare Committee particular type of welfare activiies which should be undertaken at the respective offices. It is also provided in that clause that these committee will render appropriate accounts to the Circle Welfare Committee of the branch or as otherwise directed. Paragraph 7 at page 3 of Ext. M-1(a) deals with the composition of each Circle Welfare Committee. The next paragraph on the same page deals with the composition of the Local Implementation Committee. Clause (a) of that paragraph provides that the Agent of the branch or the Chief Accountant (or any other officer nominated by the President of the Circle Welfare Committee) at the Local Head Office will be the President of the Local Implementation Committee. The working arrangement and the relationship between the Implementation Committee and the Circle Welfare Committee are enumerated in succeeding paragraph. It is relevant also to point out that the management had provided allocation of suitable amounts to various Circle Committees to be utilised for the Welfare activities in the circle. This amount was created by the Central Board of the Bank by transfer of funds from annual profits which was declared to be appropriated to the bank but it was earmarked for providing certain amenities to the staff and carrying out other welfare activities for the employees of the bank as a whole.

3. On the basis of these conditions and limitation set forth in Ext. M-1 and M-1(a) canteens have been established in various branches of the bank in the Bengal circle. The implementation Committeee have appointed certain number of men as employees as staff in the canteens for preparation of tea, edible food and other snacks and sometimes even meals to be prepared and supplied to the members of the staff. The employees of the canteens have got access in any part of the bank for the supply of food to the members of the staff. The canteens are situated within one of the rooms of the office of the bank. However, the appointment of the canteen employees was made by the Local Implementation Committee. The President and other office bearers as well as the members of the committee are all regular employees of the bank. No outsider is permitted to hold any office in the Implementation Committee or in the Circle Welfare Committee. The contention of the union on behalf of the canteen employees is that all the employees of the canteen shall be deemed to be the workmen of the bank having right to get the same salary and other emoluments and amenities as other recognised workmen of the bank and they have claimed that their pay, status and facilities shall be the same as class IV employees of the bank.

4. The management in their written statement contended that the Canteen staff was appointed by the Local Implementation Committee and as such they were not workmen of the bank. They have set forth the terms and conditions of the Welfare fund and the directions contained therein as to the management of the welfare fund regarding the establishment of the welfare schemes for the benefit of bank employees and as such they state that the bank has nothing to do with the appointment and control, supervision or working of the canteen and as such they state that the canteen staff are not and they have never been the workmen of the bank. In the written statement they have also contended that there is no industrial dispute between the bank and their employees and as such the reference in question is incompetent. In a rejoinder dated 7-7-1976 the bank maintains that the State Bank of India Employees' Association,

Bengal Circle, does not represent any substantial section of the workmen of the State Bank of India and as such the dispute referred to is not a collective dispute and so this Tribunal has no jurisdiction to entertain the same. They have also denied some of the allegations which the union made in their earlier written statement.

5. One of the questions that has come up for consideration in this reference is whether there is an industrial dispute that existed between the bank and its employees. This question can be bifurcated into two sections; one question is whether the present dispute can be entertained as an industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947. That is one of the contentions which the bank has taken up in the written statement they filed on 23-12-1975. It is not necessary to reproduce the definition of 'industrial dispute' in Section 2(k). It is sufficient to point out that there is a substantial dispute between the bank and the union which espoused the cause of the workmen on the question of the status of the canteen employees. In case reported in Workmen of Dimakuchi Tea Estate v Dimakuchi Tea Estate, 1958 I LLJ, 500, the dispute was regarding an employee of the Tea Estate who was not a workman. It was nevertheless held that this was a dispute between the workmen and the company. Whether the canteen staff should be regarded as the workmen of the bank is a relevant or substantial dispute between the bank and its workmen. So, the first part of Section 2(k) is satisfied to say that there is an industrial dispute. The second part is that the dispute or difference should be between employer and employer or between employer and workmen or between workmen and workmen. There cannot be any dispute that the dispute which has now been raised before this tribunal is between the management on one side and its workmen represented by sponsoring union. So, the second condition is also satisfied. The third condition is that the dispute or difference must be on the employment or non-employment or the terms of employment or the condition of labour of any person. It was held in the decision reported above that 'any person' used in Section 2(k) would not justify the workmen of a particular employer to raise a dispute about anyone in the world though the words "any person" in that provision may not be equated with the words "any workman". The test in determining the question as to the meaning as of the words "any person" in Section 2(k) was stated in the following words at page 510 of the above decision. It is reported at page 237 affirming the earlier decision in Standard Vacuum Refining Company of India, Ltd. and Their Workmen and another, 1960 II LLJ, 233 :

> "If, therefore, the dispute is a collective dispute, the party raising the dispute must have either a direct interest to the subject-matter of dispute or a substantial interest therein in the sense that the class to which the aggrieved party belong is substantially affected thereby. It is the community of the interest of class as a whole—class of employers or class of workmen—which furnishes the real nexus between the dispute and the parties to the dispute. We see no insuperable difficulty in the practical application of this test. In a case where the party to a dispute is composed of aggrieved workmen themselves and the sub-matter of the dispute relates to them or any of them, they clearly have a direct interest in the dispute. Where, however, the party to the dispute also composed of workmen espouse the cause of another person whose employment or non-employment, etc., may prejudicially affect their interest, the workmen have a substantial interest in the subject-matter of dispute. In both such cases the dispute is an industrial dispute."

6. It cannot be disputed that the union which raised the dispute had a direct interest in the subject-matter of the dispute as a substantial interest in the sense that the class to which they belong is substantially affected thereby. Whether there is community of interest between the Union and those whose cause they espoused has to be considered. The canteen staff as well as the workmen who are members of the union are the workmen of the same employer and they work in the same office. It can therefore be said that there are some community of interest between the two. Still the larger question is as to whether the union which represented the workmen concerned in the dispute has got any representative character.

7. On this question the evidence is that of WW-1 who is a member of the State Bank of India Employees Association. He stated that about 30 per cent of the members of the union are the employees of the bank. This evidence of WW-1 was not controverted by the management's witness who was examined as MW-1. On the other hand, he stated that he had no idea of the representative character of the union concerned in the case. It is clear from the evidence of WW-1 that at least 30 per cent of the employees of the bank are members of the concerned union. There is another union known as All State Bank of India Staff Federation. It is admittedly the majority union. The fact that a minority union or even unregistered union espousing the cause of the workmen is not a relevant matter to hold that they have no representative character. The question is whether a substantial section of the members of the union espoused the cause of the workmen. Excepting the evidence of WW-1 there is no evidence to the contra. His evidence has to be accepted to hold that the union concerned has representative character to espouse the cause of the aggrieved workmen though they work in another section of the establishment. One of the conditions setforth in the case reported in the Workmen of Dharampal Premchand (Saugandhi) and Dharampal Premchand (Saughandhi), 1965 I LLJ, 668, is that if there is no union of workmen in any establishment, a group of employees can raise the dispute and the dispute then becomes an industrial dispute even though it is a dispute relating to an individual workman. Having found that the dispute has been sponsored by a representative union of the workmen of the establishment, it cannot be said in the circumstances of the case that there is no industrial dispute in existence. I find accordingly that the union has rightly sponsored the cause of the canteen employees in respect of an industrial dispute.

8. The next point for consideration is whether the canteen employees are the workmen of the bank. It has to be said that the question whether the staff of any particular establishment of a bank is a workman or not as defined under Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947 depends upon the facts and circumstances of each case. In this case it is nobody's contention that the staff of the canteen was appointed by the bank; that the bank pays salary directly to the workmen; that they superwise their work from day to day and that they have exercised any disciplinary proceedings against the workmen. On the contrary, it is admitted case of both sides that the canteen employees have been appointed by the Local Implementation Committee which is a creature of the bank. It cannot also be contended that the canteen occupation in the particular circumstances of the case is an industry. The Bombay High Court in a judgment evidenced by Ext. M-2 has stated that canteen within the bank premises is not an industry. That conclusion however will not deter us from coming to a conclusion whether the canteen employees are the workmen of the bank or not. The dispute covered by Ext. M-2 judgment was taken up by the Canteen employees on the one side and their employers who are State Bank of India Staff Canteen Department, Bombay. The committee referred to therein was the Local Implementation Committee which was formed under the Welfare Scheme. The bank was not a party to that judgment, neither it was contended in the judgment that the employees of the canteen were the workmen of the bank. The only question that posed for determination in that judgment was whether canteen occupation was an industry. The Bombay High Court held that it was not an industry. That finding is not very material for the purpose of deciding the issue before us.

9. The learned Counsel on behalf of the union has brought to my notice three decisions. They are, (i) in the case of The Ahmedabad Manufacturing and Calico Printing Company, Ltd. (Calico Mills) and three other Companies v Their workmen, 1953 II LLJ, 647; (ii) the case between Ramtahel Ramanand and Ors., and Ahmedabad Manufacturing and Calico Printing Company Ltd., and another, 1968 II LLJ, 46 and (iii) the case between the Ahmedabad Mfg. and Calico Ptg. Co. Ltd., and Ram Tahel Ramanand and others, 1972 II LLJ, 165. All these three decisions are based upon an interpretation of Sections 3(13) and (14) of Bombay Industrial Relation Act, 1947. Section 3(13) defines "employee" and Section 3(14) defines "employer". Clause (e) of Sec. 3(14) provides, "where the owner of any undertaking in the course of or for the purpose of conducting the undertaking contracts with any person for the execution by or under the contractor of the whole or any part of any work which is

ordinarily part of the undertaking, the owner of the undertaking". The scope and extent of this definition are very wide to include any person to connect his activities reasonably attributable to the undertaking, and if that be so then such an activity was considered to be as an activity of the worker who are to fall within Section 3(13) of the said Act. It is, therefore, clear that none of the above decisions can be applied to the facts of the present case. This case has to be decided on the materials on record, oral and documentary evidence and other circumstances.

9. There is evidence that it was out of the fund of the bank that the canteen employees were being paid their salaries. The members of the Local Implementation Committee are the workmen of the bank. The committee figures as an intermediary between the canteen employees and the bank management. In that sense the Local Implementation Committee has no independent activity. They take direction and advice from Circle Welfare Committee who in its turn take their instruction and advice from the bank management. In the above circumstances one is inclined to consider the scope of the Union's contention in the light of judicial pronouncements made in earlier cases. The first of these cases is the one reported in 1955 I LLJ, 688 between Shivnandan Sharma and Punjab National Bank, Ltd. In that case the bank employed certain persons named as Treasurers under a contract by which they were styled as "contract treasurers". They have to obey the orders of the bank and they shall be paid for their services and the salaries to the persons employed by them were also be paid by them. But the Supreme Court in that case pointed out that though it is true that the treasurers had the fullest responsibility for the appointment, dismissal and payment of the salary of the cashiers and other assistants employed by the treasurers, still having regard to the fact that the appointment of the cashier and other assistants had to be approved by the bank and the treasurers cannot continue to employ those workmen in whose fidelity and efficiency the bank had no confidence, such workmen must be regarded as workmen of the bank only. If the treasurers' relation to the bank was that of servants to a master, simply because the servants were authorized to appoint and dismiss the ministerial staff, of the cash department this would not make the employees in the cash department independent of the bank. If a master employs a servant and authorizes him to employ a number of persons to do a particular job and to guarantee their fidelity and efficiency for a cash consideration, the employees thus appointed by the servant would be, equally with the employer, servants of the master. This decision was followed in a later case between Kanpur Mill Mazdoor Union and Muir Mills Company, Ltd., 1955 II LLJ, 537. In that case the position was that a sum of Rs. 753 was given to Ghasi Ram by the management and he in his turn disbursed the wages to the coal coolies out of the same. In the light of those circumstances the Labour Appellate Tribunal of India stated that the so called contractor and his employees all are employees of the mill and not that of an independent contractor. The facts of those two cases can be applied here.

10. The third case in this regard is the one reported in J. K. Cotton Spinning and Weaving Mills Company, Ltd., and Labour Appellate Tribunal of India and others, 1963 II LLJ, 436. That was a case in respect of employees of a Textile mill which allotted residential bungalows to its officers and its director. The bungalows were situated in the mills compound and were owned by the company. The company used to allot the bungalows as a part of the service condition of its officers. The company was paying the salaries of the malis appointed by it to look after the gardens attached to the bungalows. The company used to recover a portion of their salary from the officers in lieu of the salaries paid to the employees. The amounts so recovered were used to be credited to the general revenues of the company, The company had also appointed a person to supervise the work of the malis and the company alone had the disciplinary authority in respect of the malis. This case can be distinguished to some extent from the earlier two decisions referred to above in as much as in this case the malis were appointed directly by the mill authorities. However, the principal enunciated in that case should be brone in mind for consideration of the question whether in the instant case the canteen employees can be considered as the workmen of the bank. The next case on this question is the one reported in D. C. Dewan Mohiden Sahib & Sons and United Bidi Workers' Union, Salem and another, 1964 II LLJ, 633. In that case also the so called contractors intervened between Beedi rollers and the manufacturers. It was found on evidence that the so called independent contractors were the agents of the beedi manufacturers. The work of beedi rolling was done in the premises of the so called contractors. There was no supervision or control of the work of the beedi rolling. In these circumstances it was found that the employees who rolled beedis were really the workmen of the manufacturers. The next case in these series is one in Standard Vacuum Refining Company of India Ltd., and Their workmen and another, reported in 1960 II LLJ, 233. In that case there was contract labour as well as regular employees of the oil refinery doing the same kind of wok. The contract workers wanted abolition of the contract system and their appointment as regular workmen of the refinery. In that case the Supreme Court set aside the contract system and held that the workmen shall be employed as and when work is available as regular workmen of the refinery. The principle involved in that case can be applied to the facts of the present case.

11. These decisions establish beyond doubt that the canteen employees of the bank can be considered as the workmen of the bank. The fact that they were paid directly by the Local Implementation Committee their monthly remuneration is not a circumstance to hold that they are not workmen of the bank. A large sum of money is set apart by the bank and put in the hands of the Circle Welfare Committee for distribution amongst the various Local Implementation Committees towards the salary to be paid to the canteen employees. The appointment of the canteen employees is not a material circumstance when it is to be held that the members of the Local Implementation Committee are creatures of the bank. They have no independent existence. The agent of the local branch is the President of the Committee. He is to pass every item of expenditure. The house-hold utensils to be used in the canteen are supplied by the bank. Several other items of expenditure has to be countersigned by the President of the Committee who is the Agent of the branch of the bank. It is admitted that the bank has its own employees as workmen in canteens which they established in several branches of the bank for maintaining their own canteens for supply of tea, etc. to the officers of the bank as well as other visitors to the bank. Their salaries are paid on the basis of class IV employees. That is an indication that the bank has accepted the employees of the canteen as workmen of the bank, but at the same time they have refused to accept the canteen employees under the Local Implementation Committee as their workmen. This discrimination cannot be allowed to stand. Two other witnesses have also been examined on behalf of the workmen as WWs 2 and 3. As against their evidence the evidence of MW-1 was not very convincing. There is no reason to reject the evidence of WWs 1 to 3 in this case. They have proved hat they are bank employees and they have been treated as such in their conduct of work from day to day. They work during the working hours of the bank. They get their uniforms from the bank. These circumstances are sufficient to hold that the canteen empolyees are workmen of the bank. They shall, therefore, be regarded as class IV employees who are entitled to get the same salary as the other employees of the bank.

12. Having found that the canteen employees are workmen of the bank they would be entitled to the same status, pay and other facilities as are available to other class IV employees of the Bank. But those rights will accrue to their favour only with effect from 1st November, 1976. I hold accordingly because this point has not ben decided at any time before by any competent authority; so the right will accrue in their favour only with effect from the above date.

13. In the result, an Award is passed in favour of the canteen workmen which are run by the Local Implementation Committees giving them same status, pay and facilities as are available to other Class IV employees of the bank with effect from 1st November, 1976.

Dated, Calcutta,
The 30th November, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding officer

[F. No. L-12011/10/75-D. II(A)]
R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 8th December, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 4857.—In this Ministry's Notification No. L-20012/135/72-LRII/DIIIA, dated the 6th August, 1976, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 21st August, 1976, S.O. No. 3064 at Page 2910, the following correction shall be carried out:—

In para 1, line 6 for words "South Jharia Colliery" read "Alkusa South Colliery".

[No. L-20012/135/72-LR.II/D.III(A)]

New Delhi, the 9th December, 1976

S.O. 4858.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mudidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th November, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 35 of 1975

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's order No. L-20012/145/74-LRII/DIIIA Dt. 4-4-1975)

PARTIES:

Employers in relation to the management of Mudidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

On behalf of the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the Workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, Dated, the 27th November, 1976.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mudidih colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Sijua, Dstrict Dhanbad sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the same with the following issues framed:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Mudidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad, in stopping from work Shri Satya Shanti Prakash, Shale Picker, with effect from 6-7-1974, is justified ? If not, to what relief are the concerned workman entitled ?

2. The case of the workmen is that Shri Satya Shanti Prakash was employed in the colliery as a Shale Picker on 15-9-73. He drew his wages and bonus and became a member of the Coal Mines Provident Fund and Pension Scheme. He was stopped from work without notice on 6-7-74. It is prayed that he be reinstated with back wages from 6-7-1974.

The employers allege that Shri Satya Shanti Prakash was inducted in the colliery with effect from 15-9-1973 in collusion with some colliery employee in a surreptitious manner without any permission and approval of the appropriate authority. When this fact came to the notice of the management he was stopped from service with effect from 6-7-1974. Others like him were also stopped from service.

The fact remains that the person concerned worked in the colliery from 15-9-73 and he was stopped from work with effect from 6-7-74. Examined as WW1 he says that he got wages, bonus etc. for all these months and he became a member of the Coal Mines Provident Fund. He says that he was appointed by the Manager, Shri Bahal but no appointment letter was issued to him. The case of the management is that he surreptitiously got into service in collusion with some colliery employees. He was working for about 10 months before he was stopped from work, getting his wages and bonus alright and becoming a member of the Coal Mines Provident Fund. These are not secret facts and they are all open facts and matters of record. The colliery is supposed to have supervisory staff under whom he was working in addition to various grades of officers and staff. I fail to understand how he could work unauthorisedly escaping the notice of his supervisor and other staff and how he could get his wages. If actually the contention of the management is true, then it does not redound to the credit of the management regarding their supervision and checks. In that case there must be something wrong somewhere and it is high time that they found out how not only this man but many others could work unauthorisedly without the notice of the supervisors. It may be that the person concerned could not produce any appointment letter and his name does not apper in 'B' Form. That apart, the accomplished fact remains that the person concerned worked for about 10 months before he was stopped from work and some benefit has accrued to him. He got into service after nationalisation of collieries. The question remains if the management can stop a person who has rendered about 10 months service, on their unilateral finding that he was an inductee. Not a single witness from the employers side was examined. The concerned workman might have something to say in the matter. From the case of the employers it is apparent that he got into service by deceiptful means in collusion with some workmen of the colliery. In my opinion the concerned workman should have been given reasonable oportunity to show cause against his removal from service and then the Company should have enquired into the matter and only when the case of the employers was made out, the employers could have removed him from service. In this connection the learned Advocate for the workmen referred to a decision as in Lab. I.C. 1973 Supreme Court 1267. In this circumstances I do not find that the action of the employers in stopping the concerned workman as they did from service with effect from 6-7-1974 is justified. Reinstatment with back wages should have been the normal remedy in this case. But in the facts and circumstances of the case I do not pass any orders of his re-instatement and back wages. But direct that he should be given some compensation. Compensation equivalent to four months wages, in my opinion, would meet the ends of justice.

In the result, the action of the management in stopping from work Shri Satya Shanti Prakash with effect from 6-7-1974 is found not justified. He is entitled to compensation equivalent to four month's wages.

This is my award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[No. L-20012(145)/74-IR.II/D.III(A)]

New Delhi, the 13th December, 1976

S.O. 4859.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Damoda Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Karmatand, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th November, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 25 of 1976.

In the matter of an industial dispute u/s 10 (1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's order No. L-20012/8/76/D. IIIA dt. 25-5-1976)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Damoda Colliery of M/S. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Karmatand Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri P. K. Burman, Law Officer.

On behalf of the workmen.—None

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad 26th November 1976

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :

SCHEDULE

Whether the action of the management of Damoda Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited Post Office Karmatand-via Mohuda District Giridh in terminating the lie of S/Shri Dhanraj Mahato and Rameshwar Mahato Miners on their permanent appointment and placing them on the Badli list with effect from 16th July, 1975 is justified ? If not, to what relief are the two workmen entitled ?

As the parties did not file their respective statement of demand before this Tribunal notices were sent them for the same.

It appears that a settlement in respect of the Industrial Dispute was reached by the parties i.e. Employers and the Branch Secretary of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Damoda Branch in the meantime. Shri P. K. Burman, Law Officer of the Employers Company and a representative of the workman filed the settlement before me, and prayed for an award being passed on the basis of the settlement. The signatures in the petition of compromise were verified to my satisfaction. I have gone through the memo of settlement and the terms thereof appear to be beneficial to the parties and so there is no reason why I should not accept the same. As there are certain terms specified in the memo of settlement, it should be made a part of my award.

In the result, I make an award in respect of the industrial dispute involved in this reference in terms of the memo of settlement which do form part of the award as annexure A.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In Ref. 25 of 1976.

Employers in relation to Damoda Colliery

AND

Their Workmen

Joint petition for compromise settlement

The humble petitions, on behalf of the parties most respectfully beg to state :

(1) That the above dispute has been amicably settled between the parties by a voluntary settlement between the parties dated 8th June, 1974 the copy of which is hereby enclosed for record.

(2) That the above noted settlement has been fully implemented by the management and as such, no further dispute relating to the matter under reference exists, for adjudication proceeding.

(3) The petitioners therefore pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass a no dispute award incorporating the terms of settlement.

And for this the humble petitioners shall ever pray.

Representative of the Employer.

Dated : 23-11-1976.

Representative of the Workmen.

ANNEXURE 'A'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE MANAGEMENT OF DAMODA COLLIERY AREA NO. I.BCCL. AND WORKER REPRESENTED BY RCMS, DAMODA COLLIERY BRANCH ON 8-6-1976

PARTIES.

REPRESENTING

EMPLOYERS.

1. Sri K. C. Nandkeolyar,
   Area Manager (Personnel),
   Area No. I.BCCL.
2. Sri P. K. Roy, Personnel Officer,
   Area No. I.BCCL.

REPRESENTING WORKMEN.

1. Sri K. L. Ray,
   Branch Secretary,
   RCMS,
   Damoda colliery Branch.

SHORT RECITAL

The Union namely RCMS raised a dispute before the A.L.C.(C), Dhanbad-II. vide it letter No. VI (35)/75/7240 dt. 4th Oct., 1975 in connection with alleged unjustified stoppage of work of S/Sri Dhanraj Mahato & Rameshwar Mahato with effect from 16-7-75. The matter was takenup by the A.L.C.(C), Dhanbad-II. vide file No. D-3/149/1(282)/75 dt. 22-10-1975, discussions were held with the parties and the case ultimately ended in failure. Even after the submission of failure report by the A.L.C.(C), the matter was continued to be discussed between the union and management so as to save the concerned workmen from harassment. While the discussions were going on, the dispute has been referred to Tribunal cum Labour Court Dhanbad-II for adjudication vide ministry's order No. (L-20012/8/76/DIIIA) with the following terms of reference :

"Whether the action of the management of Damoda colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited Post Office-Karmatand-Via Mohuda District Giridih in terminating the lien of S/Shri Dhanraj Mahato and Rameshwar Mahato Miners on their permanent appointment and placing them on the Badli list with effect from 16th July, 1975 is justified? If not, to what relief are the two workmen entitled."

Sri K. L. Ray, Branch Secretary, RCMS, having discussed the case with the Area Manager (Personnel) on several dates, an amicable settlement has been arrived at on the following terms of settlement.

TERMS OF SETTLEMENT

(1) That both the concerned workmen namely S/Sri Dhanraj Mahato and Rameshwar Mahato, Miners of Damoda colliery, shall be re-instated in their jobs with immediate effect but not later than 15th June, '76.

(2) That both S/Sri Dhanraj Mahato & Rameshwar Mahato shall be deemed be suspended for a period of 10 days with effect from 16-7-75 and with the re-instatement as per item No. 1 hereinabove, they will be treated as on leave without pay after the period of suspension to the date of the actual reinstatement, for the purposes of continuity of service only.

(3) That dispute having been settled amicably it is agreed further that a joint compromise petition with 5 signed copies of this settlement shall be filed before the Presiding Officer Central Industrial Tribunal cum Labour Court Dhanbad-II, for treating the case as closed in view of this settlement.

(4) That the Union assures on behalf of the workmen that the concerned workmen will not absent from duty unauthorisedly in future nor they will extend their leave without justified reason and prior intimation/permission.

(5) That this settlement shall not be cited as precedent.

(6) That copies of this settlement shall be sent to the authorities concerned under Rule 58(4) of the I.D.(C) Rules 1957.

Representing Employers :

1. K. C. NANDKEOLYAR,
   Area Manager (Personnel),
   Area No. I., BCCL.
2. P. K. ROY,
   Personnel Officer,
   Area No. I., BCCL.

Representing Workmen :

1. K. L. RAY,
   Branch Secretary, RCMS,
   Damoda Colliery Branch.

Witness :—

(1) ——————————

(2) ——————————

Dated, Barora, 8th June, 1976.

Copy for information, record & necessary action to :

(1) The Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad-II.
(2) The Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad.
(3) The Chief Labour Commissioner (C), Shram Shakti, New Delhi.
(4) The Ministry of Labour Employment, Government of India, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
(5) Five copies for filing before the Central Industrial Tribunal Cum Labour Court, Dhanbad-II.
(6) The Manager, Damoda Colliery. For information & implementation.
(7) The Personnel Manager (MP), Karmik Bhawan, Sraidhella, DNB.
(8) Sri A. P. Sinha, Dy. Personnel Manager (IR), Karmik Bhawan, Sraidhella Dhanbad. This refers to his discussion with Sri P. K. Roy, P. O. on 7-6-1976.
(9) Case File.
(10) Settlement File.
(11) Branch Secretary, RCMS, Damoda Branch.
(12) General Secretary, RCMS, Rajendra Path Dhanbad.
(13) The Area Manager (F), Area No. I

PARTIES

1. K. C. NANDKEOLYAR,
   Area Manager (P),
   Area No. I, BCCL.
2. P. K. ROY,
   Personnel Officer,
   Area No. I BCCL.

1. K. L. RAY,
Branch Secretary, RCMS.,
Damoda Branch.

K. K. SARKAR, Presiding Officer,
[No. L-20012/8/76/D. IIIA]

S. H. S. IYER, Desk Officer.

New Delhi, the 9th December, 1976

S.O. 4860.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shyamsundarpur Colliery of Eastern Coal Fields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th December, 1976.

116 GI/76—9

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No. 14 of 1976

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shyamsundarpur Colliery of Eastern Coal Fields Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Sri N. Das, Advocate, with Sri B. N. Lala, Asstt. Chief Personnel Officer, Sri P. S. Lall Singha, Sr. Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Sri B. S. Azad.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mines

AWARD

By Order No. L. 19012/3/75/DIII(B) dated 28th February, 1976, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Shyamsundarpur Colliery of Eastern Coal Fields Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads :

> "Whether the action of the management of Sarpi Kajora Pit of Shyamsundarpur Colliery of Eastern Coal fields Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan in suspending Shri Mahadeo Sew Mondal, Pump Khalasi from 1-6-1974 to 12-6-1974 without wages was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The concerned workman Sri Mahadev Sew Mondal was appointed in the Sarpi Kajora Colliery in 1962 as a Pump Khalasi. In addition to his duty as pump khalasi he was also directed to switch on the main switch underground during the shift of his work. It is alleged that for switching on the main switch he was being paid at the rate of Rs. 30 per week while he was an employee in the erstwhile Sarpi Kajora Colliery. But, when the colliery was taken over by the Government with effect from 31-1-1973, the complaint of the workman was that his additional allowance of Rs. 30 per week was stopped. The charge against the workman was that on the night of 31-5-1974 he refused to switch on the main switch Board and thereby the underground of the mine was without light from 6.45 to 8.30 with the result that there was lot of confusion and damage as the workmen could not proceed to work. On the basis of the report a charge was served on the workman on 1-6-1974. He was also suspended from service with effect from that date. On 3-6-1974 the workman filed an explanation to the charge alleging that switching on the light was not part of his duty. The explanation was not accepted by the management. So, on 8-6-1974 the workman was served with a notice that a domestic enquiry shall be conducted against him. However, he was alleged to have resumed his normal duties with effect from 13-6-1974. In due course there was a domestic enquiry against him. After the enquiry the officer who conducted the enquiry held the workman guilty of the charge that he refused to switch on the main switch. The finding of the enquiry officer was accepted by the management and the concerned authority passed an order on 2-7-1974 suspending the workman for 10 days. However, the period of suspension pending enquiry was confined from 1-6-1974 to 12-6-1974. The case of the workman is that the suspension was illegal and that he should be paid his full salary from 1-6-1974 to 12-6-1974.

3. On behalf of the union which espoused the cause of the workman, the workman himself was examined as WW-1. Neither in the written statement nor in evidence anything had been stated to show that the enquiry conducted against the workman was illegal or invalid. The only case set up in the written statement was with regard to the non-receipt of a letter by the Enquiry Officer. That letter is now marked as Ext. W-1 dated 3-5-1974. This letter was addressed

to Sub-Area Manager. But, there is nothing to show that during the enquiry this letter was produced or that the workman wanted to get it admitted in evidence. The entire enquiry proceeding is before the Tribunal. On a persual of the proceeding it does not appear that the workman produced this letter during the enquiry for consideration. It would also appear that Ext. W-1 is not a material piece of evidence in appreciating the case of the workman. So, in the absence of any definite pleading much less evidence it cannot be said that the workman had any complaint against the domestic enquiry. In the absence of any allegation made against the domestic enquiry, the only question that has to be decided at this stage is whether the suspension order is invalid inasmuch as the workman is entitled to get the proportionate salary from 1-6-1974 to 12-6-1974.

4. In the written statement of the workman the prayer is only to give a direction to the management to pay the full salary of the workman for the illegal suspension period from 1-6-1974 to 12-6-1974. He did not make a prayer that the enquiry is invalid and that it should be set aside. So, we have to consider whether the suspension order is invalid for any of the reasons alleged by the workman. He has no case that the suspension was an act of victimisation or that it was made as a result of mala-fide conduct on the part of the management. It can not also be said that the punishment order is in any way disproportionate to the misconduct alleged against the workman. The workman appears to have put forward two inconsistent cases. First of all he stated that he had been attending on switch board in addition to his normal duty of pump khalasi. At the next moment he would say that he was not attending to the work in relation to the switch board. The explanation which the workman gave in answer to the charge on 3-6-1974 shows that the operation of the main switch was not a part of his duty as he had already informed the management that he was not bound to do that work. He also stated that his work was that of a pump khalasi. But, Ext. W-1 shows that he was attending to switch board in addition to his normal work of pump khalasi. In his evidence he stated, "I refused to switch on and when I was asked by the Manager I said that as I was not getting the allowance for the same, I would not switch on". He had admitted that for more than 6 to 7 months before the nationalisation he was putting on the main switch underground. So, his attendence on the switch board had been a part of his duty. The question whether he should be paid allowance or not is not a material circumstances for consideration in this case. If his attendance on the switch board was a part of his duty, he should not have refused to switch on the main switch on 31-5-1974 causing inconvenience and loss to the management. The charge against the workman having been proved it has to be said that the punishment of 10 days' suspension was correct. The relevant provision in paragraph 17 of the Standing Order provides that a workman may be suspended or fined subject to the provisions of payment of Wages Act, 1936 or his increment may be stopped or he may be dismissed without notice if he is found to be guilty of misconduct provided that suspension without pay as punishment shall not exceed 10 days. So, the workman cannot dispute the order of punishment passed in the case. The punishment is neither invalid nor disproportionate to the misconduct alleged against him.

5. The management, however, did not pay two days' salary to which the workman is entitled. On the basis of the punishment of suspension for 10 days the workman's suspension will lapse with effect from 11-6-1974 and the workman will be entitled to get full salary for two days i.e. for 11th and 12th June, 1974. The contention that he would be given only his subsistence allowance for these two days as the management chose to punish him with 10 days' suspension without pay cannot be accepted. So, the workman will be entitled to get proportionate full salary for 11th and 12th of June, 1974.

6. In the result, an Award is passed to the effect that the workman Sri Mahadeo Sew Mondal, Pump Khalasi, shall be paid full proportionate salary for 11th and 12th June, 1974 upholding the order of suspension which is effective from 1-6-1974 to 10-6-1974 and in other respects the reference is rejected.

Dated, Calcutta,
The 1st December, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-19012/3/75-D.III(B)]
V. VELAYUDHAN, Under Secy.

नई दिल्ली 6 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4861.—केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप खण्ड (6) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2197 तारीख 11 जून, 1976 द्वारा सिक्यूरिटी पेपर मिल होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 दिसम्बर, 1976 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं. एस.-11017/11/76-डी 1 (ए)]

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 4861.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2197 dated the 11th June, 1976, the Security Paper Mill, Hoshangabad, to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 1976.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 18th December, 1976.

[No. S. 11017/11/76/D.I(A)]

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4862.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2196 तारीख 11 जुलाई, 1976 द्वारा बैंकिंग उद्योग को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर, 1976 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस-11017/7/76-डी. 1(ए)]

New Delhi, the 7th December, 1976

S.O. 4862.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of

India in the Ministry of Labour No. S.O. 2196 dated the 11th July, 1976, the Banking Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th June, 1976.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 29th December, 1976.

[No. S. 11017/7/76/D.I(A)]

का. आ. 4863.—केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2198 तारीख 14 जून, 1976 द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन दिल्ली दुग्ध प्रदाय के उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 जून, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 दिसम्बर, 1976 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं. एस-11017/10/76-डी. 1(ए)]

एल. के. नारायणन, डैस्क अधिकारी

S.O. 4863.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2198 dated the 14th June, 1976, the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 22nd June, 1976.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 22nd December, 1976.

[No. S. 11017/10/76/D.I(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1976

का०आ० 4864.—केन्द्रीय सरकार, लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 3 के साथ पठित लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3550 तारीख 24 अक्तूबर, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए सलाहकार समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:—

1. श्रम मंत्री, आंध्र प्रदेश राज्य हैदराबाद	अध्यक्ष
2. श्रम आयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य	उपाध्यक्ष
3. श्री किशन राव, एम० एल० ए० जिला—आदीलाबाद	सदस्य विधान सभा
4. श्री ए० श्रीनिवास मूर्ति प्रबंधक मैसर्स बेलारी आयरन ओर प्राइवेट लिमिटेड पार्वतीनगर, बेलारी श्री टी०वी० सिवैया, खान स्वामी डाकघर वेदुरुती, धोन तालुक जिला—कुर्नूल	आंध्र प्रदेश के लोह अयस्क खानों के स्वामियों के प्रतिनिधि
6. श्री हनुमन्तप्पा इन्टक नाण्डयाल जिला कुर्नूल 7. श्री एम० कुमारैया, महासचिव सिंगरेनी, कोईलारी, कर्मकार संघ, कोथागुदम	आंध्र प्रदेश के लोह अयस्क खानों के कर्मकारों के प्रतिनिधि
8. श्रीमती बोद्धु कलावती, एम० एल०ए० विजियानगरम	महिला प्रतिनिधि
9. सहायक कल्याण प्रशासक, आई०ओ० एम०एल०डब्ल्यू० फण्ड आंध्र प्रदेश	सचिव

2. केन्द्रीय सरकार लोह अयस्क श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 18 के अनुसरण में हैदराबाद को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है ।

[फा० सं० यू-19012/3/75-एम० 4/डब्लू ए० (एम)]

पी० के० सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 1976

S. O. 4864—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Iron Ore mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) read with rule 3 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No S.O. 3550 dated the 24th October, 1972, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh with the following as members, namely:—

1. Labour Minister, State of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Chairman
2. Commissioner of Labour, State of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Vice-Chairman
3. Sri Kishan Rao, M.L.A. Adilabad District.	Member of the Legislative Assembly
4. Shri A. Srinivas Murthy, Manager, M/s. Bellary Iron Ores Pvt. Ltd., Parvatinagar, Bellary. 5. Sri T.V. Sivaiah, Mine Owner, P.O. Vedurty, Dhone Tq. Kurnool Distt.	Representatives of the Iron Ore Mines Owners of Andhra Pradesh.
6. Sri Hanumantappa, INTUC, Nandyal, Kurnool Distt. 7. Shri M. Komaraiah, Gen. Sec., Singareni Collieries Workers, Union, Kothagudem.	Representatives of the Iron Ore Mines Works of Andhra Pradesh.
8. Smt. Boddu Kalavathi, M.L.A., Vizianagaram.	Women Representative.
9. The Assistant Welfare Administrator, I.O.M.L.W. Fund, Andhra Pradesh.	Secretary.

2. In pursuance of rule 18 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government hereby fixes Hyderabad to be the headquarters of the said Advisory Committee.

[F. No. U. 19012/3/75 M.IV/WA(M)]

P. K. SEN Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1976

स्टाम्प

का. आ. 4865.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1399 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम द्वारा वर्ष 1976 के अक्तूबर मास में वचन-पत्रों के रूप में जारी किये गये एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये मूल्य के 6-1/4 प्रतिशत उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम बंध-पत्र, 1986 पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं. 65/76-स्टाम्प/फा. सं. 471/95/76-सी.शु.-7]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 15th December, 1976

STAMPS

S.O. 4865.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the 6-1/4 per cent Orissa State Financial Corporation Bonds, 1986 issued in the form of promissory notes in the month of October, 1976 to the value of one crore and sixtyfive lakhs rupees, by the Orissa State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 65/76-Stamps/F. No. 471/95/76-Cus. VII]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 4866.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम, बम्बई को, उक्त निगम द्वारा जारी किये जाने वाले एक करोड़ दस लाख रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य बयासी हजार पांच सौ रुपये समेकित स्टाम्प शुल्क संदत्त करने की अनुज्ञा देती है ।

[सं 66/76-स्टाम्प/फा. सं. 471/96/76-सी.शु.-7]

ORDER

STAMPS

S.O. 4866.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay, to pay consolidated stamp duty of eightytwo thousands, and five hundred rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the fact value of one crore and ten lakhs rupees to be isseud by the said Corporation.

[No. 66/76-Stamps/F. No. 471/96/76-Cus. VII]

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1976

स्टाम्प

का. आ. 4867.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दिनांक 23 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) के पृष्ठ 3698 पर प्रकाशित, भारत सरकार (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना सं. 58/76-स्टाम्प/फा. सं. 471/24/76-सी.शु.-7 (का. आ. सं. 3693) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में कालम (3) के अन्तर्गत क्रम सं. 1, 3, 6, 7, 13, 15 तथा 16 के सामने दिये गये अंकों "193", "419", "27.40", "28.60", "59.50", "47.90" तथा "27.30" के स्थान पर क्रमशः "181", "390", "25.50", "28.40", "59.40" "47.40" तथा "27.00" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं. 67/76-स्टाम्प/फा. सं. 471/24/76-सी.शु.-7]

एस. डी. रामस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 17th December, 1976

STAMPS

S.O. 4867.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 58/76-Stamps/F. No. 471/24/76-Cus. VII (S.O. No. 3693), dated the 13th October, 1976, published at page 3698 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd October, 1976, namely :—

In the Table below the said notification, for the figures "193", "419", "27.40", "28.60", "59.50", 47.90" and "27.30" under column (3) shown against S. Nos. 1, 3, 6, 7, 13, 15 and 16, the figures "181", "390", "25.50", "28.40", "59.40", "47.40" and 27.00" shall respectively be substituted.

[No. 67/76-Stamps/F. No. 471/24/76-Cus. VII]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th December, 1976

S.O. 4868.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Grindlays Bank Limited, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th December, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 52 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the Grindlays Bank Limited, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri M. S. Bala, Labour Adviser.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

AWARD

By Order No. L. 12011/15/75/DII/A dated 26th July, 1975, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The Reference reads :

"Whether the following 13 Drivers employed by the Management of Grindlays Bank Limited, Calcutta

are entitled to the same wages, allowances and other facilities enjoyed by the other drivers of the said Bank? If so, from what date and to what extent ?

1. Maksood Ahmed.
2. Md. Yakub
3. Kari Mullah Khan
4. Md. Suleman
5. Lowrance.
6. Shankar Lal Shah
7. Md. Ansar
8. Md. Nizamuddin
9. Joseph Francis
10. Chandeshwar Kumar
11. Ali Mohammad
12. S. M. Rahman
13. Kayat Mohammad."

2. Both sides filed written statements raising several contentions.

3. When the Reference came up to-day for final hearing an adjournment was asked for by an Advocate. He had neither any file with him nor had any workman present before the Tribunal. The representatives of the union which espoused the cause of the workmen were also absent. The advocate concerned however filed an application for adjournment. There were two similar adjournments given to the union to get ready with the case; the first adjournment was given on payment of cost. On that day the union Secretary had bolted away with the records of the case. The advocate appeared without any file or records. There was no workman present at the time; yet the adjournment was given on condition that the union would get ready on the next hearing date. So, the case was posted to 20th October, 1976. On that day also the union wanted an adjournment. The adjournment was granted on condition that the union would produce all the documents one week before the date of hearing. The documents had not yet been produced as directed. No other steps had also been taken. The adjournment was prayed for on the basis of a telegram dated 2-12-76 which stated that the father of the sender of the telegram had died. The authenticity of this telegram is in dispute. No one had come forward to swear that this telegram had been sent by any representative of the union. Any way, the direction of this Tribunal to produce documents one week before the hearing had not been complied with. The Advocate once again appears without any file. He admitted before the Tribunal that neither the union representative nor the workmen concerned had approached him. Under these circumstances, it is not worth-while to give an adjournment a third-time. The workmen as well as the union are declared absent ex-parte.

4. The Manager of the employer Bank was examined as a witness. He proved that the workmen concerned in the case are not employees of the Bank, and that they do not work for the bank. And as such they are not entitled to be treated as equal to the other workmen of the Bank. So, the benefits asked for in the circumstances of the case could not be granted to the workmen.

5. In the result, an award is passed negativing the claim of the alleged workmen mentioned in the reference for equal treatment with other employees of the Bank in respect of wages, allowances and other facilities which are being enjoyed by such employees.

Dated, Calcutta, E. K. MOIDU, Presiding Officer

The 9th December, 1976. [F. No. L-12011/15/75-D. II. A]

R. P. NARULA, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

का. आ. 4869.—यतः कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, दिल्ली की वृहत योजना में लागू होने वाले जोनिंग विनियमनों तथा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11-ए के अंतर्गत वर्द्धित जोन डी-1 (कनाट प्लेस तथा इसका विस्तार क्षेत्र) के जोनल विकास प्लान के जोनिंग विनियमनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण (वृहत योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियमावली 1959 के नियम 6 के अंतर्गत यथा निर्धारित पद्धति के अनुसार 9 दिसम्बर, 1975 के नोटिस सं. एफ 3(256) एम पी (भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-2, खंड-3 के उपखंड (2) के सा. का. 698(ई) तथा सा. का. 699(ई) द्वारा प्रकाशित करके नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि के अन्दर आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किए थे जैसा की उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (3) में अपेक्षित है । और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त जोनिंग नियमों के बारे में आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की वृहत योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने के निर्णय किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से वृहत योजना (जोनिंग विनियमनों) तथा दिल्ली के क्षेत्रीय विकास प्लान के वर्द्धित जोन डी-1 (कनाट प्लेस तथा विस्तार क्षेत्र) में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन

1. वृहत योजना में संशोधन (जोनिंग विनियमन)

दिल्ली की वृहत योजना के पृष्ठ 60 पर

(1) पैराग्राफ 4 "वाणिज्यिक तथा खुदरा" उप-पैरा (क) "कनाट प्लेस एक्सटेन्शन, मिन्टो रोड, रणजीत सिंह रोड" के शब्दों के स्थान पर —

(2) "कनाट प्लेस तथा इसके विस्तार क्षेत्र के लिए भूतल तथा प्रथम मंजिल के लिए 50 प्रतिशत और उपरी मंजिल के लिए 35 प्रतिशत अधिकतम अनुमेय निर्मित क्षेत्र को घटा कर क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत [अधिसूचना सं. 12014/9/72-यूडी-1 दिनांक 27-4-1974 भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड-3 के उप खंड (2) के सा. का. 270 (ई)]" के स्थान पर निम्नलिखित होगा अर्थात् :—

(3) "सभी मंजिलों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र 25 प्रतिशत होगा सिवाए होटलों के जहां भूतल तथा प्रथम मंजिल के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र अनुमेय होगा" ।

2. दिल्ली की वृहत योजना के पृष्ठ 61 पर

"5 होलसेलिंग" शीर्षक के ऊपर निम्नलिखित टिप्पणी रखी जाए, नामत :—

"टिप्पणी :—

(1) वाणिज्यिक विकास के लिए जिसमें कार्यालय शामिल है दिल्ली के सभी क्षेत्रों में सभी मंजिलों के लिए अधिक से अधिक भूमि जिस पर निर्माण किया जा सकेगा 25 प्रतिशत होगी सिवाए होटलों के मामले में जिन्हें निचली मंजिल व प्रथम मंजिल पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण करने की अनुमति होगी ।

(2) वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए वाहन ठहरने के मानक इस प्रकार होंगे :—

गतिविधि	कार स्थान के बराबर कुल स्थान
(क) व्यापार	भवन/तहखाने के कार्टीलेज के भीतर निर्मित स्थान के प्रत्येक 92.9 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) में 1.14 कारों का स्थान और भवन के बाहर और प्लाट के भीतर

निर्मित स्थान के प्रत्येक वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) अतिरिक्त 1.14 कारों का स्थान बशर्ते की भवन के आसपास 50 प्रतिशत खुला स्थान हरित/भूदृश्य के लिए अवश्य छोड़ा जाए।

(ख) कार्यालय, सिनेमा तथा होटल (5 स्टार) :— भवन/तहखाने के कवरेज के भीतर निर्मित स्थान के प्रत्येक 92.9 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) में 1.14 कारों का स्थान और अतिरिक्त पार्किंग जहां आवश्यक हो निर्मित स्थान के प्रत्येक 92.9 वर्गमीटर (1000 वर्ग फुट) 1.14 कारों के स्थान तक सीमित बशर्ते कि भवन के आसपास 50 प्रतिशत खुला स्थान हरित/भूदृश्य के लिए अवश्य छोड़ा जाए"।

दिल्ली की वृहत योजना के पृष्ठ 60-61 पर

"4. वाणिज्यिक और खुरदरा" शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित के आगे दिखाई गई अधिक से अधिक निर्माण की जाने वाली भूमि इस प्रकार होगी :—

(1) उप पैराग्राफ (ग) में 25 एकड़ तक जिला केन्द्र के आगे।

(2) समाज केन्द्रों और खुरदरा केन्द्रों के आगे उप-पैराग्राफ (घ)

(3) नेबरहुड शॉपिंग केन्द्रों के आगे उप-पैराग्राफ (ङ) वृहत योजना के पृष्ठ 61 पर नोट (1) में दिए अनुसार निर्मित क्षेत्र सीमित होगा जैसा कि उपर्युक्त मद (2) में संशोधित किया गया है।

(4) दिल्ली की वृहत योजना के पृष्ठ 63 पर "8 संस्थानिक प्रयोग" शीर्ष के अन्तर्गत फुट नोट इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—

"प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के गुण अवगुण के अनुसार एफ ए आर निर्धारित की जाएगी जो कि प्रयोग की स्थिति और प्रकार पर निर्भर करेगी। तथापि यह पुनः 24.4 मीटर (80 फुट) की उंचाई तक सीमित होगी जहां लिफ्टें और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हैं और जहां ये सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं वहां उंचाई 13.72 मीटर (45 फुट) तक सीमित होगी।"

(5) दिल्ली वृहत योजना के पृष्ठ 59 पर कुल रिहायशी घनत्व अधिकतम निर्मित क्षेत्र तथा एफ ए आर विहित करने वाली तालिका के नीचे टिप्पणी 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"5-क दिल्ली में ग्रुप आवास आधार पर रिहायशी विकास हेतु सभी क्षेत्रों के लिए एफ. ए. आर. पर विभिन्न उंचाईयों के निम्नलिखित और प्रतिबन्ध होंगे :

(1) उन सरकारी प्वायंट ब्लाक भवनों के सम्बन्ध में जहां भवनों में उपरि जलाशय (टैंक्स) लिफ्टें तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध की जानी हैं अधिकतम 36.58 मीटर (120 फुट),

(2) जहां लिफ्टें तथा अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध की जानी हैं वहां अधिकतम 24.4 मीटर (80 फुट): तथा

(3) यदि ऐसी सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो 13.72 मीटर (45 फुट)।

6. दिल्ली वृहत योजना के पृष्ठ 54 बायें ओर के कालम के नीचे (बाटम पर) शीर्ष "5 यूज जोन्स में, आवश्यकताएं, घनत्व अधिकतम निर्मित क्षेत्र फर्शी क्षेत्रफल अनुपात, सेट बैक तथा यूज जोन की अपेक्षितताओं के सम्बन्ध में व्यवस्था" के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी (फुट नोट) जोड़ी जाए :—

"टिप्पणी फुट नोट : वाणिज्यिक विकास के लिए 13.72 मीटर (45 फुट) की उंचाई से अधिक सभी उंचे/बहुमंजले नों में बिजली के लिए स्टैन्ड-बाई जनरेटर्ज होंगे।

(2) क्षेत्रीय विकास योजना (वर्द्धित क्षेत्र डी-1 कनाट प्लेस एक्सटेंशन) जिसमें विकास नियन्त्रण शामिल हैं, में संशोधन :

(1) उंचाई प्रतिबन्ध : 5

क्षेत्रीय विकास योजना (वर्द्धित क्षेत्र डी-1 कनाट प्लेस तथा इसकी एक्सटेंशन—दिल्ली का महानगर शहर केन्द्र) के पाठ (टैक्सट) में 8 तथा पृष्ठ 9 पर वर्तमान पैराग्राफ 7-8 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ स्थापित किए जाएंगे, नामतः

"7-8 दिल्ली के महानगर केन्द्र के लिए वाणिज्यिक/कार्यालय भवनों के लिए उंचाई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। तथापि उंचाई लागू एफ. ए. आर. तथा वास्तविक नियंत्रण जो दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा विहित किए गए हैं द्वारा शासित होगी"।

(2) पार्किंग के मानदण्ड :

क्षेत्रीय विकास योजना (वर्द्धित क्षेत्र डी-1 कनाट प्लेस तथा इसकी एक्सटेंन्शन-दिल्ली का महानगर केन्द्र) के पाठ में पृष्ठ 11 पर तालिका जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए पार्किंग के मानदण्ड की व्यवस्था हैं को छोड़ दिया जाएगा तथा दिल्ली की वृहत योजना [उपर्युक्त संशोधन सं. 1(2)] के पृष्ठ 61 पर टिप्पणी (2) में उल्लिखित पार्किंग के मानदण्ड लागू होंगे।

[सं. के.-12014(19)/72-यू. डी. आई.]

के. बिस्वास, निदेशक

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 24th December, 1976

S.O. 4869.—Whereas certain modifications which the Central Government proposes to make to the zoning regulations, applicable to the Master Plan for Delhi and the Zoning Regulations of Zonal Development Plan for enlarged Zone D-1 (Connaught Place and its extension), under Section 11-A of the Delhi Development Act, 1957, mentioned in the manner as prescribed under rule 6 of the Delhi Development Authority (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959 vide notices No. F. 3(256)/72-M.P. dated 9th December, 1975 [S.O. 698(E) and S.O. 699(E) Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (ii)] for inviting objections and suggestions within a period of 30 days from the date of notices as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act.

And whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions with regard to the said zoning regulations, have decided to modify the Master Plan and the Zonal Development Plan for Delhi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications to the Master Plan (Zoning Regulations) and the Zonal Development Plan for enlarged Zone D-1 (Connaught Place and its extension) for Delhi, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATIONS :

I. Modifications in the Master Plan (Zoning Regulations) :

(1) In paragraph IV 'Commercial and Retail', sub-para (a) 'Connaught Place Extension, Minto Road, Ranjit Singh Road', occurring on page 60 of the Master Plan for Delhi for the words—

"(ii) Maximum permissible coverage of 50 per cent on the ground and first floors and 35 per cent on the upper floors has been reduced to 25 per cent and 30 per cent respectively for Connaught Place and its Extension [Notification No. K-12014/9/72-UDI dated 27th April 1974—S.O. 270(E) Gazette of

India Part II, Section 3, Sub-Section (ii),"—the following words shall be substituted, namely :—

"(ii) Maximum floor coverage for all the floors shall be 25 per cent except in the case of hotels where for ground and first floors, an additional coverage of 5 per cent will be permissible".

(2) On page 61 of the Master Plan for Delhi, above the heading "V. Wholesaling", the following notes shall be inserted, namely—

"Notes :

(1) For commercial development, including offices, in all areas of Delhi, the maximum ground coverage shall be 25 per cent for all floors except that in the case of hotels and additional coverage of 5 per cent will be permissible on ground and first floors only.

(2) Parking standards for various types of commercial activities shall be as below :—

Type of activity	Total equivalent car space
(a) Trade	1.14 car spaces per 92.9 sq. mts. (1000 sq. ft.) of built up space within the curtilage of the building/basement, and an additional 1.14 car spaces per 92.9 sq. mts. (1000 sq. ft) of built up space within the plot outside the building, subject to the condition that 50 per cent of the open space around the building should in any case be left for greenary/landscaping.
(b) Offices, Cinamas & Hotels (5-Star)	1.14 car space per 92.9 sq. mts. (1000 sq. ft) of built up space within the curtilage of the building/basement, and an additional parking, where required, limited to the extent of 1.14 car spaces per 92.9 sq. mts. (1000 sq. ft.) of the built up space, subject to the condition that 50 per cent of the open space around the building should in any case be left for greenary/landscaping."

(3) On pages 60 and 61 of the Master Plan for Delhi, under the heading "IV. Commercial and Retail", the maximum coverages on the ground floor shown against—

(i) sub-paragraph (c) against District Centres upto 25 acres,

(ii) sub-paragraph (d) against Community Centres and Retail Centres, and

(iii) sub-paragraph (e) against Neighbourhood Shopping Centres,

shall be limited by the coverage as indicated in Note (1) on page 61 of the Master Plan as amended under item (2) above.

(4) On page 63 of the Master Plan for Delhi, the foot-note, under heading "VIII. Institutional Use", shall be read as below :

"F.A.R. will be determined on the merit of each individual case depending upon the location and the nature of use. However, this will be further subject to a height restriction of 24.4 metres (80 feet) where lifts and other necessary services are provided and 13.72 metres (45 feet) if such services are not adequately provided."

(5) On page 59 of the Master Plan for Delhi, below the table prescribing Gross Residential Density, maximum coverage and maximum F.A.R., after Note (5) the following Note shall be inserted, namely—

"5A. For all areas in Delhi for residential development on group housing basis, the F.A.R. will be further subject to the restrictions of various heights, as below :—

(i) a maximum of 36.58 metres (120 feet) in respect of Government point block buildings where overhead water reservoirs (tanks) as well as lifts and other services are to be provided in the buildings ;

(ii) a maximum of 24.4 metres (80 feet) where lifts and other necessary services are provided, and

(iii) a maximum of 13.72 metres (45 feet) if such services are not adequately provided.

(6) At the bottom of the left hand column on page 54 of the Master Plan for Delhi under the heading "5. Provision regarding requirements in use zones, density, coverage, Floor Area Ratio, Setback and other requirements of use zones", the following foot-note shall be added :—

"Foot-note : All tall/multistoreyed buildings for commercial development over 13.72 metres (45 feet) in height, shall have standby generators for electricity within the buildings."

II. Modifications in the Zonal Development Plan (enlarged Zone D-1—Connaught Place and its Extension) including development control :

(1) Height Restrictions.—On pages 8 and 9 in the text of the Zonal Development Plan (enlarged Zone D-1—Connaught Place and its Extension—Metropolitan City Centre of Delhi) for the existing paragraph 7-8 the following paragraph shall be substituted namely :—

"7-8. For the Metropolitan City Centre of Delhi, there is no height restriction for commercial/office buildings. However, the height shall be governed by the F.A.R. applicable and the architectural control, prescribed by the Delhi Urban Art Commission."

(2) Parking Standards.—On page 11 in the text of the Zonal Development Plan (Enlarged Zone D-1—Connaught Place and its Extension—Metropolitan City Centre of Delhi), the table stipulating the parking standards, for various type of activities, shall be omitted and the parking standards mentioned in note (2) on page 61 of the Master Plan for Delhi [Modification No. I(2) above] shall apply.

[No. K-12014(9)/72-UDI]

K. BISWAS, Director

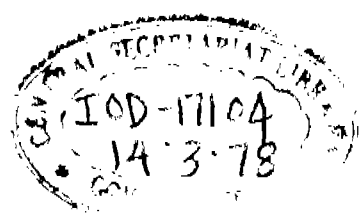

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.